



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256486
CG-DL-E-20082024-256486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 209]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं - एडी (ओआई) - 14/2023

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एपिक्लोरोहाइड्रिन” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/15/2023-डीजीटीआर.— क. मामले की पृष्ठभूमि

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए: एपिग्रल लिमिटेड (जिसे पूर्व में मेघमनि फाइनकेम लिमिटेड रूप में जाना जाता था) (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग कहा गया है) में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, ताईवान और थाईलैंड से एपिक्लोरोहाइड्रिन (जिसे आगे

विचारधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु या ईसीएच भी कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. संख्या 6/15/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 सितंबर, 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तथापि, ताईवान से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी ने ताईवान से आयातों की जांच की शुरुआत करना उचित नहीं समझा।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 26 सितंबर 2023 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने दिनांक 26 सितंबर 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति पाटनरोधी नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों को भेजी थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
- ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को सूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे जांच शुरुआत अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने नियमावली के 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी:

- i. डोंगयिंग रिच केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. फार्मासिनो फार्मास्यूटिकल्स (जिआंगसू) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. इन्फोर्क इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iv. नानजिंग बेइनुओ फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- v. सिकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

- vi. जिबो फेयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - vii. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड, एडवांस्ड मैटेरियल्स, थाईलैंड
 - viii. एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ix. सैमसंग फाइन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
- च. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:
- i. जियांगसू रईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड ("रईजियांग"), चीन जन. गण.
 - ii. निंगबो हुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ("हुआनयांग"), चीन जन. गण.
 - iii. कैनको मार्केटिंग, इंक. कोरिया गणराज्य
 - iv. एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
 - v. हनवा कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - vi. हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - vii. लोटे फाइन केमिकल, कोरिया गणराज्य
 - viii. मिंजिन कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ix. एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - x. सैमसंग सीएंडटी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- छ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी:
- i. अतुल लिमिटेड
 - ii. कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी
 - iii. एंडोक लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. मेसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड सिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - v. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेसर्स कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी
 - vi. हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड
 - vii. आईपीसीए लैब्स
 - viii. कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट
 - ix. पारीचेम रिसोर्सेज एलएलपी

- x. प्रफुल वेंचर
 - xi. रेजिन और प्लास्टिक
 - xii. ऋषभ मेटल
 - xiii. सिंथोकेम लैब्स
 - xiv. यूनिड्रग्स लिमिटेड
- झ. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. अतुल लिमिटेड
 - ii. कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी
 - iii. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड
- ञ. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पक्षकारों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया या जांच की प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए:
- i. ट्रेड, लीगल अफेयर्स एंड प्लोनिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी, कोरिया सरकार
 - ii. ट्रेड इंटरेस्ट एंड रेमिडीज डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरिन ट्रेड, थाईलैंड सरकार
 - iii. चीन क्लोर-अल्काली इंडस्ट्री एसोसिएशन, चीन जन. गण.
 - iv. ऋषभ मेटल्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - v. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ट. जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन का अगोपनीय अंश 5 अक्टूबर, 2023 को निम्नलिखित एसोसिएशनों को भेजा गया था:
- i. एफआईआईओ
 - ii. एफआईसीओ
 - iii. एसएसओसीएचएएम
 - iv. सीआईआई
- ठ. जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन का अगोपनीय अंश तथा आर्थिक हित प्रश्नावली की एक प्रति 5 अक्टूबर, 2023 को निम्नलिखित मंत्रालय को भेजी गई थी। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।
- i. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- ड. उक्त के अलावा, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड जो संबद्ध वस्तु का आगामी उत्पादक है और जो अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आवेदन के समर्थन में एक पत्र प्रस्तुत किया।

- ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।
- ण. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए और जांच अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- त. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की है। क्षति अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की अवधि शामिल होगी। इसके अलावा, चूंकि यह आवेदक केवल जांच अवधि के दौरान प्रचालनरत रहा था। इसलिए आंकड़ों को (क) जांच अवधि को तिमाही में विभाजित करके; (ख) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार और (ग) 80 प्रतिशत क्षमता पर विचार करते हुए विश्लेषित किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन अनिवार्य सभी तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को 12 जुलाई 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। पूर्ववर्ती अनुरोध को केवल पुनः प्रस्तुत करने वाले किसी अनुरोध और जिसकी प्राधिकारी ने पर्याप्त रूप से जांच की थी, को संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है।
- ध. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर साक्ष्य द्वारा उनके समर्थकों ने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।
- न. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- प. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- फ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 फरवरी 2024 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और बाद में खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।
- ब. हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने

ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार / अवलोकन दर्ज किए हैं।

- म. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्पित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है।
- य. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- कक. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.06 रुपए है।
- खख. इस दस्तावेज में निम्नलिखित शब्द-संक्षेप का प्रयोग किया गया है:
- i. ईसीएच = एपिक्लोरोहाइड्रिन
 - ii. एनआईपी = क्षतिरहित कीमत
 - iii. पीओआई = जांच की अवधि
 - iv. पीयूसी = विचाराधीन उत्पाद

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरूआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एपीक्लोरोहाइड्रिन, संक्षिप्त रूप में ईसीएच है। इस उत्पाद, जिसे सीमा शुल्क वर्गीकरण में भी प्रयुक्त किया गया है, का रासायनिक नाम 1-क्लोरो-2,3-एक्पोक्सीप्रोपेन है। इसका रसायन फार्मूला C3H5ClO है।

4. यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादित किया जाता है। यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादित किया जाता है। इसका अधिकांशतः एपोक्सीरेजिन बनाने में प्रयोग होता है जो इसकी खपत का लगभग 80 प्रतिशत बनता है। इसे भेषज एपीआई, जल उपचार, कागज रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फैक्टेंट, अधेसिव, इलेस्टोमर्स, प्लास्टिक तथा रबड़ और कागज में मजबूतीवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद को प्रोपलीन तथा ग्लेसरीन प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को पारंपरिक रूप से प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है जहां एलाइन क्लोराइड के उत्पादन हेतु उच्च तापमान पर प्रोपीलीन का क्लोरीनेशन होता है। एलाइल क्लोराइड पृथक् होने और एलाइल क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरीनेशन के बाद भी डीक्लोरोहाइडाइन उत्पादित होता है और एलीक्लोराइड प्राप्त होता है। डीक्लोरोहाइडाइन ईसीएच के उत्पादन हेतु साबुनीकरण से गुजरती है जिसे बाद में शुद्धीकृत किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद प्रक्रिया से अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इस प्रकार निपटान हेतु उच्च पूंजीगत व्यय अपेक्षित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ईसीएच को जैव आधारित ग्लाइसीरीन के प्रयोग से उत्पादित किया जा रहा है जो एक पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया है।

6. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के शीर्ष 2910 के उपशीर्ष 2910 30 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि संबद्ध आयातों के विश्लेषण प्रमाण पत्र की घरेलू उद्योग के प्रमाण पत्र से तुलना की जानी चाहिए। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध

भी किए हैं:

- क. इपोक्सी उद्योग में प्रयोग के लिए बेचे गए ईसीएच को बल्क में और आईएसओ टंकियों में बेचा जाता है जबकि एपीआई में प्रयोग के लिए भेजे गए ईसीएच को कमतर मात्राओं और ड्रम पैकिंग में बेचा जाता है जिनकी कीमत अधिक होती है। अतः संबद्ध वस्तु के अंतिम प्रयोग के परिणामस्वरूप कीमत निर्धारण में अंतरों के आधार पर उत्पाद के लिए पीसीएन पर विचार करने की जरूरत है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी विनिर्देशन शीट भी प्रस्तुत की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एपीक्लोरोहाइड्रीन या ईसीएच है। जिसका रासायनिक नाम 1-क्लोरो-2,3-एक्पोक्सीप्रोपेन है। इसका रसायन फार्मूला C_3H_5ClO है। यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादित किया जाता है। इसका प्रयोग भेषज एपीआई, जल उपचार, कागज रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फैक्टेंट, इलेस्टोमर्स, अधेसिव तथा रबड़ में भी किया जाता है इसे कागज में मजबूतीवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
8. ईसीएच को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 29 के शीर्ष 2910 के टैरिफ कोड 2910 30 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ जांच शुरुआत सूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के समान दायरे पर विचार किया है।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दावा कि है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। संबद्ध वस्तु को दो तरीकों से उत्पादित किया जा सकता है – प्रोपलीन के प्रयोग द्वारा या ग्लिसरीन की डिस्टॉक पद्धति के प्रयोग द्वारा। घरेलू उद्योग ने ग्लिसरीन की डिस्टॉक की पद्धति के प्रयोग से ईसीएच का उत्पादन किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्रोपलीन के प्रयोग से उत्पादित संबद्ध वस्तु, यदि कोई हो, में कोई अंतर नहीं है और ग्लिसरीन के प्रयोग से समान वस्तु निर्मित होती है। दोनों तरीकों से उत्पादित ईसीएच में समान तकनीकी और भौतिक विशेषताएं, अनुप्रयोग, कीमत निर्धारण और उपभोक्ता होते हैं। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रोपलीन या ग्लिसरीन पद्धति से उत्पादित संबद्ध वस्तु में किसी अंतर का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन और थाईलैंड में उत्पादकों ने भी ग्लिसरीन के द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
11. कोरिया की सरकार द्वारा पीसीएन पर विचार करने के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि पक्षकार जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर ऐसे तर्क देने में विफल रहा है। इस प्रकार जांच के अंतिम स्तर पर किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह कोरिया गणराज्य सहित किसी भी अन्य प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक ने ऐसे आधारों पर पीसीएन के सृजन का अनुरोध नहीं किया है। इस प्रकार ऐसे किसी तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग की मौजूदगी और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के बारे में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है जिसने जून 2022 में उत्पादन शुरू किया था।
- ख. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी ईसीएच का विनिर्माण करने वाली उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में हैं।
- ग. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”

15. वर्तमान आवेदन एपिग्रल लिमिटेड (जिसे पहले मेघमनि फाइनकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा दायर किया गया था। वर्तमान में एपिग्रल लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। इस प्रकार आवेदक का उत्पादन भारत में ईसीएच से कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है। आवेदक कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है और उसने ऐसी किसी वस्तु का आयात नहीं किया है। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत एपिग्रल लिमिटेड घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

16. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अगोपनीय सारांश प्रदान किए बिना याचिका और लिखित अनुरोधों में गोपनीयता आंकड़ों पर भरोसा किया है जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नुकसान हुआ है।
- ग. आवेदक ने परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट का अगोपनीय अंश नहीं दिया है जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकार उत्तर बनाने के अवसर से वंचित हो गए हैं और इस प्रकार ऐसे अनुमानों से संबंधित कोई अनुरोध निराधार है।
- घ. आवेदक ने प्रपत्र IVक में जांच अवधि के लिए गलत सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं जो प्रत्येक तिमाही के लिए सभी सूचीबद्ध संख्याओं का योग होना चाहिए।
- ड. आवेदक ने उत्पादन प्रक्रिया में अपने फ्लो चार्ट के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

- च. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और कच्ची सामग्री की लागत, निवेश पर आय और शट डाउन के दिनों की संख्या संबंधी रूझान भी नहीं बताए हैं। इसके अलावा, सामान्य मूल्य, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती की गणना के भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- छ. आवेदक की दलीलों के उत्तर में यह अनुरोध किया गया था कि शुल्क के प्रभाव की गणना लागत संरचना और प्रयोक्ता के इनपुट खर्च के आधार पर की गई है जो व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हैं। प्रयोक्ता उद्योग के लिए वास्तविक सूचना देना अपेक्षित नहीं है और उसके लिए संभव सीमा तक केवल तर्कसंगत सारांश देना अपेक्षित है।
- ज. ग्रासिम द्वारा क्षमता विस्तार के संबंध में विस्तृत पहलू और शामिल लागत व्यापार संवेदनशील सूचना है। आवेदक द्वारा शेयर की गई सार्वजनिक सूचना केवल एक सामान्य विवरण है और उसने कुल व्यय और क्षमता खपत के लिए समायोजन पर विचार नहीं किया गया है।
- झ. प्रयोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घावधिक संविदा के ब्यौरे अत्यधिक व्यापार संवेदनशील हैं।
- ञ. वितरण की श्रृंखला और निर्यात कीमत में समायोजन के दावे की पद्धति वाणिज्यिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील सूचना है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के उल्लंघन में पूरे उत्तरों का गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, पक्षकार व्यापार सूचना संख्या 1/2013 के अंतर्गत विहित प्रपत्र के अनुसार कारणों का विवरण देने में विफल रहे हैं।
- ख. एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए समायोजन, वितरण श्रृंखला विनिर्माण प्रक्रिया के लेखन, प्रयुक्त कच्ची सामग्री और बीजक पश्चात छूटों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग. एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने ऐसी सूचना प्रदान की है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जैसे कि संबंधित पक्षकारों से खरीदी गई कच्ची सामग्री और इनपुट के ब्यौरे, कंपनी की स्वामित्व संरचना और स्थापित क्षमताएं।
- घ. प्रयोक्ताओं ने शुल्क के कथित प्रभाव, कथित पाटन या सब्सिडीकरण के घरेलू उद्योग पर प्रभाव, प्रचलित कीमतों, घरेलू उद्योग को क्षति के अन्य कारण, दीर्घावधिक संविदाओं की मौजूदगी आदि के संबंध में पूरी गोपनीयता का दावा किया है।
- ड. ग्रासिम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार और कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी द्वारा बेचे गए उत्पादों की सूची जैसी सूचना जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, के संबंधित प्रयोक्ताओं द्वारा गोपनीय होने का दावा किया है।
- च. हनव्हा कॉर्पोरेशन, हनव्हा सॉल्यूशंस, लोटे फाइनकेम और सैमसंग सीएंडटी ने संबद्ध वस्तु की बिक्री और उत्पादन में शामिल संबंधित पक्षकारों के ब्यौरे नहीं दिए हैं जो व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं का उल्लंघन है। इसके अलावा, ऐसे निर्यातकों ने शेयरधारिता के ढांचे संबंध में गोपनीयता का दावा किया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
- छ. लोटे फाइनकेम और सैमसंग सीएंडटी ने विनिर्माण प्रक्रिया के लेखन, कच्ची सामग्री और बेची गई संबद्ध वस्तु के विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
- ज. लोटे फाइनकेम ने एक उत्पादक के रूप में इस दावे के बावजूद परिशिष्ट 10 के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत नहीं करते हुए अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है कि उसने ईसीएच में प्रयोग के लिए आबद्ध रूप से इनपुट का

उत्पादन किया है।

- झ. निंगबो इंगबो हुआयांग और जियांगसू रूइजियांग ने ईसीएच के उत्पादन और बिक्री में शामिल संबंधित पक्षकारों विनिर्माण प्रक्रिया के लेखों, प्रयुक्त कच्ची सामग्री, बेची गई संबद्ध वस्तु के विवरण, वितरण के चैनल और निर्यात कीमत तुलनीयता के लिए सभी समायोजनों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ञ. निंगबो हुआयांग और जियांगसू रूइजियांग ने असंगत उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उत्तर के विभिन्न भागों में अलग-अलग सूचना दी है।
- ट. अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के उत्तर में यह बताया गया था कि टिप्पणियां समय के बाद दी गई थीं जिन्हें जांच शुरूआत अधिसूचना में अधिसूचित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया था।
- ठ. घरेलू उद्योग ने इस प्रकार से सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं जिससे एक तिमाही की सूचना की तुलना हो सकती है और जांच अवधि के आंकड़े प्रत्येक तिमाही के लिए आंकड़ों को दर्शाने हेतु अनुपातिक रूप से समायोजित किए गए हैं।
- ड. घरेलू उद्योग की परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट अत्यधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत उसका प्रकटन करना अपेक्षित नहीं था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लिए व्यापार सूचना के अंतर्गत कीमत कटौती का प्रकटन करना भी अपेक्षित नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।
19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
20. हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। यह नोट किया गया है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने इन निर्देशों का पालन किया है और उचित प्रकटन किए हैं।
21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आवेदक के इसकी परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के संबंध में किए गए गोपनीयता के दावे

के संबंध में तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन तर्कों को जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट में दी गई सूचना व्यापार संवेदनशील है और उसका प्रकटन उनके हितों के लिए नुकसानदायक होगा। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे को स्वीकार किया है।

22. उत्पादक, एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने दावा किया है कि ऐसी सूचना व्यापार संवेदनशील है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे सौदों का प्रकटन नहीं किया जा सकता है। इस दावे को प्राधिकारी को स्वीकार किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क को पूर्व व्यापी रूप से लागू करने की चीन जन. गण. से सोडियम ट्रिपोली फॉस्फेट के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अनुमति नहीं है।
- ख. चूंकि घरेलू उद्योग ने ऐतिहासिक पाटन सिद्ध नहीं किया है। इसलिए पूर्व व्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने की अपेक्षा पूरी नहीं होती है।
- ग. जांच की वर्तमान अवधि सामान्य बाजार स्थितियों को नहीं दर्शाती है, क्योंकि वह ईसीएच, उसकी कच्ची सामग्रियों और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के भारी वैश्विक कीमत उतार-चढ़ाव द्वारा प्रभावित थी।
- घ. जांच की अवधि सतत अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए जो अन्य बाह्ताओं द्वारा प्रभावित न हो जैसा कि ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग में अपीलीय निकाय ने माना था।
- ड. जांच की अवधि न्यूनतम दो वर्षों की अवधि होनी चाहिए।
- च. घरेलू उद्योग को केवल तभी पाटनरोधी जांच की शुरूआत के आवेदन की अनुमति होनी चाहिए। यदि वे न्यूनतम दो वर्षों से प्रचालन में रहे हों।
- छ. घरेलू उद्योग की बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करना चाहिए।
- ज. जांच को डब्ल्यूटीओ के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- झ. रिफाइंड और कच्चे ग्लिसरीन के प्रयोग, शुल्क और कीमतें अलग-अलग हैं और इसलिए किसी भ्रम से बचने के लिए बिल्कुल सही संदर्भ देना चाहिए।
- ञ. चीन से आयातों पर मूल सीमा शुल्क एआईपीटीए के अंतर्गत 5.775 प्रतिशत है जबकि कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के आयातों पर शुल्क 0 प्रतिशत है। ताईवान से आयातों पर मूल सीमा शुल्क 8.25 प्रतिशत है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के उत्तर घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. इस दलील के उत्तर में कि जांच अवधि उचित नहीं थी उसमें काफी उतार-चढ़ाव हुए थे। यह अनुरोध किया गया था कि रासायनिक उत्पादों की कीमतों में काफी अस्थिरता रही थी और यदि किसी अस्थिरता के बिना वाली अवधि पर विचार करना हो तो रासायनिक उत्पादों के लिए कोई जांच नहीं हो पाएगी।

- ख. ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का निर्णय था कि जांच की अवधि सतत अवधि होनी चाहिए जो इस मामले में 12 महीने है, क्योंकि इससे किसी अस्थिरता पर विचार करते हुए पाटन और क्षति का उचित मूल्यांकन हो पाएगा। अपीलीय निकाय ने यह भी माना है कि जांच अवधि के दौरान या उसके बाद प्रमुख परिवर्तनों की स्थितियां जिनके परिणामस्वरूप पाटन या क्षति समाप्त हो सकते हैं, पर समीक्षा तंत्र के जरिए ध्यान दिया जा सकता है।
- ग. नियम 5 (3क) के अंतर्गत जांच की अवधि सामान्यतः 12 महीने की होगी और अधिकतम 18 महीने की अवधि हो सकती है।
- घ. यह दलील कि घरेलू उद्योग को आवेदन दायर करने से पहले कम से कम दो वर्षों के लिए प्रचालन में होना चाहिए, सही नहीं है, क्योंकि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी की प्रक्रिया और डब्ल्यूटीओ के पैनल के विभिन्न निर्णयों के अनुसार उत्पादन शुरू करने से पहले भी पाटनरोधी जांच की शुरुआत का अनुरोध कर सकता है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि एक जांच में माना गया था, एक मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क के लागू नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि अन्य मामले में शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वव्यापी शुल्कों की जरूरत को मामले के तथ्यों और कानूनी स्थिति के संबंध में देखा जाना चाहिए।
- च. घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी सूचना देगा।
- छ. घरेलू उद्योग ने याचिका में अपनी तकनीकी विनिर्देशन शीट प्रदान की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. इस दावे के संबंध में कि वर्तमान जांच अवधि सामान्य बाजार दशाओं की प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत केवल सूचना के आधार पर ऐसी अवधि के दौरान कीमत में काफी उतार-चढ़ाव हुआ था, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तु तथा कच्ची सामग्री की कीमतों में पहले भी काफी अधिक उतार-चढ़ाव रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कीमत उतार-चढ़ाव जांच अवधि के बाद भी जारी रहे हैं। इसके अलावा, उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव असामान्य नहीं है। तथापि, सामान्यतः उत्पादन लागत के कारकों में उतार-चढ़ाव के उत्तर में कीमत में अस्थिरता होती है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि ईसीएच की कीमतों में इस प्रकार से अस्थिरता हुई थी। वह कच्ची सामग्री कीमत से मेल नहीं खाती है। उतार-चढ़ाव यह नहीं दर्शाते हैं कि वर्तमान जांच की अवधि अनुचित है।
26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा करने के लिए ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है कि जांच की अवधि सतत अवधि होनी चाहिए और ऐसी अवधि किसी अंतर से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तथापि, डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने जांच की कम अवधि पर विचार करने के ब्राजील के तर्क को अस्वीकृत कर दिया था जो उतार-चढ़ाव से अप्रभावित था, बल्कि यह निर्णय दिया गया था कि जांच की अवधि लगातार 12 महीने की होनी चाहिए जो बाजार में किसी अस्थिरता का ध्यान रखती है। अपीलीय निकाय यह बताते हुए आगे बढ़ाती। ऐसी स्थिति जहां कतिपय कारकों में अंतर या उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप पाटन या क्षति समाप्त हो जाती है, वहां हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी करार के अंतर्गत समीक्षा की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
27. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को दो वर्षों की न्यूनतम अवधि में प्रचालन करने के बाद पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि अधिनियम या नियमावली में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई कंपनी प्राधिकारी से उपचार की मांग करने से पहले न्यूनतम दो वर्षों से प्रचालन में हो। इस प्रकार, इस दावे में कोई तथ्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को आवेदन प्रस्तुत करने से कम से कम दो वर्ष पहले प्रचालन करना चाहिए।
28. इस दावे के संबंध में कि जांच अवधि में न्यूनतम दो वर्ष शामिल होने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि

नियमावली के नियम 5(3) के स्पष्टीकरण में यह व्यवस्था है कि जांच की अवधि सामान्यतः 12 महीने की होगी और कारण दर्ज कराने पर यह न्यूनतम 6 महीने या अधिकतम 18 महीने की अवधि हो सकती है। अतः दो वर्षों की अवधि पर किसी स्थिति में जांच अवधि के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।

29. चीन जन. गण. के लिए पहुंच मूल्य के निर्धारण हेतु 5.775 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क पर विचार करने दावे के संबंध में प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान यथा लागू मूल सीमा शुल्क का विचार करते हुए सभी संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य निर्धारित किया है।
30. शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में शुल्क को लागू नहीं करने से वर्तमान या भावी मामलों में शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की सिफारिश करने से प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है। यदि प्राधिकारी शुल्क लागू करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं तो वे शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की सिफारिश की आवश्यकता की जांच भी कर सकते हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि पूर्वव्यापी रूप से शुल्क लागू करने की अनुमति नहीं है क्योंकि पाटन का कोई इतिहास नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क(3) के प्रावधानों में पाटन का इतिहास शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के लिए पूरी की जाने वाली एक अनिवार्य शर्त के रूप में अपेक्षित नहीं है। उपखंड (3) के खंड (i) के अनुसार शुल्क को वहां पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जहां पाटन का इतिहास हो या आयातक अथवा आयातकर्ता को उस बात की जानकारी थी या होनी चाहिए थी कि निर्यातक पाटन कर रहा है और ऐसे पाटन से क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ऐसी कानूनी स्थिति के अनुसार अपने अंतिम निर्धारण तक पहुंचेंगे।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु थाईलैंड में घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयासों को स्पष्ट नहीं किया है।
 - ख. आवेदक ने यह नहीं दर्शाया कि कोरिया गणराज्य और थाईलैंड जैसे आर्थिक दशाओं की दृष्टि से तुलनीय हैं और केवल निर्यातों की मात्रा के अनुसार तुलनीयता पर विचार किया है।
 - ग. प्राधिकारी को हान्वा ग्रुप से निर्यातकों को सहयोगी हितबद्ध पक्षकार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समस्त अपेक्षित सूचना दी है।
 - घ. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित करना अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत प्रदत्त नीति क्रमिक नीति और कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ में सेस्टेट और शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है।
 - ड. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना निर्यातकों के लिए हानिकारक होगी क्योंकि उच्च स्टार्ट-अप लागत और उच्चतर मूल्य पर प्रमुख कच्ची सामग्री की खरीद के कारण ऐसी लागत काफी अधिक होगी।
 - च. चीन के सहयोगी उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य के आधार परिकलित होना चाहिए जो इस जांच का भी हिस्सा है।
 - छ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ग्लिसरीन और ईसीएच की कीमतों में जांच अवधि के दौरान भारी कीमत अंतर के कारण उचित तुलना हेतु मासिक आधार पर निर्धारित करना चाहिए।
 - ज. डब्ल्यू - टी पद्धति के प्रयोग से पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित नहीं होगा, क्योंकि कीमतों में काफी अंतर है जिससे गणना में विचित्रता आ सकती है।

- झ. डब्ल्यू - टी पद्धति का प्रयोग अपवाद है जैसा कि यूएस - वाशर्स मामले में अपीलीय निकाय ने माना था और उसे लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में खरीदारों, क्षेत्रों या समयावधि के बीच निर्यात कीमतों में कोई खास अंतर नहीं है।
- ञ. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की गणना के लिए "शून्यकरण" करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उनकी स्वयं की प्रक्रिया और डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के विपरीत है।
- ट. एलएफसी ने आईसीआईएस द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत के आधार पर वस्तु का निर्यात किया है और यह उम्मीद करना अतर्कसंगत है कि एलएफसी विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए पृथक बाजार कीमत बनाए रखेगा।
- ठ. एजीसी विनिथाई ने सभी संबद्ध पक्षकार सौदों के संबंध में समस्त उचित प्रकटन किए हैं और वह सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी से सहयोग करेगा।
- ड. निर्यात घोषणा और सीएआरओटीएआर का प्रयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है, परंतु ऐसा मूल्यांकन डीजीटीआर के दायरे से बाहर है, क्योंकि यह बीआरआई का मामला है। चूंकि कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से सीआईएफ कीमत उच्चतर है इसलिए अल्प बीजकीकरण से शुल्क रियायत के अंतर्गत आयातों के संबंध में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. विदेशी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन डब्ल्यू - टी पद्धति के प्रयोग से परिकलित होना चाहिए क्योंकि निर्यात कीमत ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो पहले दो तिमाही की तुलना में जांच अवधि की अंतिम दो तिमाही से कोई खास अलग हो।
 - ख. यूएस - कोरिया से लार्ज रेजिडेंशियल वासर पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने लक्षित पाटन की स्थिति की समाधान के लिए डब्ल्यू - टी पद्धति के प्रयोग का समर्थन किया और यह नोट किया कि कीमत विभेद की प्रवृत्ति विवेकपूर्ण होनी चाहिए, यह प्रवृत्ति अन्य सौदों से कमतर कीमत के सौदों के संबंध में होनी चाहिए, कीमत में अंतर अधिक होना चाहिए और केवल नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए तथा सौदों की ऐसी प्रवृत्ति अन्य गैर प्रवृत्ति वाले सौदों से अलग होनी चाहिए।
 - ग. डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने यह भी माना कि डब्ल्यू - टी पद्धति के प्रयोग से पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रवृत्ति के सौदों तक सीमित होना चाहिए और गैर प्रवृत्ति सौदों पर पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, सभी निर्यात बिक्रियों पर पाटन मार्जिन के निर्धारण एक अंश के रूप में विचार करना चाहिए।
 - घ. डब्ल्यू-डब्ल्यू या टी-टी के पद्धति के प्रयोग से पाटन मार्जिन का निर्धारण आरंभिक अवधि में अपाटित सौदों द्वारा वर्ष के उत्तरार्ध में पाटन के स्तर को आवरित कर देगा।
 - ड. घरेलू उद्योग ने शून्यकरण का दावा नहीं किया है बल्कि घरेलू उद्योग का दावा डब्ल्यूटीओ की स्थिति से संगत है।
 - च. एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड जो जांच अवधि में ईसीएच का उत्पादक था, अपनी मूल कंपनी एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड को संबद्ध वस्तु की बिक्री से संबंधित सूचना देने में विफल रहा है।
 - छ. एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड / एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड को यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि घरेलू बाजार में की गई पर्याप्त बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है। यदि बिक्री की मात्रा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कम है तो उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य तीसरे देश

को निर्यात द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

- ज. प्राधिकारी को यह जांच अवश्य करनी चाहिए कि एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड / एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनी मूल कंपनी और विभिन्न संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री या इनपुट की खरीद दूरस्थ कीमतों पर थीं, ऐसा नहीं होने पर उत्पादक की उत्पादन लागत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यथा प्रचलित कच्ची सामग्री की कीमतों / इनपुट की कीमतों से समायोजित करना चाहिए।
- झ. एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड / एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत में अपनी संबंधित कंपनी एजीसी एशिया पैसिफिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रदत्त वितरण और सेवा शुल्क को निर्यातक के लिए निर्धारित निर्यात कीमत में संबंधित विपणन कंपनी के बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के रूप में समायोजित करना चाहिए।
- ञ. घरेलू उद्योग ने ऐसी सूचना के आधार पर थाईलैंड में सामान्य मूल्य उपलब्ध कराया है जो उत्तर देते समय तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थी।
- ट. बाजार अर्थव्यवस्था के लिए उचित तीसरे देश के चयन के लिए विकास के स्तर पर विचार करना अपेक्षित नहीं है। चूंकि थाईलैंड से निर्यातों की दूसरी सबसे बड़ी मात्रा कोरिया को हुई है। इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस पर विचार करना अपेक्षित है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के लिए समायोजनों के संबंध में ऐसी सूचना दी है जो आवेदन दायर करते समय तर्कसंगत रूप से उपलब्ध थी।
- ड. सामान्य मूल्य को थाईलैंड या कोरिया की कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विरोधी पक्षकारों ने यह दर्शाया है कि ऐसे देश अर्थव्यवस्था के विकास या संबंधित उत्पाद के स्तर की दृष्टि से चीन से तुलनीय हैं।
- ढ. चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित होना चाहिए जो तर्कसंगत लाभ के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित हो।
- ण. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत बढ़ी हुई नहीं है और वह किसी स्टार्ट-अप लागत से प्रभावित नहीं है इसे उत्पादन लागत का हिस्सा माना जाए। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए रिफाईंड, ग्लिसरीन और कास्टिक सोडा के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कोई आपत्ति नहीं है।
- त. निर्यात कीमत को आयातों की सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे कारखानाद्वारा स्तर पर ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।
- थ. मासिक आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण का दावा देरी करने की एक चाल है। किसी भी तरह घरेलू उद्योग ने तिमाही आधार पर सूचना दी है जिस पर विचार किया जा सकता है।
- द. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दिया गया है:

- i. जियांग्सू रूईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड ("रूईजियांग"), चीन जन. गण.
- ii. निंगबो हुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ("हुआनयांग"), चीन जन. गण.
- iii. कैनको मार्केटिंग, इंक. कोरिया गणराज्य
- iv. एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

- v. हनवा कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- vi. हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- vii. लोटे फाइन केमिकल, कोरिया गणराज्य
- viii. मिंजिन कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- ix. एजीसी विनीथार्ड पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- x. सैमसंग सीएंडटी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

34. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निर्यात कीमत में एक रूझान है जो पहले की दो तिमाही की तुलना में जांच अवधि की अंतिम दो तिमाही में काफी अलग है और इसलिए पाटन मार्जिन को डबल्यू - टी पद्धति से निर्धारित करना चाहिए। दूसरी ओर अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि प्राधिकारी को शून्यकरण नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी ने डबल्यू - डबल्यू आधारित मार्जिन संबंधी सूचना और अपने लिखित अनुरोध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त डबल्यू - टी पद्धति के संबंध में सूचना की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड के आयात के मामले में प्रस्तुत सूचना यह नहीं दर्शाती है कि विभिन्न अवधियों के बीच निर्यात कीमत में अंतर डबल्यू - डबल्यू पद्धति के प्रयोग से पर्याप्त रूप से लेखांकित नहीं होता है। इसके मद्देनजर पाटन मार्जिन को डबल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4.2 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 (iv) प्रावधानों के अनुसार डबल्यू - डबल्यू पद्धति के प्रयोग से परिकलित करना अपेक्षित नहीं है। चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से निर्यातों के संबंध में यद्यपि कीमत में अंतर अधिक महत्वपूर्ण है परंतु क्षति मार्जिन ऐसे देशों से सहयोगी और असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में कम है। इसके मद्देनजर चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से निर्यातों के लिए डबल्यू - टी पद्धति का प्रयोग आवश्यक नहीं है।
35. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयातित संबद्ध वस्तु की कीमत में भी काफी अंतर है। इस बात को घरेलू उद्योग और विरोधी पक्षकारों दोनों ने दर्शाया है। वर्ष के पूर्वार्ध में संबद्ध वस्तु की कीमतें अधिक रही हैं जबकि वर्ष के उत्तरार्ध में इनमें से भारी गिरावट आई है। अतः ऐसे अंतरों पर विचार करने के लिए प्राधिकारी ने सभी विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

36. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित निम्नलिखित संगत प्रावधानों को भी नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयवधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत

अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

37. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा के साथ कार्रवाई की थी। जांच शुरुआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना देने की सलाह दी थी कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण में उनके आंकड़ों / सूचना को अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार / पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं।
38. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का

निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि चीन जन. गण. के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक / निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है जिससे नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित धारणा का खंडन हो सके। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
41. यह नोट किया जाता है कि एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की परिकलन की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत और (ग) किसी तर्कसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे किसी ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

42. आवेदन प्रस्तुत करते समय घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर परिकलित होना चाहिए जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने हेतु विधिवत समायोजन होना चाहिए।
43. यह नोट किया जाए कि पहले और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना हेतु पक्षकारों द्वारा कोई सूचना / साक्ष्य नहीं दिया गया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य भारत में उचित प्रतिनिधि देश अर्थात् बेल्जियम या सऊदी अरब से निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि ऐसे तीसरे देशों से निर्यात न्यूनतम सीमा से कम रहे हैं। इसके अलावा, हितवद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य इंग्लैंड या कोरिया में कीमतों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, उन्होंने सिद्ध नहीं किया है कि इन दोनों में से कोई देश संबंधित देश के विकास और संबंधित उत्पाद के स्तर के मद्देनजर उचित है।
44. उक्त सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति अर्थात् जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
45. इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रत्येक तिमाही के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ छोड़कर उस पर विचार किया है। जांच अवधि के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

जियांग्सू रूईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड (रूईजियांग)

46. जियांग्सू रूईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड (रूईजियांग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। रूईजियांग ने भारत में असंबद्ध आयातकों को सीधे विचाराधीन उत्पाद बेचा है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान रूईजियांग भारत में असंबंधित आयातकों को *** एमटी का निर्यात किया है। भाड़ा, ऋण लागत, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित किए हैं और जांच अवधि के लिए भारत औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निंग्बो हुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड (हुआनयांग)

47. निंग्बो हुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड (हुआनयांग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। हुआनयांग ने भारत में असंबद्ध आयातकों को सीधे विचाराधीन उत्पाद बेचा है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान हुआनयांग ने भारत में असंबंधित आयातकों को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, ऋण लागत, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय तथा बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों को वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित किए हैं और जांच अवधि के लिए भारत औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन.गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

48. चीन जन. गण. से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन (एचएससी)

49. हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन (एचएससी) कोरिया गणराज्य में एक संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एचएससी ने

जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। एचएससी ने ऋण लागत और अंतरदेशीय परिवहन के लिए कीमत समायोजन का दावा किया और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी। इस प्रकार एचएससी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य प्रत्येक तिमाही के लिए परिकलित किया गया है और जांच अवधि के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

लोटे फाइन केमिकल (एलएफसी)

50. लोटे फाइन केमिकल (एलएफसी) कोरिया गणराज्य में एक संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एलएफसी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। एलएफसी ने अंतरदेशीय परिवहन, लोडिंग प्रभार, निरीक्षण शुल्क, ऋण लागत और पैकेजिंग लागतों के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी। इस प्रकार एलएफसी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य प्रत्येक तिमाही के लिए परिकलित किया गया है और जांच अवधि के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

51. कोरिया गणराज्य से अन्य सभी अहसयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

हनवा सोल्यूशंस कॉर्पोरेशन (एचएससी), हनवा कॉर्पोरेशन (एचसी), कैन्को मार्केटिंग, इंक. (कैन्को), एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड (एवरलाइट) और मिंजिन कॉर्पोरेशन (मिनजिन)

52. हनवा सोल्यूशंस कॉर्पोरेशन (एचएससी) कोरिया गणराज्य में एक संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। एचएससी ने हनवा कॉर्पोरेशन (एचसी), कैन्को मार्केटिंग, इंक. (कैन्को), एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड (एवरलाइट) और मिंजिन कॉर्पोरेशन (मिनजिन) के जरिए भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। एचसी, कैन्को, एवरलाइट और मिंजिन ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। जांच अवधि के दौरान एचएससी ने निम्नलिखित वितरण चैनल के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री की है।

एचएससी → एचसी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

एचएससी → कैन्को → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

एचएससी → एवरलाइट → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

एचएससी → मिनजिन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

53. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान एचएससी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। भारत को बिक्री के लिए अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, ब्रोकरेज, पत्तन प्रभार, समुद्री बीमा, ऋण लागत, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए इन्हें स्वीकृत किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और जांच अवधि के लिए भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

लोटे फाइन केमिकल (एलएफसी) और सैमसंग सी एंड टी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (एससीटी)

54. लोट्टे फाइन केमिकल (एलएफसी) कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एलएफसी ने सैमसंग सी एंड टी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड (एससीटी) जो थाईलैंड में एक व्यापारी है, के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। एलएफसी और एससीटी ने दावा किया है कि इन वस्तुओं को कोरिया से भारत को सीधे भेजा गया है और एससीटी केवल एक व्यापारी के रूप में कार्य करता है। एलएफसी ने आईएमएस कारपोरेशन के जरिए भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है। तथापि, चूंकि आईएमएस कारपोरेशन के जरिए निर्यात मामूली हैं। इसलिए उन्हें वर्तमान जांच से बाहर रखा गया है। एलएफसी और एससीटी ने संबद्ध वस्तु को भारत में सीधे असंबंधित उपभोक्ताओं को बेचा है। जांच अवधि के दौरान एलएफसी ने निम्नलिखित वितरण चैनलों के जरिए वस्तुओं का निर्यात किया है।

एलएफसी □ → एससीटी □ → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

55. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान एचएससी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। भारत को बिक्री के लिए समुद्री भाड़ा, सीमा शुल्क निकासी फीस, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, ऋण लागत, निरीक्षण शुल्क, पैकेजिंग लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए इन्हें स्वीकृत किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और जांच अवधि के लिए भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कोरिया गणराज्य से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

56. कोरिया गणराज्य से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड

57. एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) थाईलैंड में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एवीटी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु को बेचा है जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त मात्रा में की गई है।
58. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि एवीटी ने अपनी मूल कंपनी और अन्य संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री और इनपुट खरीदे हैं, यह नोट किया गया है कि निर्यातक ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए अपने संबंधित पक्षकार से खरीदी गई समस्त कच्ची सामग्री और इनपुट के पूरे व्यौरे दिए हैं। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना सत्यापित की है। यह नोट किया गया है कि एवीटी (पूर्व में एडवांस्ड बायोकेमिकल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात) अपने संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री और इनपुट की खरीद दूरस्थ आधार पर की गई है।
59. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि एवीटी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में अपने संबंधित पक्षकार को संबद्ध वस्तु बेची है। यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान एडवांस्ड बायोकेमिकल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित पक्षकारों को अन्य उत्पाद बेचे थे जो संबद्ध वस्तु की बिक्रियां नहीं थी। अब इसे प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।
60. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत के संबंध में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया था। कंपनी ने बीमा और अंतर्देशीय परिवहन के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। इस प्रकार एवीटी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य प्रत्येक तिमाही हेतु परिकलित किया गया है और जांच अवधि के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

61. थाईलैंड से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत**एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी)**

62. एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) थाईलैंड में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एवीटी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे विचाराधीन उत्पाद बेचा है। जांच अवधि के दौरान एवीटी ने निम्नलिखित वितरण चैनल के जरिए वस्तुओं का निर्यात किया है।

एवीटी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

63. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि एवीटी ने अपने संबंधित पक्षकार को कतिपय विपणन शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान किया है जिसे निर्यात कीमत में समाहित करना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी ने विपणन शुल्क के बारे में निर्यातक से अतिरिक्त सूचना मांगी है। निर्यातक ने बताया कि वह गैर विशेष आधार पर कतिपय सेवाएं देने के लिए अपने संबंधित पक्षकार के साथ एक सेवा करार में शामिल हुआ है। एवीटी ने मासिक आधार पर और नियत फार्मूले के आधार पर विपणन शुल्क का भुगतान किया है। यह नोट किया गया है कि चूंकि एवीटी ने जांच अवधि के दौरान केवल ईसीएच बेचा है। इसलिए एवीटी द्वारा उसकी संबद्ध कंपनी को प्रदत्त विपणन शुल्क भारत को ईसीएच के निर्यातों से सीधे संबंधित है। तदनुसार, एवीटी द्वारा उसके संबंधित पक्षकार को प्रदत्त विपणन शुल्क को निर्यातक के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत में समायोजित किया गया है।

64. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान एवीटी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, सर्वेक्षक लागत, बीमा, संभलाई प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया गया है और प्राधिकारी ने इन्हें स्वीकृत किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और जांच अवधि के लिए भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

65. थाईलैंड से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.2 पाटन मार्जिन

66. वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन तिमाही आधार पर निर्धारित किए गए हैं और निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	एनवी	ईपी	डीएम	डीएम	रेंज
क	थाईलैंड	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	%	
1	एजीसी विनयथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) (पूर्व में एडवांस्ड बायोकेमिकल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	***	***	***	***	10-20%
2	कोई अन्य	***	***	***	***	15-25%
ख	कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	
1	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	30-40%
2	लोटे फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
3	कोई अन्य	***	***	***	***	45-55%
ब	चीन जन. गण.	***	***	***	***	

1	जियांगसु रूईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%
2	निंग्बो हुआनयांग न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	(***)%	Negative
3	कोई अन्य	***	***	***	***%	30-40%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

67. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. थाईलैंड से संबद्ध आयात चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी मात्रा के रूझान अलग तरह के हैं और इसलिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार इनका संचयी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
- ii. थाईलैंड से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं है क्योंकि वे भारतीय खपत के अनुसार चले हैं।
- iii. चीन से संबद्ध आयातों में कीमत को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है क्योंकि चीन से आयातों की मात्रा थाईलैंड से आयातों की तुलना में काफी कम है जबकि चीन से पहुंच कीमत थाईलैंड से काफी अधिक है।
- iv. प्रस्तुत सूचना के आधार एलएफसी के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक होगा। क्षति यदि कोई हो, तो वह थाईलैंड से निर्यातों के कारण हो सकती है।
- v. 2013 में उत्पादक की मौजूदगी जो बाद में समाप्त हो गया। प्राधिकारी को वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की जांच करने से नहीं रोकता है।
- vi. आयातों की केवल क्षतिकारी मात्रा पर विचार करते हुए क्षति मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 के संगत नहीं है।
- vii. जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में मांग में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जो आवेदक के उत्पादन शुरू करते समय काफी अधिक हैं। जांच अवधि से पहले आयातों और मांग में घरेलू उत्पादन के अभाव में तालमेल रहा था।
- viii. आवेदक का यह दावा कि आयातों की मात्रा में उत्पाद शुरू होने के साथ गिरावट आनी चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक आरंभिक उद्योग स्थिर होने में और बाजार में जगह बनाने में पर्याप्त समय लेता है। फिर भी संबद्ध आयातों में जांच अवधि की एक तिमाही में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की विक्रियों में वृद्धि हुई है।
- ix. चूंकि आवेदक ने अभी उत्पादन शुरू किया है और शट डाउन का सामना किया है। इसलिए उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा स्वाभाविक रूप से अधिक होगी।
- x. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक बंदी के बाद निर्यात मात्राओं में केवल पुनः वापसी है।
- xi. समग्र आयातों में संबद्ध आयातों का बड़ा हुआ हिस्सा संबद्ध आयातों द्वारा गैर संबद्ध आयातों का केवल स्थान लेने से हुआ और इससे आवेदक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। आवेदक ने स्वयं संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से का स्थान लिया है।
- xii. भारत में मांग में एक सकारात्मक रूझान रहा है और इसलिए घरेलू उत्पादक के अभाव में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई होगी।
- xiii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव नहीं डाला है क्योंकि थाईलैंड से आयात में आयात

कीमत में कटौती के बावजूद गिरावट आई है।

- xiv. आयात कीमतों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के रुझान का पालन किया है और उनमें कच्ची सामग्री की कीमत में परिवर्तन के कारण अस्थिरता आई है और यह गिरावट पाटन के कारण नहीं हुई है।
- xv. आवेदक का यह दावा कि निर्यातक भारतीय बाजार में कम कीमत पर आपूर्ति कर रहे हैं, अस्वीकृत होना चाहिए क्योंकि इस दावे पर पहुंचने का स्रोत या पद्धति नहीं बताई गई है।
- xvi. आवेदक द्वारा निर्धारित लक्ष्य कीमत बाजार परिदृश्य को देखते हुए अवास्तविक है जो जांच अवधि के समय मौजूद थी और ऐसे लक्ष्य को पूरा करने में किसी विफलता को संबद्ध आयातों से नहीं जोड़ा जा सकता है।
- xvii. निर्यातक की कीमत व्यवहार्य की जांच के लिए मात्रा और कीमत के आंकड़े प्रपत्र IVक में प्रदत्त आंकड़ों तथा ट्रेड मैप से स्वतंत्र रूप से निकाले गए आंकड़ों से काफी अलग हैं।
- xviii. प्राधिकारी को संबद्ध वस्तु के कीमत के रुझानों के विश्लेषण के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच करनी चाहिए।
- xix. आवेदक ने उच्च कीमत पर कच्ची सामग्री खरीदी है और अपने संयंत्र के चालू होने में सुविधा के लिए उसे 3-4 महीने के लिए स्टोर किया है। जैसा कि क्यू3 और क्यू4 के लिए आय विवरण में स्वीकार किया गया है। दूसरी ओर सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी आयातों ने आर्थिक रूप से कुशल ढंग से कच्ची सामग्री खरीदी है।
- xx. ग्लिसरीन और ईसीएच की कीमतें मई, 2022 में शीर्ष पर थीं और जून 2022 के बाद जब आवेदक ने प्रचालन शुरू किया तो उनमें गिरावट आई। जून 2022 जब कीमतें सर्वाधिक थीं तब रिफाइंड ग्लिसरीन के प्रयोग से ईसीएच के उत्पादन के कारण घरेलू उद्योग की लागत उच्च रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की श्रम लागत में भी वृद्धि हुई है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने कच्ची ग्लिसरीन जो अधिक लागत कुशल होती है, के बजाय सितंबर, 2022 तक रिफाइंड ग्लिसरीन का प्रयोग किया है क्योंकि जांच अवधि के दौरान उनकी कीमतों के बीच *** प्रतिशत का अंतर था। घरेलू उद्योग ने काफी देरी से कच्ची ग्लिसरीन का प्रयोग किया। इस प्रकार उन्हें ग्लिसरीन पर आधारित उत्पादन प्रक्रिया के चयन के सचेत निर्णय के कारण बांछित बाजार हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका।
- xxii. इस अवधि में ईसीएच की कीमतों में तेजी से गिरावट को देखते हुए प्राधिकारी को विभिन्न मामलों में पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक विश्लेषण के बजाय कीमत और उत्पादन लागत के बीच तिमाहीवार विश्लेषण करना चाहिए।
- xxiii. लगभग सभी रसायनों की सीआईएफ कीमत में यूक्रेन – रूस युद्ध, इजराइल युद्ध, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में वित्तीय अस्थिरता के कारण जांच अवधि में गिरावट आई है।
- xxiv. चूंकि ग्रासिम लिमिटेड और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड इस समय ईसीएच का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह अस्पष्ट है कि ऐसे उत्पादक उत्पाद में निवेश क्यों कर रहे हैं।
- xxv. चूंकि घरेलू उद्योग संपूर्ण जांच अवधि के लिए प्रचालनरत नहीं था। इसलिए प्रचालन की सीमित अवधि के लिए क्षति मापदंड उद्योग की स्थिति की सही तस्वीर नहीं दिखा सकेंगे।
- xxvi. आवेदक के अनुमानित मापदंड पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रचालन लागत और लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले भारी कीमत उतार-चढ़ाव पर विचार किए बिना विशिष्ट बाजार दशाओं पर निर्भर होते हैं।
- xxvii. आयातों ने घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग को बाधित नहीं किया है और वह उसे धीरे-धीरे बढ़ाने में सक्षम है जैसा कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 और वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में तिमाही

आय विवरण में रिकार्ड किया गया है।

- xxviii. आवेदक का क्षमता उपयोग आरंभिक स्तर पर घरेलू उद्योग के लिए शट डाउन का सामना करने के बावजूद प्रभावशाली रहा है।
- xxix. आवेदक पर संबद्ध आयातों के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े हैं क्योंकि उनके बाजार हिस्से में लक्षित स्तर तक नहीं परंतु वृद्धि हुई हुई है।
- xxx. तीसरी तिमाही में संयंत्र बंद होने के बावजूद घरेलू उद्योग पहली तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में अपनी बिक्री और उत्पादन तेजी से बढ़ाने में सक्षम रहा था जो तिमाही आय लक्ष्यों में व्यक्त आशाओं के अनुरूप था।
- xxxi. आवेदक ने दावा किया है कि ईष्टतम क्षमता उपयोग पर भी उसे परियोजना रिपोर्ट के आधार पर घाटा होगा परंतु रिपोर्ट का अगोपनीय अंश नहीं दिया गया है।
- xxxii. प्रचालन जारी रखने में आवेदक की अक्षमता के लिए अनेक शट डाउन जिम्मेदार हो सकते हैं जो प्रचालनात्मक अक्षमताएं दर्शाए हैं। ऐसे शट डाउन ईसीएच की कीमत में गिरावट और ग्लिसरीन की कीमत में वृद्धि के कारण कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता और वाणिज्यिक अव्यवहार्यता के कारण हो सकते हैं।
- xxxiii. चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता है इसलिए उसे बाजार के आयामों के कारण स्वयं को स्थापित करने में थोड़ा समय लगेगा और प्रयोक्ता द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल बदलना समाधान नहीं है।
- xxxiv. मालसूची स्तर पर तिमाहीवार अस्थिरता जो एकमात्र है क्षति का संकेत नहीं हो सकती है क्योंकि उसे दीर्घावधिक रुझानों के रूप में विश्लेषित करना चाहिए और बिक्री कीमत, बिक्री मात्रा, लाभ आदि जैसे अन्य मानदंडों के संबंध में देखना चाहिए।
- xxxv. घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई मालसूची निर्यातकों के ट्रैक रिकार्ड, चालू संविदाएं और प्रदत्त उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर के आधार पर केवल प्रयोक्ता उद्योग की पसंद के कारण है।
- xxxvi. भेषज क्षेत्र द्वारा बनाई गई संविदा अवधि जनवरी से दिसंबर तक है और इसलिए आवेदन के बाद स्वयं को स्थापित करने का अवसर नहीं है।
- xxxvii. घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के संबंध में किया जाना चाहिए जिनमें उसने बाजार में प्रवेश किया।
- xxxviii. आवेदक के पीओआई के बाद के निष्पादन की भी जांच की जानी चाहिए। जैसे सीपीवीसी, स्टायरिन बुटाडीन रबड़ और रेजिन के मामले में प्राधिकारी की प्रक्रिया रही थी।
- xxxix. उत्पादन पद्धति और खरीद प्रक्रिया में जांच अवधि के दौरा रिफाइंड से कच्चे ग्लिसरीन में परिवर्तन के प्रभाव को हटाने के लिए दावा की गई क्षतिरहित कीमत समायोजित की जाना चाहिए। जांच अवधि के लिए कच्चे ग्लिसरीन (और रिफाइंड ग्लिसरीन नहीं) की औसत लागत पर भारत में आयातों की वास्तविक कीमत या औसत आईसीआईएस कीमत के आधार पर विचार करना चाहिए तथा आवेदक के पीओआई के बाद के प्रचालनों के आधार पर कच्चे ग्लिसरीन के शुद्धिकरण की वास्तविक वृद्धिशील लागत पर विचार किया जाए। इसके अलावा, प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए ईष्टतम उत्पादन निर्धारित करने हेतु ईष्टतम क्षमता उपयोग के रूप में *** प्रतिशत पर विचार करना चाहिए कि क्षतिरहित कीमत बाजार की गति से प्रभावित न हो जिससे क्षति हो सकती है।
- xl. उत्पादन अक्षमताओं के कारण उच्च मूल्य ह्रास और व्याज लागत कम क्षमता प्रचालन और कच्ची सामग्री की अधिक खपत क्षतिरहित कीमत और परिणामी क्षति की गणना को विकृत बना सकती है।

- xli. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक ने अपारंपरिक उत्पादन तकनीकी लेने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार के लिए किसी रायालिटी शुल्क का भुगतान किया है जिससे उत्पादन की लागत बढ़ गई है।
- xlii. घरेलू उद्योग की अनुमानित लाभप्रदता को प्राप्त करने में असमर्थ था। आयातों के कारण नहीं है बल्कि अन्य कारकों की वजह से है।
- xliii. घरेलू उद्योग निर्यात बाजार पर अधिक केंद्रित है और उसने यूरोप के प्रमुख पत्तनों पर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किए हैं।
- xliv. मिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड जो ईसीएच संयंत्र के रूप में अपनी जेवी कंपनी, पेट्रो एराल्डाइट प्राइवेट लिमिटेड की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित हुआ था, ने खराब निष्पादन के कारण प्रचालन बंद कर दिया। इसकी वजह से टीपीएल द्वारा ईसीएच प्रचालन बंद हो गए।
- xlvi. आवेदक ने अपने आय लक्ष्यों में स्वीकार किया है कि इपोक्सी की वैश्विक मांग में कमी, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी रही है।
- xlvi. ताईवान और अन्य देशों से आयातों के प्रभाव पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए।
- xlvi. अंतिम प्रयोक्ता चीन द्वारा उत्पादित ईसीएच को कम पसंद करते हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

68. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. सभी संबद्ध देशों से आयातों का संचयी विश्लेषण किया जा सकता है क्योंकि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत संचयी विश्लेषण के लिए प्राधिकारी के लिए ईसी-ट्यूब या पाइप फिटिंग में अपीलीय निकाय द्वारा संमुक्ति के अनुसार संचयी की पूर्व शर्त के रूप में देश वार मात्रा और कीमत का विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं है।
- iii. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग जांच की पूरी अवधि में प्रचालनरत नहीं था, कि वर्तमान जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि वास्तविक बाधा के विश्लेषण में मूल मान्यता यह है कि उद्योग तर्कसंगत समयावधि के लिए प्रचालन में नहीं रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत कच्ची सामग्री की कीमतों में अंतर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुमानों में पर्याप्त रूप से प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना के रूप में पर्याप्त रूप से रखा गया है।
- v. जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन शुरू होने के बावजूद संबद्ध आयातों में आधार वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों की मात्रा पीओआई की बाद की अवधि में भी अधिक रही है।
- vi. संबद्ध आयातों में घरेलू खपत के संबंध में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और ये कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 6 गुना रहे थे।
- vii. यद्यपि संबद्ध वस्तु की मांग में इस अवधि में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि आयातों की मात्रा में इसी समय के दौरान 44 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई है।
- viii. संबद्ध आयात भारत में ईसीएच की मांग – आपूर्ति के अंतर से अधिक हैं।
- ix. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 2019-20 में *** प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में *** प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में घरेलू उद्योग को बाजार के *** प्रतिशत प्रतिशत से अधिक को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद बाजार हिस्से में मामूली लाभ हुआ है।

- x. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के बाद लगातार गिरावट आई है और यह गिरावट कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट से अधिक है।
- xi. यद्यपि संबद्ध आयात 2021-22 तक गैर संबद्ध आयातों से अधिक कीमत पर हुए थे, परंतु संबद्ध आयातों की कीमत में जांच अवधि में भारी गिरावट आई और ये गैर संबद्ध आयातों से 13 प्रतिशत कम कीमत पर थे।
- xii. रिफाइंड ग्लिसरीन और कास्टिक सोडा की कीमतों पर विचार करते हुए यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की कीमत कच्ची सामग्री की लागत से कम से कम 700 – 1,000 अमरीकी डॉलर से अधिक थी। तथापि कच्ची सामग्री का मार्क-अप जांच अवधि में तेजी से कम हुआ है और तीसरी तिमाही में ऋणात्मक भी रहा था। घटते हुए मार्क-अप का कच्ची सामग्री की लागत में रुझान तब भी स्पष्ट था जब कच्चे ग्लिसरीन की कीमत पर विचार किया गया है।
- xiii. विदेशी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में अपने निर्यात कीमत को जानबूझकर कम किया है और भारत को निर्यात कीमत शेष विश्व की निर्यात कीमत से काफी कम थी और जांच अवधि के दौरान यह अगले बड़े बाजारों से कम रही थी।
- xiv. संबद्ध आयातों से घरेलू कीमतों और घरेलू उद्योग की लक्षित कीमत में इस तथ्य के बावजूद भारी कटौती हुई थी कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें घटाई और घाटे उठाना चुना। संबद्ध आयातों से कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा पीओआई के बाद की अवधि में भी जारी रही।
- xv. कम कीमत के आयातों में घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास किया क्योंकि उसे अपनी बिक्री कीमत में कच्चे ग्लिसरीन और कास्टिक सोडा की कीमत में गिरावट से काफी अधिक दर पर कटौती करनी पड़ी ताकि वह काफी कम पहुंच कीमतों से प्रतिस्पर्धा कर सके।
- xvi. यद्यपि कच्ची सामग्री की कीमतों में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई। तथापि, ईसीएच की कीमतों में काफी तेजी से गिरावट आई।
- xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार बिना किसी आधार के कच्चे और रिफाइंड ग्लिसरीन के बीच केवल कीमत अंतर का उल्लेख करके जांच को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ईसीएच की कीमत की तुलना रिफाइंड ग्लिसरीन या कच्चे ग्लिसरीन की कीमत से की जाए तो वह संबद्ध आयात की कीमत में असाधारण गिरावट दर्शाएगी।
- xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि संबद्ध वस्तु की कीमतें वास्तविक सांकेतिकों के अनुसार चली हैं।
- xix. थाईलैंड में उत्पादक एजीसी विनिथाई आक्रामक कीमत में शामिल है, क्योंकि उसे अपने पीवीसी संयंत्र से उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न हाइक्लोरोरिक एसिड गैस की खपत सुनिश्चित करने के लिए अपना ईसीएच संयंत्र चलाना पड़ा है।
- xx. घरेलू उद्योग ने उच्च क्षमता उपयोग के साथ प्रचालन शुरू किए थे परंतु मामूली बाजार हिस्से और मालसूची के एकत्र होने के कारण उसे उत्पादन में कटौती करनी पड़ी और अपनी क्षमता का एक तिहाई से कम का उपयोग करना पड़ा। ऐसा उत्पादन और क्षमता उपयोग निरंतर पाटन के कारण अनुमानित स्तरों से काफी कम है।
- xxi. घरेलू उद्योग को प्रचालन के केवल 3 महीनों बाद उत्पादन रोकना पड़ा था और उत्पादन पूरी तीसरी तिमाही में बंद रहा। उत्पादन पीओआई के बाद की अवधि में दो महीने के अधिक के लिए बंद रहा।
- xxii. संबद्ध आयातों में बाजार में बिक्री करने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है और उसकी घरेलू बिक्रियों का उसकी क्षमताओं में मामूली हिस्सा है और उसके कुल उत्पादन के आधे से कम है।

- xxiii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां और बाजार हिस्सा उसके अनुमानों से काफी कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्रियां प्रचालन के दूसरे वर्ष में ही अपने अनुमान से काफी कम हैं।
- xxiv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में थोड़ी वृद्धि को क्षति की अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उत्पादन शुरू करने वाला कोई उत्पादक धीरे-धीरे बाजार हिस्सा बढ़ाने की उम्मीद करता है।
- xxv. घरेलू उद्योग ने मालसूची एकत्रित की है जो कतिपय महीनों में उसके उत्पादन से काफी अधिक हैं और जांच अवधि में घरेलू बिक्रियों से अधिक है। इसके अलावा, मालसूची अनुमानित स्तरों से काफी अधिक थी और प्रचालन के दूसरे वर्ष में भी अधिक रही है।
- xxvi. घरेलू बिक्रियों के संबंध में मालसूची धारण अवधि एक वर्ष से अधिक थी और उत्पादन के संबंध में यह 6 महीने के बराबर थी।
- xxvii. प्रचालन के पहले महीने में लाभ कमाने के बावजूद घरेलू उद्योग को भारी घाटे, नकद घाटे और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेशी उत्पादकों ने अपनी कीमतें आक्रामक रूप से कम कर दी। होने वाले घाटे प्रचालन के प्रथम वर्ष में लाभप्रदता के अनुमानों से विपरीत थे।
- xxviii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी परिवर्तनशील लागत से कम पर बिक्री के लिए मजबूर किया है और परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का अंशदान ऋणात्मक हो गया है।
- xxix. वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग को यदि वह अनुमानित क्षमता उपयोग और प्रचालन करता तो भी भारी घाटों का सामना करना होगा और लागत वसूलना भी असंभव होगा।
- xxx. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तब अधिकतम थी जब ग्लिसरीन की कीमतें अधिक थी। जबकि लाभप्रदता ग्लिसरीन की कीमतों के घटने पर कम हो गई।
- xxxi. घरेलू उद्योग द्वारा आयातित रिफाईंड ग्लिसरीन तिमाही के भीतर उपयोग के लिए पर्याप्त थी, परंतु उसे लंबी अवधि के लिए भंडारित रखा था, क्योंकि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को उसकी क्षमताओं के उपयोग से रोक दिया। किसी भी तरह घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों पर कच्ची सामग्री खरीदने या अपने पास कच्ची सामग्री के रूप में कच्चे ग्लिसरीन के प्रयोग पर भी उच्चतर घाटा हुआ होता।
- xxxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक द्वारा उसकी वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही आय लक्ष्य पर अलग से विवरणों का संदर्भ दिया है और संदर्भ या पूरे प्रयोजन के लिए उपयुक्त पूर्ण संदर्भ नहीं दिए हैं।
- xxxiii. कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो भिन्न कच्ची सामग्री के लिए घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत के प्रतिस्थापन का प्रावधान करता हो और घरेलू उद्योग की वही में दर्ज लागतों पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में कच्ची सामग्री की लागत उच्चतर है।
- xxxiv. अनुबंध III के प्रावधान इस अवधि में उत्पादन क्षमताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार की अनुमति देते हैं और न कि क्षमताओं के ईष्टतम उपयोग की। जब भी प्राधिकारी ईष्टतम उपयोग को मानते हैं तो भी वह अनुमानित उपयोग पर आधारित होना चाहिए और न कि 100 प्रतिशत पर। इसके अलावा, जहां घरेलू उद्योग इतने कम उपयोग पर कार्य कर रहा है, वहां वह संसाधन तैनात नहीं करेगा और खर्च नहीं उठाएगा, क्योंकि वह अपनी पूर्ण क्षमताओं पर प्रचालनरत होगा।
- xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई उत्पादन अक्षमताएं नहीं बताई हैं जिनसे उच्चतर लागत हो। घरेलू उद्योग ने ग्लिसरीन के ईष्टतम उपयोग पर विचार करते हुए क्षतिरहित कीमत का दावा किया है जो किसी भी तरह औसत उद्योग खपत से कम है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग को क्षति को यथा मौजूद रूप में देखा जाना चाहिए और घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारकों

के संबंध में गैर आरोपण विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यूरोपीय संघ – बायोडीजल (अर्जेटीना) में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय, निप्पॉन ज़ियोन कंपनी लिमिटेड बनाम डीए ने सेस्टेट और पूर्ववर्ती जांचों में स्वयं प्राधिकारी ने माना है।

- xxxvii. ऐसी कोई संविदाएं नहीं थीं जिन्होंने प्रयोक्ता उद्योग को घरेलू उद्योग से वस्तुएं खरीदने से रोका हो क्योंकि प्रयोक्ता विशिष्ट रूप से अपनी मांग के केवल 50-60 प्रतिशत के लिए संविदा में शामिल होते हैं जबकि शेष मांग को मौके पर पूरा किया जाता है। इसके अलावा, संविदाओं की मौजूदगी काफी कम कीमत के आयातों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती है।
- xxxviii. भेषज उद्योग मौके पर या तिमाहीवार संविदाओं के अंतर्गत वस्तुएं खरीदता है और वह किसी वार्षिक संविदा तक सीमित नहीं है। किसी भी तरह घरेलू उद्योग लगभग दो वर्षों से प्रचालनरत है और उसे अब भी घाटा हो रहा है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग की कम बिक्रियां भेषज उद्योग की संविदा अवधि के कारण नहीं हैं। इसके अलावा, भेषज उद्योग के पास कुल खपत का बड़ा हिस्सा नहीं है।
- xxxix. यद्यपि एक प्रमुख इपोक्सी उत्पादक ने घरेलू उद्योग से बड़ी मात्रा में खरीद की है, परंतु उसने कीमतों में गिरावट शुरू होने पर ईसीएच का आयात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह पता चलता है कि प्रयोक्ता किसी संविदा से सीमित नहीं है, बल्कि सस्ते उत्पादों की उपलब्धता से चलते हैं।
- xl. घरेलू उद्योग ने उच्चतर कीमतों पर अपनी वस्तु का निर्यात किया है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद गुणवत्ता की समस्याओं से ग्रस्त नहीं है।
- xli. घरेलू उद्योग द्वारा देखा गया शट डाउन कच्ची सामग्री की कमी, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, कानूनी अनुपालनों, बिजली की कमी, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश क्षमताओं के कारण नहीं हुआ था।
- xlii. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत में कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क नहीं जोड़ा है। किसी भी तरह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला कोई उत्पादक ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा और यह घरेलू उद्योग के लिए कोई विचित्र बात नहीं है।
- xliii. संबद्ध देशों के अलावा, केवल ताईवान से भारी आयात हुए हैं, परंतु ऐसे आयात उच्चतर कीमत पर हुए हैं और उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

69. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
70. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वर्तमान आवेदन उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा से संबंधित है। इस प्रकार एक विस्तृत क्षति जांच करने से पहले प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग उस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था जिसमें वह वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन करवा सकता था या घरेलू उद्योग एक

शुरूआती या आरंभिक उद्योग था। उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में हो और जिसके पास वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन करने के लिए पर्याप्त पूर्व इतिहास न हो।

ज.3.1 किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा

71. यह देखा गया है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार या नियमावली “वास्तविक बाधा” के लिए परिभाषा नहीं देते हैं। डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 के फुटनोट 9 में केवल निम्नानुसार उल्लेख है:

“ इस करार के अंतर्गत “क्षति” शब्द यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग के वास्तविक क्षति के खतरे या ऐसे किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के अर्थ में प्रयुक्त होगा और इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार इसकी व्याख्या की जाएगी।”

72. इसी प्रकार नियमावली का अनुबंध II केवल वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे और वास्तविक बाधा को क्षति की परिभाषा के अंतर्गत संयुक्त करता है। इसका कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं है कि एक उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा क्या होती है।
73. तथापि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग के लिए वास्तविक बाधा किसी अस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगी और न कि उस उद्योग के संदर्भ में जो पूरी तरह स्थापित हो। यह सच है क्योंकि प्राधिकारी के लिए यह ज्ञात करना तार्किक नहीं है कि कोई घरेलू उद्योग पाटित आयातों द्वारा नुकसान उठा रहा है (जो पहले मानते हैं कि ऐसा कोई उद्योग पहले से स्थापित है) और इसी के साथ वह पाते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना उन आयातों द्वारा वास्तविक रूप से बाधित हुई है। अस्थापित उद्योग शब्द डब्ल्यूटीओ करार, अधिनियम या नियमावली में उल्लिखित नहीं है। तथापि, डब्ल्यूटीओ में पाटनरोधी करार में एक संशोधन प्रस्तावित है जो वास्तविक बाधा और उद्योग की स्थापना के अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करता है। मसौदा प्रस्ताव का संगत उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत है। यद्यपि उक्त प्रावधान अब तक करार में शामिल नहीं हुआ है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण करने के लिए भी इस पर विचार किया है।

“3.9 घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और केवल आरोप, संयोग या सुदूर संभावना पर आधारित नहीं होगा। किसी उद्योग को तब स्थापित माना जा सकता है जब आयातक सदस्य के क्षेत्र में पूर्व में नहीं उत्पादित किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए संसाधनों की वास्तविक और पर्याप्त वचनबद्धता की गई हो, परंतु उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ हो या अभी वाणिज्यिक मात्राओं तक नहीं पहुंचा हो। यह निर्धारण करने में कि क्या कोई उद्योग स्थापना में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित क्षमता, किए गए निवेश और प्राप्त वित्तपोषण तथा व्यवहार्यता अध्ययन, निवेश योजना या बाजार अर्चनों से संबंधित साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं”।

74. मोरक्को - तुर्की से कतिपय हॉट रोलड स्टील पर पाटनरोधी उपाय पर डब्ल्यूटीओ पैनल ने इस निर्धारण के लिए कुछ निर्देश निर्धारित किए कि किसी उद्योग की स्थापना क्या है। पैनल ने यह अवलोकन किया कि अनुच्छेद 3.1 में यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति विहित नहीं है कि क्या कोई उद्योग विस्थापित हुआ है। तदनुसार, प्राधिकारी के लिए किसी तर्कसंगत पद्धति के प्रयोग की अनुमति है जो मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित हो तथा ये अनुमानों तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।
75. पैनल ने यह भी संमुक्ति की है कि प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि यह निर्धारित करने में कौन से मापदंड संगत हैं कि क्या एक नया उद्योग स्थापित हुआ है। पैनल द्वारा संगत माना गया एक मापदंड यह था कि क्या उत्पादन किसी मौजूदा कंपनी की एक नई उत्पाद लाइन है। यदि कोई मौजूदा उद्योग / कंपनी केवल एक नई उत्पाद लाइन शुरू करता है तो उसे अस्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता है। इस कारक की जांच के लिए प्राधिकारी उत्पादक की समग्र अवसंरचना के प्रयोग में अतिव्यापन की मात्रा की जांच करेंगे (उपभोक्ता संविदा, वितरण चैनल, मौजूदा उत्पादन, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियां आदि सहित) पुरानी अवसंरचना में अतिव्यापन की अधिक मात्रा का अर्थ होगा कि इसकी कम संभावना है कि कोई नया उद्योग स्थापित हुआ है। पैनल की संमुक्ति का संगत हिस्सा नीचे दिया गया है।

“7.2.11. आरंभ में हम नोट करते हैं कि हम इन कारकों की स्वयं घोषणा नहीं करते हैं या क्या वे यह निर्धारित करने में निर्देशक या परिभाषात्मक हैं कि क्या घरेलू उद्योग अस्थापित है। हम स्वीकार करते हैं कि संगत कारक हो सकते हैं कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में जांच के अधीन समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। इसी के साथ हम नोट करते हैं कि यद्यपि बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है, जहां वह उत्पाद किसी मौजूदा उद्योग की केवल एक नई उत्पाद लाइन हो और मौजूदा उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों से लाभान्वित होता हो, वहां ऐसे साझे प्रचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या एक अलग नया उद्योग स्थापित हुआ है। यदि कोई मौजूदा उद्योग इस समय उत्पादित किसी अन्य उत्पाद से अलग कोई नया उत्पाद शुरू करने को चुनता है तो उस नए उत्पाद की शुरुआत आवश्यक रूप से नए उद्योग के सृजन का परिणाम नहीं होगी। यह फिर भी माना जा सकता है कि मौजूदा उद्योग में एक नई उत्पाद लाइन की शुरुआत मौजूदा उद्योग की समग्र अवसंरचना के प्रयोग की मात्रा पर निर्भर करती है (उत्पादक, वाणिज्यिक अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) समग्र अवसंरचना के प्रयोग में अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी एक नए उद्योग की स्थापना दर्शाने वाले नए उत्पाद की शुरुआत की अवधारणा उतनी ही कम होने की संभावना है। यह तथ्य कि कोई घरेलू उद्योग समान उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 में परिभाषित है और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के कोई पहले मौजूद उत्पादक नहीं हैं, उस घरेलू उद्योग को मौजूदा अवसंरचना जैसे उपभोक्ता संपर्क और वितरण चैनल के उपयोग की संभावना से घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत को मान्यता नहीं देता है”।

76. उक्त पर विचार करते हुए और ऐसी किसी विहित पद्धति के अभाव में जिसे प्राधिकारी यह निर्णय करने में अपनाए कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित है, प्राधिकारी ने वास्तविक बाधा की जांच करने के लिए उपयुक्त मामला की जांच करते समय निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया है।

ज.3.2 वर्तमान में घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक बाधा

77. यह देखा गया है कि आवेदक ने भारी निवेश करके संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत से पहले संबद्ध वस्तु की संपूर्ण मांग आयातों से पूरी हो रही थी। ऊपर जांचे गए कारकों के आधार पर यह देखा गया कि वर्तमान मामले घरेलू उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और उद्योग को हुई क्षति वास्तविक बाधा की प्रकृति की है।

क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत

78. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यद्यपि संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। फिर भी घरेलू उद्योग का निष्पादन अनुमानित आंकड़ों से कम है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन उसकी अनुमानित उत्पादन मात्रा का केवल *** प्रतिशत और क्षमता उपयोग का केवल *** प्रतिशत था। इस स्थिति के विपरीत घरेलू उद्योग प्रचालन के पहले वर्ष में *** प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने के अनुमान पर था जिसका अर्थ *** एमटी का उत्पादन है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मौजूदगी के कारण अपना अनुमातिन उत्पादन प्राप्त करने में विफल रहा है।

ख. क्या संबद्ध वस्तु का उत्पादन एक मौजूदा उद्योग में केवल एक नई उत्पाद लाइन है ?

79. जैसा ऊपर उल्लिखित डब्ल्यूटीओ पैनल ने संसुक्ति की है कि यदि उद्योग का उत्पादन मौजूदा उद्योग में केवल एक नई उत्पाद लाइन है तो वह वास्तविक बाधा का मामला नहीं हो सकता है। तथापि पैनल ने जोर दिया कि महत्वपूर्ण यह है कि वह मात्रा कितनी है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के लिए मौजूदा अवसंरचना का उपयोग हुआ है। इसके अलावा, पैनल ने यह देखा कि नई उत्पाद लाइन के अलावा, प्राधिकारी को उद्योग की मौजूदा अवसंरचना में अतिव्यापन की मात्रा की जांच करनी चाहिए।
80. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के लिए एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया और जुलाई, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा, चूंकि नया संयंत्र या उत्पादन लाइन संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए स्थापित हुई थी। इसलिए मौजूदा अवसंरचना और स्थापित किए गए नए संयंत्र के बीच कोई

अतिव्यापन नहीं है।

ग. समग्र रूप से घरेलू बाजार के आकार के तुलना में उत्पादन और क्षमता का आकार

81. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान क्षमताएं स्थापित की हैं जो बाजार के *** प्रतिशत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, *** एमटी के उत्पादन के मुकाबले घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में केवल *** एमटी बेचने में समर्थ रहा था। यद्यपि संबद्ध आयातों के पास *** प्रतिशत का बाजार हिस्सा था। तथापि, घरेलू उद्योग केवल *** प्रतिशत बाजार मांग को पूरा कर रहा था। यह दर्शाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग बाजार में आपूर्ति नहीं कर पा रहा था।

घ. अनुमानित प्रचालनों की तुलना में प्रचालनों की स्थिरता

82. विभिन्न व्यापक आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्रियां, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त निष्पादन निवेश करते समय घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है। यद्यपि घरेलू उद्योग मांग के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से को पूरा करने की स्थिति में है। तथापि उसका बाजार हिस्सा *** प्रतिशत तक सीमित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रचालन के बिल्कुल पहले वर्ष में लाभ का अनुमान लगाया था। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी लागत और यहां तक कि परिवर्तनशील लागतों की वसूली करने में असमर्थ रहा है और उसे भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, अनुमानित निष्पादन और प्राप्त वास्तविक निष्पादन के बीच काफी बड़ा अंतर है।

ज.3.3 क्षति का संचयी आकलन

83. विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो तो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित होता हो कि :

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में कि चीन से आयात से घरेलू उद्योग की मात्रा या कीमतें प्रभावित नहीं हो सकती हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.3 तथा अनुबंध II का पैरा (iii) स्पष्ट रूप से सभी संबद्ध देशों से आयातों के संचयी विश्लेषण से पहले पूरी की जानी वाली शर्तें दर्शाते हैं। ऐसे प्रावधानों में प्राधिकारी के लिए ऐसे संचयी आकलन से पहले की शर्त के रूप में कीमतों का देशवार विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं होता है। इसी - ब्राजील से मैलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट [डीएस/129/एवी] में यह मत अपनाया गया है कि जिसमें निम्नानुसार माना गया था:

“ 110. हमें ब्राजील की इस बात के लिए अनुच्छेद 3.3 के पार्ट में ऐसा कोई आधार नहीं मिला कि पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों के संभावित ऋणात्मक प्रभाव का देश विशिष्ट विश्लेषण सभी पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन की पूर्व शर्त है। अनुच्छेद 3.3 स्पष्ट रूप से वे शर्तें रखता है जिन्हें एक से अधिक देश से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष पूरा किया जाना चाहिए। देशवार मात्रा और कीमत विश्लेषण का ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जिसे ब्राजील संचयन की पूर्व शर्त के रूप में बताता हो।

वास्तव में अनुच्छेद 3.3 में स्पष्ट रूप से जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए देश विशिष्ट मात्राओं की जांच ब्राजील द्वारा सुझाए गए अनुसार नहीं करना अपेक्षित है बल्कि यह निर्धारित करने के लिए अपेक्षित है कि क्या प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है।

85. इसके अलावा, थाईलैंड सरकार ने दावा किया है कि थाईलैंड से आयातों में चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों की तरह प्रतिस्पर्धा की समान शर्तें नहीं हैं, क्योंकि थाईलैंड से आयातों के मात्रा के रूझान ऐसे अन्य संबद्ध देशों से आयातों के समान नहीं हैं। तथापि यह नोट किया गया है कि आयातों की समान मात्रा और बाजार हिस्से के रूझानों के विश्लेषण को यह निर्धारित करने का एकामत्र मापदंड नहीं माना जा सकता है कि क्या एक देश से आयात दूसरे देश से आयातों के प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.3 जांचकर्ता प्राधिकारी पर ऐसा कोई दायित्व नहीं डालता है। डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा इस बात की यूरोपीय संघ – चीन से कतिपय फुटबियर पर पाटनरोधी उपाय मामले में उसकी रिपोर्ट में [डब्ल्यूटी/डीएस405/आर] पुष्टि की है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:

“7.404. अनुच्छेद 3.3 के कथित उल्लंघन को देखते हुए हमें चीन के इस विचार के लिए अनुच्छेद 3.3 के पार्ट में कोई आधार नहीं दिखता है कि कोई जांचकर्ता प्राधिकारी यह सिद्ध करेगा कि विभिन्न देशों से आयातों में समान मात्रा और बाजार हिस्से के रूझान हैं या यह कि विभिन्न निर्यातक देशों में प्रतिस्पर्धा की दशाएं “समान” या “सामान्य” हैं ताकि यह निष्कर्ष निकल सके कि “प्रतिस्पर्धा की स्थितियों” के आलोक में संचयी आकलन उचित है। जैसा हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 3.3 में ऐसे कोई विशिष्ट अनिवार्य या सांकेतिक कारक नहीं हैं जिन पर यह आकलन करने हेतु विचार करना चाहिए कि क्या “प्रतिस्पर्धा की स्थितियों” के आलोक में संचयी विश्लेषण करना उचित है। हम इस संबंध में, नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने ऐसे तर्कों को अस्वीकृत किया है जो एडी करार के अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत अतिरिक्त दायित्व सृजित करेंगे...”

86. इस प्रकार, केवल इसलिए कि थाईलैंड से आयातों की मात्रात्मक रूझान अन्य देशों के आयातों के अनुसार नहीं चले हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे आयात परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर थाईलैंड से आयात अन्य संबद्ध देशों से आयातों के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु से प्रतिस्थापनीय हैं। इसके अलावा, थाईलैंड से आयातित संबद्ध वस्तु उसी अंतिम उपयोग में प्रयोग होती है जिसमें अन्य देशों से आयात और भारत में उत्पादित समान वस्तु प्रयोग होती है। अतः यह नोट किया गया है कि थाईलैंड से आयात चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के आयातों से साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

87. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- क. संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा का अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ भी सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

88. तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित होगा।

ज.3.4 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

89. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस

प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आवेदक की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	100
संबद्ध आयात	एमटी	46,202	40,906	69,292	81,388
अन्य आयात	एमटी	14,003	17,041	9,192	4,822
खपत / मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	130	150

90. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2020-21 तक गिरावट आई, परंतु उसके बाद 2021-22 और जांच अवधि में वृद्धि हुई है। 2020-21 के दौरान मांग में गिरावट कोविड-19 के कारण हो सकती है।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	46,202	40,906	69,292	81,388
थाईलैंड	एमटी	43,036	35,456	62,598	67,195
चीन	एमटी	92	1,360	3,943	8,339
कोरिया	एमटी	3,074	4,090	2,752	5,854
अन्य आयात	एमटी	14,003	17,041	9,192	4,822
कुल आयात	एमटी	60,205	57,947	78,484	86,210
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	0	0	0	***
मांग / खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	130	150
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	0	0	0	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध				100
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात:					
कुल आयात	%	77%	71%	88%	94%
मांग / खपत	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	115	118
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	100

92. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में 2020-21 में गिरावट आई परंतु उसके बाद 2021-22 तथा जांच अवधि में वृद्धि हुई।
- ख. आयातों में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों का जांच अवधि में भारत में खपत में लगभग *** प्रतिशत हिस्सा है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में उत्पादन शुरू किया है और उसके पास मांग के पर्याप्त हिस्से को पूरा करने की क्षमता थी।
- घ. आयातों की वर्तमान मात्रा देश में मांग – आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी अधिक है।
- ड. जांच अवधि से पहले संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं था। तथापि, जांच अवधि के दौरान भी घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग को उत्पादन शुरू करने के बावजूद 7 गुना से अधिक थी।
- च. संबद्ध देशों से आयात जांच अवधि में कुल आयातों के 94 प्रतिशत हैं।
- छ. आयातों ने संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि की दर की तुलना में काफी अधिक दर से वृद्धि हुई है। यद्यपि मांग में इस अवधि में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु संबद्ध आयातों में 76 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

93. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना और ट्रेड मैप द्वारा सत्यापित जानकारी भी दर्शाती है कि भारत में थाई उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जिसका उनके निर्यातों में *** प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, भारत चीन और कोरिया में उत्पादकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो दर्शाता है कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार है।

ज.3.5 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

94. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारित कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

95. कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ जांच अवधि के लिए आयातों की पहुंच मूल्य की तुलना द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित किया गया है। भारित औसत कीमत कटौती निम्नानुसार है। यह देखा गया है कि कीमत कटौती जांच अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी अधिक है।

विवरण	यूनिट	क्यू1	क्यू2	क्यू3	क्यू4	पीओआई
पहुंच कीमत	रु/एमटी	2,22,886	1,99,157	1,29,997	1,14,403	1,66,530
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	51	44	68

कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%	0-10%	0-10%	0-10%	5-15%

* आयातों की मात्रा पर आधारित तिमाही बिक्री कीमत का भारित औसत।

96. घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि आयातों की पहुंच कीमत अनुमानित बिक्री कीमत से कम है जबकि काफी उच्चतर कीमत कटौती हुई है। यदि घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत पर विचार किया जाए तो यह देखा जाएगा कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की लक्ष्य कीमत में कटौती कर रहे थे।

विवरण	यूनिट	पीओआई
पहुंच मूल्य	रु/एमटी	1,66,530
लक्ष्य कीमत	रु/एमटी	***
कीमत कटौती	रु/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

97. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी न्यूनीकरण करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई थी:

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4
बिक्रियों की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	106	104
बिक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	51	44
पहुंच कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	58	51

98. यह नोट किया गया है कि दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी गिरावट आई है। तत्पश्चात तीसरी और चौथी तिमाही में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में काफी उच्च दर पर रही है ताकि वह आयातों की पहुंच से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम रही है। इस प्रकार, यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू

उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है। आवेदक ने यह भी बताया है कि आयातों ने उन्हें उनकी परियोजना रिपोर्ट में यथा अनुमानित लक्ष्य कीमत प्राप्त करने से उन्हें रोका है और उन्हें संबद्ध वस्तु को उसकी लागत से कम पर बेचना पड़ा है।

ग) घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम पहुंच कीमत

99. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयातों की पहुंच कीमत में जांच अवधि के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत को कम कर दिया है। यह देखा गया है कि क्षति की आरंभिक अवधि के दौरान ईसीएच की कीमतें कच्ची सामग्री की लागत से काफी अधिक थीं। ईसीएच की कीमतों में 2022-23 के पूर्वार्ध में घटना शुरू कर दिया है जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू किया। तथापि पिछली दो तिमाहियों में आयातों की पहुंच कीमत प्रयुक्त कच्ची सामग्री की लागत से कम थी। जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग अपनी लागत वसूल करने में असमर्थ था, क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे ग्लिसरीन के बजाय रिफाइनड ग्लिसरीन का प्रयोग किया। यह दावा किया गया था कि घरेलू उद्योग ने कच्चे ग्लिसरीन जो अधिक लागत कुशल है, के बजाय उच्च कीमत के रिफाइनड ग्लिसरीन को खरीदा। इसके उत्तर में घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए कच्चे ग्लिसरीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रदान की कि ईसीएच की कीमत कच्चे ग्लिसरीन की कीमत से कम थी। यह नोट किया गया है कि थाईलैंड और चीन के उत्पादक भी रिफाइनड ग्लिसरीन के प्रयोग से ईसीएच का उत्पादन कर रहे हैं। फिर भी जैसा घरेलू उद्योग ने दर्शाया यदि कच्चे ग्लिसरीन की कीमत पर विचार भी किया जाए तो ईसीएच की कीमतों में भी समान रुझान दर्शाया है। यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत के ऊपर मार्क-अप जांच अवधि के पूर्वार्ध तक उचित था, परंतु घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू करते समय जांच अवधि के उत्तरार्ध में इसमें तेजी से गिरावट आई।

आंकड़े यूएस डॉलर / एमटी में

तिमाही	भारत में ईसीएच की आयात कीमत	कास्टिक सोडा कीमत	रिफाइनड ग्लिसरीन कीमत	रिफाइनड ग्लिसरीन की कीमत पर विचार करते हुए आरएम लागत	लागत पर मार्क-अप (ईसीएच कीमत - आरएम)	कच्चे ग्लिसरीन कीमत	कच्चे ग्लिसरीन पर विचार करते हुए आरएम	लागत पर मार्क-अप (ईसीएच कीमत - आरएम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20 क्यू1	1,608	239	711	800-850	750-800	259	425-475	1125-1175
2019-20 क्यू2	1,696	224	645	750-800	900-950	223	375-425	1275-1325
2019-20 क्यू3	1,786	214	638	725-775	1000-1050	233	375-425	1350-1400
2019-20 क्यू4	1,625	194	617	800-750	950-900	229	375-425	1200-1250
2020-21 क्यू1	1,512	200	692	750-800	700-750	252	400-450	1050-1100
2020-21 क्यू2	1,355	204	775	850-900	450-500	292	450-500	850-900
2020-21 क्यू3	1,286	191	712	800-850	450-500	289	450-500	800-850
2020-21 क्यू4	1,528	174	790	850-900	600-650	355	525-575	950-1000
2021-22 क्यू1	1,972	183	874	950-1000	950-1000	440	425-475	1275-1325
2021-22 क्यू2	2,338	212	1,036	1100-	1150-	568	375-425	1450-1500

				1150	1200			
2021-22 क्यू3	2,597	288	1,246	1375-1425	1150-1200	677	375-425	1550-1600
2021-22 क्यू4	2,645	390	1,574	1750-1800	850-900	757	375-425	1450-1500
2022-23 क्यू1	2,845	456	1,834	2050-2100	750-800	773	400-450	1575-1625
2022-23 क्यू2	2,548	485	1,730	1950-2000	550-600	732	1000-1050	1325-1375
2022-23 क्यू3	1,580	555	1,309	1575-1625	(50)-0	493	1150-1200	650-700
2022-23 क्यू4	1,379	530	1,051	1300-1350	50-100	351	1200-1250	650-700

100. परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी परिवर्तनशील लागत भी वसूल करने में असमर्थ रहा जिससे नकारात्मक अंशदान प्राप्त हुआ। *** रूपए/एमटी की परिवर्तनशील लागत के मुकाबले घरेलू उद्योग केवल *** रूपए/ एमटी की वसूल करने में सक्षम था।

ज.3.6 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

101. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

102. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे। यह नोट किया जा सकता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने 50,000 एमटी की क्षमता स्थापित की, परंतु वह अनुपातिक रूप से समायोजित हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने जून 2022 में प्रचालन शुरू किया।

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4	पीओआई	अनुमानित
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	300	300	300	300	300
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	0	168	113	254
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	36	0	56	38	85
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	445	309	760	484	2,903
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1144	117	103	439	
शट डाउन के दिन	दिनों की संख्या	***	***	***	***	***	***

103. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने पहली तिमाही में ही *** प्रतिशत का क्षमता उपयोग का तर्कसंगत रूप से उच्च स्तर प्राप्त कर लिया ताकि उसके बाद क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- ख. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका है और *** प्रतिशत की अनुमाति उपयोग के मुकाबले *** प्रतिशत से कम का उपयोग प्राप्त करने में सक्षम रहा था। घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित लगभग तीन चौथाई क्षमता जांच अवधि के दौरान बेकार रही है।
- ग. घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन अनुमानित उत्पादन के मुकाबले *** प्रतिशत कम रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां पूरी अवधि में कम रही हैं और अनुमानित बिक्री मात्रा का केवल *** प्रतिशत रही हैं।
- ड. घरेलू बिक्रियां क्षमता का केवल *** प्रतिशत रही हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन के केवल *** प्रतिशत की खपत करने में समर्थ रहा है।
- च. चूंकि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के निपटान में सक्षम नहीं रहा था। इसलिए उसे पर्याप्त अवधि के लिए अपना संयंत्र बंद रखना पड़ा था। जून 2022 में उत्पादन की शुरुआत से आवेदक को प्रचालनों की वाणिज्यिक अव्यवहार्यता के कारण काफी समय तक प्रचालन बंद रखने पड़े थे। उत्पादन शुरू करने के कुल *** दिनों में से घरेलू उद्योग 50 प्रतिशत से अधिक दिनों तक बंद रहा है।

104 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार पर फोकस किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग काफी अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ मौजूद है। अतः निर्यात करने के बाद भी घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार के बड़े हिस्से को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि इसका बाजार हिस्सा कम रहा है।

ख) बाजार हिस्सा

105. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	115	118
अन्य आयात	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	50	23
घरेलू उद्योग	%	-	-	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में उत्पादन शुरू किया है इसलिए उसके बाजार हिस्से में सुधार हुआ है। तथापि, संबद्ध आयातों के पास जांच अवधि के दौरान लगभग 90 प्रतिशत का बाजार हिस्सा रहा है जबकि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद थीं। आधे से ज्यादा मांग को पूरी करने की पर्याप्त क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल *** प्रतिशत था, जो *** प्रतिशत के अनुमानित बाजार हिस्से से काफी कम है।

ग) मालसूची

107. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4	पीओआई	अनुमानित
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	99	139	197	57

108. यह नोट किया गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, क्योंकि वे घरेलू बाजार में बिक्री करने में असमर्थ थे।
- ख. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची संबद्ध वस्तु के निर्यात करने के बावजूद उनकी कुल उत्पादन मात्रा के लगभग आधे के बराबर है।
- ग. इसके अलावा, मालसूची घरेलू बिक्री कीमतों के 91 प्रतिशत के बराबर है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग अपनी वस्तु को मुश्किल से बेच पा रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग की मालसूची धारक अवधि काफी अधिक है, जो घरेलू बिक्रियों के संबंध में एक वर्ष से अधिक और उत्पादन के संबंध में लगभग 6 माह के बराबर है।
- ड. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची जांच अवधि के प्रत्येक माह के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों से अधिक थी और एक महीने को छोड़कर पूरी अवधि में इसके प्रचालनों में उत्पादन से अधिक थी।
- च. औसत मालसूची अनुमानित मालसूची से उच्चतर क्षमता उपयोग के अनुमान के बावजूद काफी अधिक थी।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

109. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4
बिक्रियों की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	106	104

विक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	51	44
लाभ / (हानि)	रु/एमटी	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-47	-112	-132
लाभ / (हानि)	रु लाख	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-208	-344	-1007
नकद लाभ	रु लाख	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-110	-237	-638
निवेश पर आय	%	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-82	-229	-695

110. यह देखा गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग को आरंभ में पहली तिमाही में लाभ हुआ। तथापि, उसे आगे दूसरी तिमाही में भारी घाटा उठाना पड़ा और प्रत्येक तिमाही में उसके घाटों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के नकद लाभ पर निवेश पर आय ने समान रुझान अपनाया है। घरेलू उद्योग को भारी नकद घाटे उठाने पड़े हैं और निवेश पर उसकी आय दूसरी तिमाही में ऋणात्मक हो गई है।
111. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट पहुंच कीमत में गिरावट से सीधे प्रभावित हुई है। यह नोट किया गया है कि दूसरी तिमाही में और उसके बाद पहुंच कीमत और कच्ची सामग्री कीमत के बीच अंतर में तेजी से गिरावट आई। इसमें पहुंच कीमत बाद में कच्ची सामग्री की लागत से कम हो गई। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसमें तेजी से गिरावट आई।
112. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में भी उत्पादन शुरू किया। इसलिए उसके निष्पादन का विश्लेषण 80 प्रतिशत के उपयोग के लागत ढांचे पर विचार करते हुए अनुमानित निष्पादन के साथ तुलना करते हुए किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:

विवरण	यूनिट	पीओआई (वास्तविक)	अनुमानित	मानकीकृत
विक्रियों की लागत	रु/एमटी	***	***	***
विक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***
लाभ / (हानि)	रु/एमटी	***	***	***
लाभ / (हानि)	रु लाख	***	***	***
नकद लाभ	रु/एमटी	***	***	***
नकद लाभ	रु लाख	***	***	***
निवेश पर आय	%	(0-10)%	(10-20)%	(0-10)%

113. यह नोट किया गया है कि:

क. यद्यपि घरेलू उद्योग को जांच अवधि में *** करोड़ रूपए का लाभ होने का अनुमान था। उसे ऐसी अवधि

के दौरान *** करोड़ रूपए का भारी घाटा उठाना पड़ा। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग 80 प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता तब भी उसे वर्तमान कीमत पर घाटा उठाना पड़ता।

- ख. इसी प्रकार, घरेलू उद्योग को *** करोड़ रूपए का नकद घाटा हुआ है जबकि उसने *** करोड़ के नकद लाभ का अनुमान लगाया था। घरेलू उद्योग को 80 प्रतिशत के क्षमता का प्रचालन करने का भी भारी नकद घाटा उठाना पड़ेगा।
- ग. घरेलू उद्योग के निवेश पर आय *** प्रतिशत की अनुमानित आय के विपरीत ऋणात्मक रही थी।
- घ. घरेलू उद्योग ने यह भी दर्शाया है कि उसे जांच अवधि के चौथी तिमाही के दौरान अपनी परिवर्तनशील उत्पादन लागत से कम पर बिक्री करनी पड़ी थी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए लागत वसूल करना संभव हो गया था।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

114. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की निम्नानुसार जांच की है:

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
वेतन और मजदूरी	रु लाख	***	***	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	-	168	113
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	***	***	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/सं.	***	***	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	0	168	94

115. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या पूरी जांच अवधि में स्थिर रही है जबकि वेतन में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में दूसरी तिमाही में गिरावट आई और तीसरी तिमाही में वह शून्य था, क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपना प्रचालन बंद कर दिया था। तथापि, अंतिम तिमाही में उत्पादकता में सुधार हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन मात्रा बढ़ा दी। घरेलू उद्योग ने इस वजह से क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2022-23 क्यू1	2022-23 क्यू2	2022-23 क्यू3	2022-23 क्यू4
उत्पादन	%	-	8%	-100%	100%
घरेलू बिक्रियां	%	-	345%	-31%	146%
लाभ / हानि	%	-	-309%	-65%	-192%
लाभ / हानि प्रति यूनिट	%	-	-147%	-138%	-18%
नकद लाभ	%	-	-210%	-116%	-169%

निवेश पर आय	%	-	-182%	-179%	-204%
-------------	---	---	-------	-------	-------

116. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया। इसलिए तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद उसकी मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही में गिरावट आई है और किसी तिमाही में सुधार नहीं हुआ है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

117. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के लिए क्षमता स्थापित करने हेतु निवेश जुटाया और वह पूंजी निवेश जुटाने में सक्षम रहा। घरेलू उद्योग ने बताया है कि आयातों की मात्रा दिसंबर, 2023 तक घरेलू उद्योग द्वारा एक वर्ष से अधिक तक प्रचालन में रहने के बावजूद पीओआई के बाद की अवधि में उच्चतर बनी रही है। आयातों के निरंतर आने से घरेलू उद्योग घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है, जो कम रही हैं। इससे काफी अधिक मालसूची एकत्रित हो गई है जो प्रत्येक माह में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के स्तरों से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को पीओआई के बाद की अवधि में लगभग ढाई महीने का एक और शट डाउन करना पड़ा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को भारी घाटे होना, नकारात्मक नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी आय में नुकसान होना जारी है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने ध्यान दिलाया था कि घरेलू उद्योग को घाटा इस तथ्य के कारण हुआ था कि उसने जांच अवधि के एक हिस्से में रिफाईंड ग्लिसरीन के प्रयोग से समान वस्तु उत्पादित की है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि पीओआई के बाद की अवधि में उसने कच्चे ग्लिसरीन के प्रयोग से समान वस्तु उत्पादित की है। तथापि, फिर भी उसे भारी घाटे हुए हैं।

ज.3.7 क्षति का समग्र मूल्यांकन

118. विषय उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:

- घरेलू उद्योग द्वारा परिचालन शुरू करने के बावजूद आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयात में संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक दर से वृद्धि हुई।
- उत्पादन और खपत के संबंध में आयात अधिक रहा है।
- आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और कम कर दिया है, और घरेलू उद्योग को अपनी अनुमानित कीमतों को प्राप्त करने से रोका है।
- जांच की अवधि के दौरान विषय आयात की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित कीमतों को कम कर रहे थे।
- जांच की अवधि की अंतिम दो-तिमाहियों में आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम है।
- आयात की कीमत और कच्चे माल की कीमतों के बीच के अंतर में इस अवधि में तेजी से गिरावट आई है।
- सस्ते आयात के कारण, घरेलू उद्योग को इसकी बिक्री लागत और इसकी परिवर्तनीय लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का 30% से कम उपयोग करने में सक्षम रहा है, जो अनुमानित उपयोग से बहुत कम है।
- घरेलू उद्योग अपने उत्पादन संस्करणों के आधे से थोड़ा अधिक ही बेच पाया, वह भी कुछ संस्करणों का निर्यात करके। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग में घरेलू बिक्री की मात्रा कम बनी हुई है।
- घरेलू उद्योग को बाजार में वाणिज्यिक अव्यवहार्यता के कारण संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- xi. घरेलू उद्योग को अपने संचालन के पहले वर्ष में आविष्कारों के एक महत्वपूर्ण संचय का सामना करना पड़ा। जांच की अवधि के प्रत्येक महीने के दौरान इसकी इन्वेंट्री घरेलू बिक्री से अधिक थी।
- xii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता इस अवधि में बिगड़ गई, बढ़ते घाटे, नकद नुकसान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न के साथ।
- xiii. घरेलू उद्योग को अनुमानित लाभप्रदता के मुकाबले जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा।
- xiv. घरेलू उद्योग को मौजूदा कीमतों पर नुकसान, नकद नुकसान और नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ता, भले ही वह 80% क्षमता उपयोग पर संचालित होता।
- xv. आयात ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xvi. डंपिंग मार्जिन नकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xvii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग का निष्पादन POI के बाद की अवधि के दौरान भी प्रतिकूल बना हुआ है।

119. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विषय आयातों ने भारत में उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से मंद कर दिया है।

झ) गैर-आरोपण विश्लेषण

120. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से कोई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों से क्षति हो सकती है जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों से इतर केवल ताईवान से अधिक आयात हुए हैं और किसी अन्य गैर संबद्ध स्रोत से नहीं। तथापि, संबद्ध वस्तु को जांच अवधि के दौरान ताईवान से पाटित कीमत पर निर्यात नहीं किया गया था। इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए ताईवान से हुए आयात जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।

ख. मांग का संकुचन

122. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में केवल 2020-21 में मामूली गिरावट के अलावा निरंतर वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की मांग में आगे वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

123. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

124. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। चूंकि घरेलू उद्योग देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। इसलिए घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा की ऐसी

कोई संभावना नहीं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में आवेदक ने एक नई उत्पादन सुविधा स्थापित की है।

च. निर्यात निष्पादन

126. प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए उस सीमा तक अलग आंकड़ों पर भरोसा किया है, जिससे वह घरेलू उद्योग को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सही हो सकती हो।

छ. कच्ची सामग्री की मालसूची का प्रयोग

127. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने भी दलील दी है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम है, क्योंकि वह उच्च कीमत पर खरीदी गई कच्ची सामग्री की मालसूची का प्रयोग करता है। ऐसी दलील के उत्तर में घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित घरेलू उद्योग की लाभप्रदता से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। प्रदत्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर कच्ची सामग्रियां खरीदने पर भी घाटा उठाना पड़ता।

विवरण	यूनिट	वर्तमान निष्पादन	यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाए
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***
उत्पादन की लागत	रु/एमटी	***	***
बिक्री कीमत	रु/एमटी	***	***
लाभ / (हानि)	रु/एमटी	(***)	(***)
लाभ / (हानि)	रु लाख	(***)	(***)

ज. उत्पादन लागत पर स्टार्ट-अप लागत का प्रभाव

128. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत उसमें शामिल स्टार्ट-अप लागतों के कारण बढ़ी हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कोई स्टार्ट-अप लागत परिसंपत्तियों की लागत में प्रयोग हुई है और उत्पादन लागत में शामिल नहीं की गई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत किसी स्टार्ट अप लागत के कारण बढ़ाई नहीं गई है।

झ. उत्पाद की गुणवत्ता या स्वीकार्यता संबंधी मुद्दे

129. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद की लंबी अनुमोदन प्रक्रिया या स्वीकार्यता संबंध मुद्दों के कारण घरेलू बाजार में वस्तु को बेचने में संघर्ष किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजारों में वस्तु की आपूर्ति करने में समर्थ है और वह भी लाभप्रद कीमतों पर। अतः यह तथ्य कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजारों में अपनी वस्तु बेचने में सक्षम है। दर्शाता है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद वैश्विक रूप से स्वीकृत है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि वह आयात कीमतों से क्षतिकारी स्तरों तक गिरने से पहले भारत में उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु बेचने में सक्षम था।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

130. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की

गणना हेतु संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम तिमाहीवार उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाहीवार उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत और / या एनआईपी से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों और / या परिसंपत्तियों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के व्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली की अनुमति दी गई है।

131. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दर्शाने के लिए समायोजित करना चाहिए और रायल्टी व्ययों पर विचार नहीं करना चाहिए। तथापि, अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार और प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी ने कंपनी की बही खातों में यथा प्रदर्शित कच्ची सामग्री की लागत और अन्य व्ययों पर कानून में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विधिवत रूप से समायोजित रूप में विचार किया है।
132. चूंकि स्टार्ट अप लागत का पूंजीकरण हुआ है। इसलिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत इस वजह से नहीं बढ़ी है। मूल्यहास के संबंध में प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान प्राप्त 80 प्रतिशत से अधिक उच्चतम क्षमता के आधार पर उस पर विचार किया है।
133. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस तर्क के संबंध में कि क्षति मार्जिन के घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार केवल आयातों की क्षतिकारी मात्रा पर विचार करते हुए निर्धारित नहीं करना चाहिए। यह नोट किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए सभी आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित की है और क्षति मार्जिन की गणना के लिए घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के साथ उसकी तुलना की है।
134. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा तिमाहीवार आधार पर उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी	एलपी	आईएम	आईएम	रेंज
क	थाईलैंड	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	%	
1	एजीसी विनाइथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) (इसे पूर्व में एडवांस्ड बायोकेमिकल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	***	***	***	***	20-30%
2	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
ख	कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	
1	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	10-20%
2	लोटे फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
3	कोई अन्य	***	***	***	***	25-35%
ग	चीन जन. गण.	***	***	***	***	
1	जियांगसु रूईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
2	निंगबो इंगबोहुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***) %	ऋणात्मक
3	कोई अन्य	***	***	***	***	5-15%

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

135. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक ने अपनी गणना में इपोक्सी रेजिन के बाजार कीमत को अधिक बताकर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव की गलत गणना की है। इपोक्सी उत्पादकों पर प्रभाव 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और काफी अधिक है।
- ii. शुल्क लागू होने के संभावित परिणाम में इपोक्सी रेजिन के लिए विपरीत शुल्क संरचना हो जाएगी क्योंकि आयात मूल सीमा शुल्क के अधीन होंगे (जो ये भागीदारों के लिए शून्य है) जबकि भारत में इपोक्सी उत्पादक अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क के अधीन होंगे।
- iii. शुल्क लागू होने का प्रभाव इपोक्सी उद्योग और विभिन्न डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों जैसे पेंट और कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अधेसिव, जल उपचार रसायन, वस्त्र, पेपर उद्योग आदि के लिए हानिकारक हैं। इपोक्सी उत्पादक शुल्क लागू होने के कारण लागत में वृद्धि को झेल नहीं पाएंगे और उसे उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। इससे प्रयोक्ता उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- iv. शुल्क लागू होने से भारत में इपोक्सी के उत्पादन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह कुकडो केमिकल्स जो भारतीय इपोक्सी क्षेत्र में निवेश की योजना बना रहे हैं जैसे कंपनियों को रोक देगा।
- v. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से अपस्ट्रीम रिफाईंड ग्लिसरीन उद्योग की मांग और कीमतें नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई होंगी।
- vi. संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अंतिम प्रयोक्ता संबद्ध वस्तु का आयात करना पसंद करेंगे।
- vii. घरेलू उद्योग आवेदक और एक प्रयोक्ता के बीच गोपनीय पत्राचार के अनुसार प्रयोक्ताओं की मात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है।
- viii. वर्तमान में घरेलू मांग मौजूदा घरेलू उत्पादन क्षमता से पूरी नहीं हो सकती है।
- ix. मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत वर्तमान जांच के दायरे से बाहर हैं।
- x. केंद्रीय बजट 2023 में विशेष रूप से ईसीएच में प्रयोग के लिए कच्चे ग्लिसरीन के आयातों पर शुल्क रियायतें दी गई हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

136. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग, उपभोक्ताओं, प्रयोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता के हित में होगा।
- ii. ईसीएच के लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है क्योंकि देश तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रचालन रोकने के बाद से पूर्णतः आयातों पर निर्भर है।
- iii. घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार शुल्क लागू होने से जो अधिकतम कीमत वृद्धि होगी वह फिर भी पहले निर्यातकों द्वारा प्रभारित कीमतों से कम होगी। घरेलू उद्योग से उचित कीमत पर खरीदे गए ईसीएच से उपभोक्ताओं को कम से कम 185 करोड़ रूपए का लाभ होगा।
- iv. प्रयोक्ताओं ने स्वयं अपने लिखित अनुरोधों में माना है कि वे कीमत वृद्धि को केवल अंतिम उपभोक्ताओं

- पर डाल देंगे और परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव भी अंतिम उपभोक्ताओं पर नगण्य होगा।
- v. शुल्क लागू होने से भारत में ईसीएच के उद्योग की स्थापना में मदद मिलेगी जिससे अपस्ट्रीम उत्पादकों की मांग और कीमत में वृद्धि होगी और उन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - vi. कुकडो केमिकल्स आगे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए अपना संयंत्र स्थापित किया है और चूंकि आगामी इपोक्सी संयंत्र मौजूदा संयंत्र को कच्ची सामग्री देगा इसलिए शुल्क लागू होने से ऐसे निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - vii. आयातों के कारण इस समय देश में 1300 करोड़ रूपए से अधिक के नए निवेश की व्यवहार्यता को खतरा है और ऐसे भारी निवेश के संरक्षण की आवश्यकता है।
 - viii. कुकडो केमिकल्स के भावी निवेश पर विचार करते हुए 250 करोड़ रूपए के एफडीआई के संभावित निवेश के मुकाबले समान वस्तु के भारत में 1000 करोड़ रूपए के भारतीय निवेश का नुकसान होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
 - ix. छूट लागू होने के बाद भारतीय उद्योग के पास अगले पांच वर्षों में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं होंगी।
 - x. संबद्ध देशों के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ताइवान, जापान, नीदरलैंड, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली और चेक गणराज्य में उत्पादकों के पास काफी क्षमताएं हैं और यदि संबद्ध आयात तेजी से घटते हैं तो वे भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं भेजने में सक्षम हो सकते हैं।
 - xi. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग – आपूर्ति में अंतर शुल्क को लागू नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि एनओसीआईएल लिमिटेड बनाम भारत सरकार में उच्च न्यायालय, डीएसएम इंडेमिट्सु कं, लिमिटेड बनाम डीए में सेस्टेट और पूर्ववर्ती जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा माना गया है।
 - xii. शुल्क लागू होने से 639 लाख अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष के विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
 - xiii. इस प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग की मौजूदगी से यह सुनिश्चित हुआ कि निर्यातक भारतीय उपभोक्ताओं से अधिक कीमत नहीं लेंगे जो पहले किया गया था जैसा कि कच्ची सामग्री की लागत से अधिक कीमत लेने से स्पष्ट है।
 - xiv. घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकारी व्यवहार की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय बाजार शुल्क लगने के समय तक अति आपूर्ति की स्थिति में आ सकता है।
 - xv. घरेलू उद्योग बायो आधारित ग्लिसरीन तरीके के प्रयोग से ईसीएच का उत्पादन करता है। दो पारंपरिक प्रोपीलीन तरीके की तुलना में पर्यावरण के लिए बेहतर है।
 - xvi. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, प्रतिकूल शुल्क संरचना है जिस पर वर्तमान जांच में विचार नहीं किया गया है।
 - xvii. इपोक्सी रेजिन के आयातों की मात्रा वर्तमान में काफी कम है। कुकडो केमिकल्स के पास आयातों का अधिकांश हिस्सा है जो स्वयं भारत में इपोक्सी रेजिन का संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिसके परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में और गिरावट हो जाएगी।
 - xviii. शुल्कों का लागू होना प्रयोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि शुल्क लागू होने से आयात कीमत में वृद्धि संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य से कम होगी।
 - xix. अंतिम प्रयोक्ताओं ने केवल इसलिए घरेलू वस्तु की तुलना में संबद्ध आयातों को पसंद किया है, क्योंकि संबद्ध आयात सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है।
 - xx. आवेदक ने सरकार की मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियों के समर्थन में केवल शुल्क लागू

करने का दावा नहीं किया है, बल्कि ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है और इस प्रकार भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा देना है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने को मनमाने ढंग से संबद्ध देशों से आयातों से कटौती के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण इन उपायों के जारी रहने से अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा कम होने के बजाय पाटनरोधी उपाय लागू होने से पाटन की प्रथाओं के कारण अनुचित लाभ समाप्त होंगे। यह उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प देकर उनका संरक्षण करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क उचित व्यापार प्रक्रिया में एक बाधा के बजाय सुविधा प्रदाता है।
138. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच अधिसूचना जारी की थी। घरेलू उद्योग, उत्पादक / निर्यातक और आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी विहित की गई थी।
139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके द्वारा जारी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग द्वारा असंबद्ध वस्तु के 4 प्रयोक्ताओं अर्थात् अतुल लिमिटेड, कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लागू होने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में घरेलू उद्योग से उचित कीमत पर ईसीएच खरीदने से प्रयोक्ताओं को 185 करोड़ रूपए का लाभ होगा। दूसरी ओर प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि शुल्क लागू होने से उनकी लागत पर 10 प्रतिशत तक का प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं ने स्वयं माना है कि वे किसी कीमत वृद्धि को डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर डाल देंगे। अतः इपोक्सी रेजिन पर शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताना उचित नहीं होगा। इपोक्सी रेजिन के उत्पादक विभिन्न प्रकार के डाउनस्ट्रीम उद्योगों जैसे पेंट, अधेसिव, लेमिनेट, ऑटोमोटिव कोटिंग्स आदि की जरूरतें पूरी करते हैं जिन्हें आगे उनके डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि प्रयोक्ताओं पर डाली जाने वाली किसी कीमत वृद्धि से अंततः अंतिम उपभोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र स्थापित करने से पहले भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर था। यद्यपि तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 2010 की शुरुआत में एक संयंत्र स्थापित किया, परंतु सस्ते आयातों के कारण वह बंद हो गया। यह बात घरेलू उद्योग द्वारा उसके वित्तीय विवरणों में दिए गए ब्यौरे से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने जोर दिया है कि यदि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहता है तो उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि शुल्क लागू होने से भारत में इपोक्सी उद्योग में विदेशी उत्पादकों के निवेश हतोत्साहित होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में केवल कुकडो केमिकल्स ने लगभग *** करोड़ रूपए के निवेश पर भारत में अपने डाउनस्ट्रीम संयंत्र को फीड करने के लिए भारत में इपोक्सी रेजिन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषित की है। दूसरी ओर भारतीय उद्योग ने पहले ही ईसीएच के लिए संयंत्र स्थापित करने हेतु भारी निवेश किया है। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग ने पहले ही *** करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया है। अतः पहले से किए गए इतने भारी निवेश के संरक्षण की जरूरत है। यह नोट किया गया है कि भारत ने भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए भारी निवेश को भावी विदेशी निवेशों की प्रत्याशा में छोड़ा नहीं जा

सकता है।

142. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से भारत में संबद्ध वस्तु की कमी नहीं होगी। यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क लागू होने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी तरह घरेलू उद्योग की आगामी क्षमता भारत में मांग से अधिक होगी और इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।

कुल भारतीय क्षमता	एपिग्रल लिमिटेड	50 केटी
	डीसीएम श्रीराम	51 केटी
	ग्रासिम	50 केटी
कुल मांग		90 केटी
अधिक आपूर्ति		11 केटी

घरेलू उद्योग ने ध्यान दिलाया है कि भारतीय उद्योग के पास न केवल वर्तमान बल्कि देश की भावी मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त क्षमता होगी।

143. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। तथापि यह देखा गया है कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। किसी भी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ताइवान, जापान, नीदरलैंड, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली और चेक गणराज्य जैसे देशों के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं और प्रयोक्ता ऐसे देशों से संबद्ध वस्तु का आयात कर सकते हैं।
144. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं की मात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग का पत्र प्रस्तुत किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि यद्यपि उसने प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु बेचने का ऑफर दिया है, परंतु उन्होंने घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु खरीदने से इंकार किया है, क्योंकि वे सस्ती आयातित वस्तु पसंद करते हैं जिसकी कीमत की बराबरी घरेलू उद्योग नहीं कर सकता था।
145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि शुल्क लागू होने से अपस्ट्रीम उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से ईसीएच के घरेलू उद्योग को फलने-फूलने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, अपस्ट्रीम उद्योग में मांग बढ़ेगी, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार किसी भी स्थिति में शुल्क लागू होने से अपस्ट्रीम उद्योग प्रभावित नहीं होंगे।
146. अंत में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क ऐसी कीमत तक सीमित होगा जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करेगी। ऐसे मामले में वह वर्तमान कीमत जिस पर इपोक्सी के उत्पादक विदेशी निर्यातकों से संबद्ध वस्तु का आयात कर रहे हैं, उस कीमत से कम बनी रहेगी, जिस पर विदेशी उत्पादक अपने घरेलू बाजार में बिक्री कर रहे हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी भारतीय बाजार में ईसीएच की कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से कम होंगी। इससे भारत में इपोक्सी उत्पादकों को उनके वैश्विक समकक्षों की तुलना में एक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा।

ठ. प्रकटन पश्चात की टिप्पणियां

147. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को 12 जुलाई 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उनके संगत समझे जाने की सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्ववर्ती अनुरोध का पुनः प्रस्तुतीकरण था और जिसकी प्राधिकारी ने पर्याप्त रूप से

जांच कर ली थी, को संक्षिप्तता के लिए यहां दोहराया नहीं गया है।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

148. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयात मात्राओं और लाभों में विसंगतियां हैं और उन पर प्रकटन विवरण में भरोसा किया गया है।
- ii. यद्यपि मात्रात्मक प्रभाव पर वार्षिक आधार पर जांच की गई है। तथापि, कीमत प्रभाव के तिमाही आधार पर विश्लेषित किया गया है। आयातों में तिमाही 1 के बाद गिरावट आई है।
- iii. जांच अवधि के दौरान कीमतों में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है जो उसे अप्रतिनिधि बनाती है, जो सामान्य बाजार अस्थिरता से अलग है।
- iv. प्राधिकारी को केवल जांच की अवधि की तिमाही 2 और तिमाही 3 में की गई घरेलू बिक्री के लिए व्यापार परीक्षण के सामान्य पाठ्यक्रम को करने के लिए POI के उत्पादन की समग्र लागत पर विचार करना चाहिए, न कि जांच की अवधि के दौरान की गई सभी बिक्री के लिए। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यदि माननीय प्राधिकरण पीओआई की तिमाही 2 और तिमाही 3 में की गई घरेलू बिक्री के लिए केवल समग्र लागत लागू करने के लिए असंगत पाता है, तो हम संबंधित तिमाही के लिए उत्पादन की लागत पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। यदि ऐसी बिक्रियों पर विचार नहीं किया जाता तो सामान्य मूल्य उत्पादन लागत जमा लाभ के रूप में 5 प्रतिशत पर आधारित होना चाहिए।
- v. कारखानाद्वारा निर्यात कीमत में जियांग्सू रुईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा यथा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा यथा स्वीकृत रूप में विसंगति प्रतीत होती है।
- vi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन का चुनिंदा रूप से विश्लेषण किया है जिसमें ऐसे मापदंड मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं, जहां निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव है। जबकि अन्य न्यूनकारी कारकों की अनेदखी की गई है।
- vii. वास्तविक मंदी की जांच में अनुमानित निष्पादन की तुलना शामिल नहीं होनी चाहिए।
- viii. प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष के लिए मोरक्को मामले में विभिन्न निर्धारित मापदंडों की जांच नहीं की है कि घरेलू उद्योग वास्तविक रूप से बाधित था।
- ix. कच्ची सामग्री को स्थिर संविदागत करारों के अंतर्गत खरीदा गया है और इस प्रकार निर्यातकों की लागत को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन दर्शाने में थोड़ा समय लगेगा।
- x. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक विवरण में स्वीकार किया है कि वह मौजूदा दीर्घावधिक संविदाओं के कारण बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ है।
- xi. अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत में उतार-चढ़ाव पर क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए विचार करना चाहिए। इसके अलावा, 22 प्रतिशत की आय पर विचार नहीं करना चाहिए।
- xii. प्राधिकारी को तिमाहीवार क्षतिरहित कीमत की गणना करनी चाहिए और उसके बाद भारित औसत क्षतिरहित कीमत और पहुंच कीमत की तुलना भारित औसत कुल आयात मात्रा के साथ करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन घट जाएगा।
- xiii. संबद्ध देशों पर शुल्क लगाने से ईसीएच की कीमत कम हो जाएगी और गैर संबद्ध देशों से निर्यातक प्रतिस्पर्धी कीमतें देकर ऐसे लाभ से वंचित कर सकते हैं।

- xiv. प्राधिकारी की समुक्तियों के विपरीत पीएपीएल ने अपने प्रचालन बंद कर दिए थे, क्योंकि उसके डाउनस्ट्रीम खरीददार पीएपीएल ने खराब निष्पादन के कारण उत्पादन बंद कर दिया था।
- xv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट अस्थायी है क्योंकि बायो ग्लिसरीन की आपूर्ति आगामी वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लागत में कमी आएगी।
- xvi. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पीओआई के बाद की अवधि में काफी सुधार हुआ है जिसमें क्षति का अभाव है।
- xvii. घरेलू उद्योग को कच्चे ग्लिसरीन के आयातों पर प्रदत्त शुल्क और कीमतों तथा कच्चे ग्लिसरीन के आयात के कारण ब्यौरे उपलब्ध कराने चाहिए।
- xviii. प्रयोक्ता अन्य देशों में उच्च उत्पादन लागत, उच्च परिवहन लागत, लंबी पारगमन अवधि, सीमा शुल्क के कारण उच्चतर पहुंच लागत और उच्च मालसूची लागत के कारण निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोक्ताओं के साथ अपने स्रोतों को नहीं बदल सकते हैं।
- xix. शुल्क लागू होने से चीन के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ जाएगा।
- xx. कम विनियमित माहौल में घरेलू उत्पादन में वृद्धि सतत पोषणीयता के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

149. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन से असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को कम से कम असहयोगी से अन्य संबद्ध देशों के स्तर पर परिकलित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे निर्यातकों द्वारा भागीदारी नहीं करने को पुरस्कृत नहीं किया जाए।
- ii. क्षतिरहित कीमत की गणना के प्रयोजनार्थ कच्ची सामग्री की लागत के निर्धारण का तरीके पर पुनर्विचार और उसकी समीक्षा की जाए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 150. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां ऐसे अनुरोधों का दोहराव है जिनकी पहले ही अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उपयुक्त जांच और पर्याप्त समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां / अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
- 151. घरेलू उद्योग द्वारा चीन के असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुनः गणना से संबंधित अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मार्जिनों का निर्धारण किया है। यह भी नोट किया गया है कि चीन से आयातों की कीमत थाईलैंड और कोरिया गणराज्य से आयातों की कीमतों से भी अधिक है। इसके मद्देनजर यह तर्कसंगत है कि चीन के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन थाईलैंड और कोरिया गणराज्य में उत्पादकों से कमतर होगा।
- 152. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत की क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए पुनर्विचार और पुनः समीक्षा की जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की लागत नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की गई है।
- 153. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयातों के ब्यौरे प्राप्त किए और उन पर भरोसा किया जिनमें आवेदक के दावे से अलग मात्राएं दर्शाई जा सकती हैं। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आर्थिक मापदंडों की जांच में सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। आवेदकों के दावे के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा यथा विचारित आर्थिक मापदंडों में कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है।

154. इस दलील के संबंध में कि आयातों की मात्रा वर्षवार आधार पर विश्लेषित की गई है जबकि कीमत प्रभाव तिमाही आधार पर विश्लेषित किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू कीमतों पर आयातों के कीमत प्रभाव की जांच करने के लिए एक तिमाहीवार विश्लेषण किया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग केवल जांच अवधि के दौरान प्रचालन में था। दूसरी ओर संबद्ध आयात संपूर्ण क्षति अवधि में देश में प्रवेश कर रहे थे।
155. निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में एवीटी द्वारा तर्कों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अवहेलना की गई बिक्री समझौते के अनुच्छेद 2.2.1 के प्रावधानों के अनुरूप है। यह ध्यान दिया जाता है कि घाटे में चल रही बिक्री जिसकी अवहेलना की गई थी, एक विस्तारित अवधि में की गई थी। इसके अलावा, अनुच्छेद 2.2.1 के फुटनोट 5 में यह प्रावधान है कि प्रति यूनिट लागत से नीचे की बिक्री पर्याप्त मात्रा में की जाती है जब अधिकारी यह स्थापित करते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचाराधीन लेनदेन का भारित औसत बिक्री मूल्य प्रति यूनिट लागत भारित औसत से नीचे है, या प्रति यूनिट लागत से नीचे बिक्री की मात्रा विचाराधीन लेनदेन में बेची गई मात्रा के 20 प्रतिशत से कम नहीं का प्रतिनिधित्व करती है सामान्य मूल्य का निर्धारण। वर्तमान मामले में, घाटे में चल रही बिक्री तिमाहियों के दौरान बिक्री की कुल मात्रा के 20% से कम नहीं है। इस प्रकार, ऐसी बिक्री व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं पाई गई और इसकी अवहेलना की गई।
156. इसके अलावा, प्राधिकरण ने निर्यातक के इस तर्क की भी जांच की है कि पीओआई के उत्पादन की समग्र लागत पर केवल जांच की अवधि की तिमाही 2 और तिमाही 3 में की गई घरेलू बिक्री के लिए व्यापार परीक्षण के सामान्य पाठ्यक्रम के निष्पादन के लिए विचार किया जाना चाहिए न कि जांच की अवधि के दौरान की गई सभी बिक्री के लिए। प्राधिकरण नोट करता है कि इस तरह का दृष्टिकोण प्रकृति में चयनात्मक होने के कारण अनुचित होगा। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि कीमतों में गिरावट के साथ-साथ इस अवधि में कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसलिए, दृष्टिकोण की निरंतरता सुनिश्चित करने के मद्देनजर, प्राधिकरण ने प्रत्येक तिमाही में कीमतों की तुलना सभी निर्यातकों के लिए उसी तिमाही की लागत से की है, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या बिक्री व्यापार के सामान्य क्रम में की गई थी। प्राधिकरण पहले से निर्धारित पाटन माजन में कोई संशोधन करना उपयुक्त नहीं समझता है।
157. इस दलील के संबंध में कि एवीटी के लिए क्यू2 और क्यू3 के लिए सामान्य मूल्य को 5 प्रतिशत के तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए, यह देखा गया है कि निर्यातक ने 5 प्रतिशत लाभ मार्जिन पर विचार करने की तर्कसंगतता के संबंध में कोई कारण या औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने इसी समय अवधि में की गई संबद्ध वस्तु की बिक्री के संबंध में स्वयं निर्यातक द्वारा अर्जित लाभ पर विचार किया है जिसे अतर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधानों में व्यवस्था है कि जब निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्रियां न हों तो सामान्य मूल्य को उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग्य जोड़ करके उसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधान यह परिभाषित नहीं करते कि इस संबंध में, कितने लाभ मार्जिन को तर्कसंगत माना जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां लाभप्रद बिक्रियों की मात्रा 80 प्रतिशत से कम होगी, परंतु 20 प्रतिशत से अधिक होगी, वहां सामान्य मूल्य प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार केवल लाभप्रद बिक्रियों की कीमत पर आधारित होगा। लाभप्रद बिक्रियों की कीमत अनिवार्य रूप से उत्पादन लागत जमा लाभप्रद बिक्रियों पर लाभ मार्जिन के बराबर होनी चाहिए। तथापि, केवल इसलिए कि लाभप्रद बिक्रियों की मात्रा 20 प्रतिशत से कम है। यह नहीं माना जा सकता है कि लाभप्रद बिक्रियों का लाभ मार्जिन सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अब उचित बेंचमार्क नहीं है। ऐसी स्थिति में 5 प्रतिशत के बेंचमार्क पर विचार करने का कारण अर्थ ऐसे उत्पादक के साथ और अधिक अनुकूल व्यवहार करना होगा जिसकी लाभप्रद बिक्रियों की मात्रा (अर्थात् कुल मात्रा का 20 प्रतिशत

से कम) की तुलना में लाभप्रद बिक्रियों की उच्चतर मात्रा वाले उत्पादक (अर्थात् कुल बिक्री के 20 प्रतिशत से अधिक) से अधिक अनुकूल होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि इन दो तिमाहियों में लाभप्रद बिक्रियों पर अर्जित लाभ मार्जिन को क्यों अतर्कसंगत माना जाना चाहिए। इसके विपरीत प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि की शेष तिमाही में अर्जित लाभ मार्जिन जहां बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, क्यू1 में *** प्रतिशत और क्यू4 में *** प्रतिशत से भी अधिक था। दो तिमाहियों में अर्जित उच्चतर लाभ मार्जिन के मद्देनजर जहां सामान्य मूल्य बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि क्यू3 में *** प्रतिशत और क्यू4 में *** प्रतिशत मात्र का लाभ मार्जिन, तर्कसंगत है।

158. प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव के लिए आवश्यक समायोजन के बाद घरेलू उद्योग के अनुमानों पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी की प्रक्रिया वास्तविक बाधा के मामलों में अनुमानित निष्पादन के साथ घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर विचार करने और उससे तुलना की रही है। ऐसी कोई तुलना प्राधिकारी की जांच के दायरे से बाहर नहीं जाती है।
159. इस दलील के संबंध में कि प्राधिकारी ने केवल चुनिंदा रूप से क्षति मापदंडों का विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपनी क्षति जांच में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के प्रावधानों के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रत्येक मापदंड की जांच की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी विशिष्ट मापदंड की पहचान नहीं की है, जिसका प्रकटन विवरण में विश्लेषण नहीं किया गया है।
160. इन दावों के संबंध में कि आयातों की मात्रा तिमाही आधार पर तुलना के समय घट गई है। प्राधिकारी पाते हैं कि यह स्पष्ट है कि आयातों की मात्रा किसी नए उत्पादक के बाजार में प्रवेश करने पर नियंत्रित होती है। इसके अलावा, कतिपय तिमाही में आयातों में गिरावट के बावजूद जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा फिर भी पूर्ववर्ती वर्ष से अधिक थी जबकि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई। इस प्रकार, यद्यपि घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग की वृद्धि बाजार में आयातों की भारी मात्रा की मौजूदगी के कारण बाधित हुई थी।
161. इस दलील के संबंध में वैश्विक बाजार कीमतें घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है जो उच्चतर लागत पर रिफाईंड ग्लिसरीन का आयात करता है। यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड से निर्यातक भी अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कच्ची ग्लिसरीन से रिफाईंड ग्लिसरीन निकालने के बजाय रिफाईंड ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उत्पादन की उच्चतर लागत का निर्यातक की लागत और कीमत पर भी समतुल्य प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके अलावा, नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार एनआईपी निर्धारित की गई है।
162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहुंच कीमत के साथ कच्चे ग्लिसरीन के उपयोग पर विचार करते हुए उत्पादन लागत की तुलना के तर्क के बारे में निर्यातक ने दावा किया है कि चूंकि उन्होंने संविदागत दायित्वों के अंतर्गत उच्च लागत पर कच्ची सामग्री खरीदी है। इसलिए उनकी उत्पादन लागत और परिणामी कीमत समय के साथ कम होगी और इसका प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देगा। तथापि, दूसरी ओर निर्यातक ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग को उच्च लागत पर ग्लिसरीन खरीदने के कारण क्षति हुई है जिसकी वजह से उत्पादन की लागत अधिक हो गई है। अतः दूसरी ओर यद्यपि निर्यातक व्यावसायिक वास्तविकता का उल्लेख कर रहा है परंतु दूसरी ओर वह ऐसी स्थिति के घरेलू उद्योग की ओर से गलत खरीद के निर्णय के रूप में दावा कर रहा है। जहां मार्जिन को कीमतों की तुलना के आधार पर निर्धारित किया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने क्यू1 और क्यू4 में भी पाटन दर्शाया है। यदि कीमतों में कच्ची सामग्री की कीमत में बदलाव को दिखाने में समय लगता है तो यह बात घरेलू बाजार और निर्यात बाजार दोनों के लिए सही होनी चाहिए। तथापि, वर्तमान मामले में यह सही नहीं है।
163. इस दावे के संबंध में कि बाजार में किसी नए उत्पादक को स्थिर होने में पर्याप्त समय लगता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपने प्रचालन के पहली तिमाही के दौरान उच्च क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था।

तथापि, उसके बाद घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई, जो यह दर्शाता है कि उसे पाटित आयातों की भारी मात्रा की मौजूदगी के कारण अपने प्रचालनों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा और आरंभिक प्रचालनात्मक अक्षमताएं इसका कारण नहीं हैं।

164. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को मौजूदा संविदाओं और सैंपलिंग / गुणवत्ता अनुमोदनों में समय लगने के कारण कम बिक्री और क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग का खराब निष्पादन ऐसे अन्य कारकों की वजह से था।
165. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक निर्यातक ने यह दावा किया है कि प्राधिकारी ने गलत ढंग से यह माना है कि तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सस्ते आयातों के कारण प्रचालन बंद कर दिये हैं और ऐसा त्रुटिपूर्ण अवलोकन जांच को संदिग्ध बना देता है। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि ईसीएच के पूर्ववर्ती उत्पादक ने सस्ते आयातों से इतर कारणों से प्रचालन बंद किए थे। दूसरी ओर तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि ईसीएच के प्रचालन सस्ते आयातों के मौजूदगी के कारण बंद हुए थे।
166. इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक बाधा विश्लेषण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन मापदंडों पर भरोसा किया गया है और उसका प्रकटन नहीं हुआ है, यह नोट किया गया है कि ऐसी सूचना गोपनीय प्रकृति की है और उसका प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है जो अनुरोध करने वाले पक्षकार के लिए हानिकारक है।
167. इस दावे के संबंध में इपोक्सी उद्योग को शुल्क लगने के कारण नुकसान हुआ। चूंकि संबद्ध देशों से ईसीएच के कम कीमत के आयातों के कारण प्राप्त कोई लाभ गैर संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा शून्य किया जा सकता है जो प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रस्तुत कर सकते हैं, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में संबद्ध देश वैश्विक रूप से ईसीएच के प्रमुख निर्यातक हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों ने भारत की तुलना में तीसरे देशों को उच्चतम कीमतों पर ईसीएच का निर्यात किया है और इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तीसरे देशों में इपोक्सी के उत्पादक भी उच्चतर कीमतों पर ईसीएच प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध देशों में भी भारत को इपोक्सी के प्रमुख निर्यातक हैं और ऐसे देशों में इपोक्सी के उत्पादक भारत को ईसीएच के निर्यात की कीमत से उच्चतर कीमत पर ईसीएच प्राप्त कर रहे हैं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक पाया गया है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों में ईसीएच की कीमतें उन कीमतों से अधिक हैं जिन पर इनका भारत को निर्यात किया गया है। चूंकि शुल्क की राशि पाटन के मार्जिन से अधिक नहीं होती है। इसलिए शुल्क लगने के बाद भी भारत में ईसीएच की कीमतें संबद्ध देशों की तुलना में उच्चतर होंगी। इस प्रकार, भारत में इपोक्सी उद्योग के लिए उपलब्ध लाभ गैर संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा शून्य किए जाने की संभावना नहीं है।
168. इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी ने तुर्की से कतिपय हॉट रोलड स्टील संबंधी मोरक्को – पाटनरोधी उपायों में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा निर्धारित मापदंडों की जांच नहीं की है। यह नोट किया जाता है कि इस पैनल ने ऐसे मापदंडों के लिए केवल दिशानिर्देश निर्धारित किए जिन पर जांचकर्ता प्राधिकारी वास्तविक बाधा की जांच करते समय विचार कर सकते हैं। तथापि, पैनल ने यह समुक्ति की थी कि अनुच्छेद 3.1 यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति विहित नहीं करता है कि क्या कोई उद्योग स्थापित हो गया है और प्राधिकारी के लिए किसी तर्कसंगत पद्धति का प्रयोग करने की अनुमति है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कोई मापदंड मुख्य रूप से नहीं दर्शाए हैं जो यह संकेत करते हो कि घरेलू उद्योग स्थापित था और इस प्रकार उसे वास्तविक बाधा नहीं हुई।
169. इस दावे के संबंध में कि जियांग्सू रुईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना से अलग है। प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए निर्धारित निर्यात कीमत संशोधित की है। अद्यतन निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को यहां नीचे तालिका में शामिल किया गया है।

170. घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण से संबंधित तर्कों और ऐसे निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत की आय पर विचार करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत प्राधिकारी की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित की गई है और तदनुसार, क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।
171. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लागू होने से चीन के साथ व्यापारिक तनाव में वृद्धि होने की संभावना है। यह नोट किया गया है कि भारत और चीन दोनों डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और सीएटी के हस्ताक्षरकर्ता हैं और जीएटी तथा संबंधित करारों के हस्ताक्षरकर्ता हैं जिनमें पाटनरोधी करार भी शामिल है। इस प्रकार, पाटनरोधी करार के प्रावधान के अनुपालन में की गई किसी कार्रवाई से किसी व्यापार तनाव की शुरुआत होने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

172. सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:
- चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एपिक्लोरोहाइड्रिन ("ईसीएच") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन एपिग्रल लिमिटेड (जिसे पहले मेघमनि फाइनकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा दायर किया गया है।
 - विचाराधीन उत्पाद एपिक्लोरोहाइड्रिन है जो एक रंगहीन तरल होता है जिसमें 99 प्रतिशत की अधिक की शुद्धता होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः इपोक्सी रेजिन बनाने में होता है और इसका प्रयोग भेषज एपीओ, जल उपचार, पेपर रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फैक्टेंट, अधेसिव, इलास्टोमर्स, प्लास्टिक और रबड़ और कागज में एक मजबूतीवर्धक के रूप में भी किया जाता है।
 - आवेदक ने आयातित विचाराधीन वस्तु के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
 - आवेदक देश में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। आवेदक ने संबद्ध वस्तु के लिए एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है और उसके प्रचालन जांच अवधि के दौरान स्थिर नहीं हुए हैं। इस प्रकार आवेदक एक स्थापित उद्योग है और नियमावली के नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग है।
 - अन्य उत्पादक डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और ग्रासिम लिमिटेड संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन क्षमताओं की स्थापना की प्रक्रिया में हैं।
 - संबद्ध देश के उत्पादक भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं।
 - संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद ये अधिकतम रहे हैं। आयातों का देश में कुल आयातों में 94 प्रतिशत हिस्सा है और ये मांग – आपूर्ति के अंतर से अधिक रहे थे।
 - भारत थाईलैंड में निर्यातकों के सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में निर्यातकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था जो दर्शाता है कि भारत संबद्ध देशों में निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार है।
 - संबद्ध आयात जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। वास्तव में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत से भी कम कीमत पर हैं जिसने घरेलू उद्योग को अपनी लक्षित कीमत तक पहुंचने से रोका है।
 - आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण हुआ है।

- xii. आयातों की पहुंच कीमत कच्ची सामग्री लागत से भी कम थी जिसमें निर्यात कीमत का अंकित मूल्य कच्ची सामग्री की तुलना में जांच अवधि के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने पर कटौती कर रहा था।
- xiii. घरेलू उद्योग अपनी परिवर्तनशील लागत की वसूली करने में असमर्थ था जिसकी वजह से जांच अवधि के हिस्से के दौरान ऋणात्मक अंशदान हुआ।
- xiv. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में संबद्ध आयातों की वजह से भारत में नए उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा हुई है। इस संबंध में, निम्नलिखित बातें संगत हैं:
- क. यद्यपि घरेलू उद्योग ने पहली तिमाही में उच्च क्षमता उपयोग हासिल किया है, उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और उसकी लगभग तीन चौथाई क्षमता बेकार पड़ी रही है।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्रियां काफी कम रहीं और अनुमानित उत्पादन और बिक्रियों से कम रहीं।
- ग. चूंकि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का निपटान करने में असमर्थ था। इसलिए उसे जांच अवधि के दौरान अपनी कुल प्रचालन अवधि के 50 प्रतिशत में अपने संयंत्र को बंद रखना पड़ा था।
- घ. घरेलू उद्योग कुल मांग के 4 प्रतिशत के थोड़े के हिस्से को पूरा करने में समर्थ था जबकि उसके पास भारी अप्रयुक्त क्षमता थी और आयातों का बाजार हिस्सा 90 प्रतिशत रहा है।
- ड. परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को मालसूची एकत्रित होने का सामना करना पड़ा, जो उसके उत्पादन का लगभग आधा थी और घरेलू बिक्रियों के 128 प्रतिशत के बराबर थी। इसके अलावा, उसके पास मालसूची प्रचालन के प्रत्येक महीने में मासिक बिक्री से अधिक थी।
- च. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में संपूर्ण जांच अवधि में गिरावट आई और उसे भारी घाटा और नकद घाटा झेलना पड़ा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को दूसरी तिमाही से अपने निवेश पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई। यह घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित लाभों के विपरीत है।
- छ. इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग वर्तमान कीमतों पर 80 प्रतिशत उपयोग पर कार्य करता तो भी उसे भारी घाटा उठाना पड़ता।
- ज. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ, परंतु उसके लाभप्रदता मापदंडों में प्रत्येक तिमाही में गिरावट आई।
- झ. झेले गए भारी घाटों और अर्जित नकारात्मक आय के कारण संबद्ध आयातों में पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।
- xv. उक्त पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा का सामना करना पड़ा है।
- xvi. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना से पता चलता है कि क्षति मार्जिन एक को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादी निर्यातकों के लिए काफी अधिक और सकारात्मक है।
- xvii. जांच से ऐसे किसी अन्य कारक का पता नहीं चला है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xviii. पाटनरोधी शुल्क व्यापक जनहित में होते हैं जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:-
- क. भारतीय उद्योग ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संबद्ध वस्तु के विनिर्माण हेतु भारी निवेश किया है।

- ख. भारतीय उद्योग द्वारा किए गए भारी निवेश के संरक्षण की आवश्यकता है।
- ग. शुल्क लागू होने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- घ. शुल्क लागू होना प्रयोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि शुल्क लागू होने के बाद आयात कीमत में वृद्धि फिर भी संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य से कम होगी।
- ड. ईसीएच के उत्पादक को पहले ही सस्ते आयातों के कारण अपने प्रचालनों को बंद करना पड़ा था।
- च. एक बार अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन शुरू करने पर संबद्ध वस्तु के लिए देश में मांग – आपूर्ति का कोई अंतर नहीं होगा।
- छ. संबद्ध वस्तु अन्य देशों से प्रतिस्पर्धी कीमत पर आयातित की जा सकती है।
- ज. बाजार में 3 उत्पादकों की मौजूदगी से यह सुनिश्चित होगा कि उद्योग के लिए एकाधिकार न बने।
- झ. शुल्क लागू होने से देश में विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

173. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के संबंध में सकारात्मक जानकारी देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन तथा क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
174. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2910 30 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन	थाईलैंड	थाईलैंड	एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) (पूर्व में एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	298	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई	(1) के इतर कोई उत्पादक	327	एमटी	यूएसडी

				देश				
3	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	थाईलैंड	कोई	327	एमटी	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	274	एमटी	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	लोटे फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	506	एमटी	यूएसडी
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	(4) और (5) से इतर कोई उत्पादक	557	एमटी	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	557	एमटी	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जियांग्सू रुईजियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	108	एमटी	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	निंग्बो हुआयांग न्यू मटेरियल कंपनी लि०	शून्य	एमटी	यूएसडी
10	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	(8) और (9) से इतर कोई उत्पादक	216	एमटी	यूएसडी
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	216	एमटी	यूएसडी

ढ. आगे की प्रक्रिया

175. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI) -14/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Epichlorohydrin” originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

F. No. 6/15/2023-DGTR.—A BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof, Epigral Limited (formerly known as Meghmani Finechem Limited) (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Epichlorohydrin (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or “ECH”) from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand.
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification F. No. 6/15/2023-DGTR, dated 26th September, 2023, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”) in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry. However, in the absence of prima facie evidence regarding the dumping of the product under consideration from Taiwan, the Authority did not find it appropriate to initiate the investigation into imports from Taiwan.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 26th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26th September 2023, to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority also forwarded a copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made

available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification. The Authority sent a questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. Dongying Rich Chemical Co. Limited, China PR
 - ii. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co. Limited, China PR
 - iii. Infoark International Co. Limited, China PR
 - iv. Nanjing Beinu Pharmaceutical Co. Limited, China PR
 - v. Synchem International Co. Limited, China PR
 - vi. Zibo Feiyuan Chemical Co. Limited, China PR
 - vii. Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited, Advanced Materials, Thailand
 - viii. Advanced Biochemicals (Thailand) Co. Limited, Thailand
 - ix. Samsung Fine Chemicals Co. Limited, Korea RP
- f. In response to the initiation notification, the following producers/exporters from the subject countries filed questionnaire response:
- i. Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Limited (“Ruixiang”), China PR
 - ii. Ningbo Huanyang New Material Co. Limited (“Huanyang”), China PR
 - iii. Canko Marketing, Inc. Korea RP
 - iv. Everlite Korea Co. Limited, Korea RP
 - v. Hanwha Corporation, Korea RP
 - vi. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP
 - vii. Lotte Fine Chemical, Korea RP
 - viii. Minjin Corporation, Korea RP
 - ix. AGC Vinythai Public Co. Limited, Thailand
 - x. Samsung C&T (Thailand) Company Limited, Thailand
- g. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- h. The Authority sent importer’s / user’s questionnaire to the following known importers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Atul Limited
 - ii. Cardolite Speciality Chemicals India LLP
 - iii. Endoc Lifecare Private Limited
 - iv. M/s Granules India Limited sim Industries Ltd.
 - v. Grasim Industries Limited M/s Cardolite Speciality Chemicals India LLP
 - vi. Hindustan Speciality Chemicals Limited
 - vii. IPCA Labs
 - viii. Krishna Antioxidant
 - ix. Paarichem Resources LLP
 - x. Praful Venture
 - xi. Resins and Plastics
 - xii. Rishabh Metal
 - xiii. Synthokem Labs
 - xiv. Unidrugs Limited

- i. In response to the initiation notification, the following importers/users submitted a response to the questionnaire response:
 - i. Atul Limited
 - ii. Cardolite Speciality Chemicals India LLP
 - iii. Grasim Industries Limited
 - iv. Hindustan Speciality Chemicals Limited
- j. Additionally, the following parties registered themselves as an interested party or made submissions during the course of the investigation:
 - i. Trade, Legal Affairs and Planning Division, Ministry of Trade, Industry and Energy, Government of Korea
 - ii. Trade Interests and Remedies Division, Department of Foreign Trade, Government of Thailand
 - iii. China Chlor-Alkali Industry Association, China PR
 - iv. Rishabh Metals and Chemicals Private. Limited
 - v. Sandeep Organics Private Limited
- k. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the following associations on 5th October 2023.
 - i. FIEO
 - ii. FICO
 - iii. ASSOCHAM
 - iv. CII
- l. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application along with a copy of the economic interest questionnaire was sent to the following ministry on 5th October 2023. However, the Authority has not received any comments:
 - i. Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers
- m. In addition to the above, DCM Shriram Limited, an upcoming producer of the subject goods who is in the process of setting up its production facilities, filed a letter supporting the application made by the domestic industry.
- n. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- o. A request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury period will cover the period of investigation and the three preceding financial years 2019-20, 2020-21, and 2021-22. Further, since the applicant was operational only during the period of investigation, data has been analysed by (a) splitting the period of investigation into quarters; (b) as per the project report; and (c) by considering 80% capacity utilization.
- r. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 12th July 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
- t. The Authority sought further information from the applicant to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis of the present case.
- u. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- v. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 8th February 2024. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- w. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- y. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- z. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - aa. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 81.06
 - bb. The following abbreviations have been used in this document:
 - a. ECH = Epichlorohydrin
 - b. NIP = Non-injurious price
 - c. POI = Period of investigation
 - d. PUC = Product under consideration

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is Epichlorohydrin, abbreviated as ECH. The chemical name of the product, which is also used in the customs classification is 1-chloro-2,3-epoxypropane. Its chemical formula is C₃H₅ClO.

4. It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is majorly used to make epoxy resins, which account for nearly 80% of its consumption. It is also used in pharmaceutical API, water treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants, adhesives, elastomers, plastics and rubbers and as a strength additive in papers. The product can be produced using propylene as well as using glycerine.

5. The product under consideration is conventionally produced using propylene, where propylene chlorination is done at high temperatures to produce allyl chloride. Following allyl chloride separation and allyl chloride hydrochlorination, dichlorohydrine is produced and allylchloride is recovered. Dichlorohydrine undergoes saponification to produce ECH which is then purified. However, such a production process results in high waste generation and thus, requires high capital expenditure for disposal. To overcome these challenges, ECH is now produced using bio-based glycerine, which is an environment-friendly production process.

6. *The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the heading 2910 under the subheading 2910 30 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.*”

C.1 Submissions by other interested parties

5. With regard to like article, the other interested parties have submitted that the Certificate of Analysis of the subject imports should be compared with that of the domestic industry. Further, the other interested parties also made the following submissions:
- a. ECH sold for use in the epoxy industry are sold in bulk and in ISO tanks, whereas ECH sold for use in APIs is sold in lesser quantities and in drum packing, which are priced higher. Thus, there is a need to consider PCN for the produce based on differences in the pricing as a result of end-usage of the subject goods.

C.2 Submissions by the domestic industry

6. The domestic industry has submitted that it has produced like article to the imported product under consideration. The domestic industry has also submitted its specification sheet.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is Epichlorohydrin or ECH, having the chemical name 1-chloro-2,3-epoxypropane. Its chemical formula is C_3H_5ClO . It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is mainly used to produce epoxy resins. It is also used in pharmaceutical API, water treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants elastomers, adhesives, and rubber. It is also used as a strength additive in paper.
8. ECH is classified under Chapter 29 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 under the tariff code 2910 30 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
9. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the scope of the product under consideration. Accordingly, the Authority has considered the same scope of the product under consideration, as defined in the notice of initiation, for the purpose of the final findings.
10. The Authority notes that the domestic industry has claimed that goods produced by it is like article to the subject goods originating in or exported from the subject countries. The subject goods can be produced using two routes – using the propylene route or using the glycerine feedstock route. The domestic industry has produced ECH using the glycerine feedstock route. However, the domestic industry has submitted that there are no differences in the subject goods manufactured using propylene, if any, and those manufactured using glycerine. ECH produced using both routes have the same technical and physical characteristics, applications, pricing and customers. None of the other interested parties have claimed any difference in the subject goods produced using the propylene or glycerine route. The Authority also notes that the producers in China and Thailand have also produced the subject goods using glycerine. Thus, the Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.
11. With respect to the argument raised by the Government of Korea concerning the consideration of PCN, it is noted that the party failed to raise such argument within the time limits prescribed by the Authority in its initiation notice. Thus, submissions made at such a belated stage in the investigation cannot be considered. In any case, none of the responding producers/exporters, including those from Korea RP have requested for creation of PCN on such grounds. Thus, such an argument cannot be accepted.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions by other interested parties

12. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the existence of domestic industry and standing.

D.2 Submissions by the domestic industry

13. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and standing:
- a. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, having commenced production in June 2022.

- b. DCM Shriram Limited and Grasim Industries Limited are also in the process of setting up production facilities for manufacturing ECH.
- c. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any exporter or importer of the alleged dumped article.

D.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

15. The present application was filed by Epigral Limited (formerly known as Meghmani Finechem Limited). At present, Epigral Limited is the sole producer of the like article in India. Thus, the production by the applicant accounts for 100% of the total production of ECH in India. The applicant is not related to any exporter or importer of the alleged dumped article and has not imported such article. Thus, the Authority holds that Epigral Limited constitutes “domestic industry” under Rule 2(b) of the Rules and the application meets the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

D. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by other interested parties

16. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
- a. The applicant has claimed excess confidentiality in violation of Trade Notice 10/2018.
 - b. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and has relied on confidential figures in the petition and written submissions, without providing a non-confidential summary, causing prejudice to other interested parties.
 - c. The applicant has not provided a non-confidential version of the project feasibility report, depriving other interested parties of an opportunity to formulate a response and any submissions in relation to such projections is thus, baseless.
 - d. The applicant has incorrectly indexed the figures for the period of investigation in Proforma IVA which should be a sum of all indexed numbers for each quarter.
 - e. The applicant has claimed confidentiality regarding its flowchart of the production process.
 - f. The applicant has claimed excessive confidentiality and has not given even trends regarding the cost of raw materials, return on investment, and number of days of shutdown. Further, the calculation of normal value, injury margin and price undercutting has also been claimed confidential.
 - g. In response to the contentions of the applicant, it was submitted that the impact of duties has been calculated using cost structure and input expenses of users, which is business sensitive. The user industry is not required to disclose actual information and is only required to give a reasonable summary to the extent possible.
 - h. With regards to capacity expansion by Grasim, detailed aspects and costs involved are business-sensitive information. Public information shared by the applicant is only a general statement and does not take into account total expenditure and adjustments for capacity consumption.
 - i. Details of long-term contracts between users and suppliers are highly business-sensitive.
 - j. Channel of distribution and method of claiming adjustment to export prices is highly commercially sensitive information.

E.2 Submissions by the domestic industry

17. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- a. The other interested parties have claimed excessive confidentiality and have claimed complete answers as confidential in violation of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and Trade Notice No. 10/2018. Further, the parties have failed to provide a statement of reasons as per the format prescribed under Trade Notice No. 1/2013.
 - b. AGC Vinythai Public Company Limited claimed excessive confidentiality with regard to adjustments for normal value and export price, channel of distribution, write up of manufacturing process, raw materials

used and post invoicing discounts.

- c. AGC Vinythai Public Company Limited has not provided information that is available in the public domain, such as details of raw materials and inputs purchased from related parties, ownership structure of the company and the installed capacities.
- d. The users have claimed complete confidentiality with regards the alleged impact of duties, impact of alleged dumping or subsidization on the domestic industry, prevailing prices, other causes of injury to domestic industry, existence of long-term contracts, etc.
- e. Information such as proposed capacity expansions by Grasim Limited and list of products sold by Cardolite Specialty Chemicals India LLP, which is available in the public domain, has been claimed confidential by the respective users.
- f. Hanwha Corporation, Hanwha Solutions, Lotte Finechem and Samsung C&T have not provided details of related parties engaged in the sale and production of the subject goods, in violation of requirements of Trade Notice 10/2018. Further, all such exporters have claimed confidentiality with regard to shareholding structure which is publicly available.
- g. Lotte Finechem and Samsung C&T have claimed confidentiality with regards to the write-up of manufacturing process, raw materials and the description of the subject goods sold.
- h. Lotte Finechem has submitted an incomplete response inasmuch as the producer has not submitted information under Appendix 10, despite claiming that it captively produced inputs for use in ECH.
- i. Ningbo Huanyang and Jiangsu Ruixiang have claimed excessive confidentiality with regards to related parties engaged in the production and sale of ECH, write-up of manufacturing process, raw materials used, description of the subject goods sold, the channel of distribution and all adjustments for export price comparability.
- j. Ningbo Huanyang and Jiangsu Ruixiang have filed inconsistent responses and have submitted different information in different parts of the response.
- k. In response to the comments filed by the other parties, it was submitted that the comments were time-barred, having been filed beyond the time limit notified in the initiation notification.
- l. The domestic industry has provided indexed figures in a manner which allows comparison of information with each quarter and the figures for the period of investigation have been proportionately adjusted to reflect the data for a quarter.
- m. The project feasibility report of the domestic industry is highly business sensitive information and the same was not required to be disclosed under Trade Notice No. 10/2018. Further, the domestic industry is also not required to disclose price undercutting under the Trade Notice.

E.3. Examination by Authority

18. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
19. About confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

20. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties provided information on a confidential basis were directed to provide sufficient

non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. It is noted that the various interested parties complied with such directions and made appropriate disclosures.

21. With regards to the arguments raised by the interested parties regarding the confidentiality claimed by the applicant concerning its project feasibility report, the Authority notes that such arguments were filed beyond the prescribed time of 7 days from the date of receipt of the non-confidential version of the application, as per the initiation notification. Further, the domestic industry has claimed that the information contained in the project feasibility report is business sensitive and disclosure of the same would be detrimental to their interests. The Authority has accepted such a claim of the domestic industry.
22. With regards to the arguments raised by the domestic industry concerning the excessive confidentiality claimed by the producer, AGC Vinythai Public Company Limited, the Authority notes that the exporter has claimed that such information is business sensitive and details of such transactions cannot be disclosed to other interested parties. Such a claim has been accepted by the Authority.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submissions by other interested parties

23. The following submissions have been made by the other interested parties about miscellaneous issues:
 - a. Retrospective imposition of anti-dumping duty is not allowed as per the decision of the Authority in the mid-term review concerning anti-dumping duty imposed on imports of Sodium Tripoly Phosphate from China PR.
 - b. Since historical dumping has not been established by the domestic industry, the requirements for retrospective imposition of duty are not met.
 - c. The current period of investigation is not representative of the normal market conditions as it was affected by significant global price fluctuations for ECH, its raw material and downstream products.
 - d. The period of investigation must be determined based on data collected over a sustained period, which is not impacted by other externalities, as held by the Appellate Body in EC—Tube or Pipe Fittings.
 - e. The period of investigation must be for a minimum period of two years.
 - f. The domestic industry should be allowed to file an application for initiation of anti-dumping investigation only after they have been in operation for a minimum of 2 years.
 - g. The minutes of meeting the domestic industry should be submitted.
 - h. The investigation should adhere to WTO guidelines.
 - i. The use, duty and prices of refined and crude glycerine are different and thus, accurate reference must be made to avoid any confusion.
 - j. The basic customs duties on imports from China is 5.775% under AIPTA, while the duty for imports from Korea RP and Thailand is 0%. The basic customs duty on imports from Taiwan is 8.25%.

F.2 Submissions by the domestic industry

24. In response to the submissions made by the other interested parties, the domestic industry submitted as under.
 - a. In response to the contention that the period of investigation was not appropriate, having had significant fluctuations, it was submitted that the prices of chemical products witness significant fluctuations and if one were to consider a period of investigation with no fluctuations, no investigation could be conducted for chemical products.
 - b. The WTO Appellate Body in EC – Tube or Pipe Fittings held that a period of investigation should be a sustained period, which was 12 months in the case as this would allow a proper evaluation of dumping and injury while taking into account any fluctuations. The Appellate Body also held that situations of major changes during or after the period of investigation which result in the elimination of dumping or injury can be addressed through review mechanisms.
 - c. Under Rule 5(3A), the period of investigation shall normally be for twelve months and may be for a maximum period of eighteen months.
 - d. The contention that the domestic industry must have been in operation for at least 2 years before filing an application is not appropriate since a domestic producer can request for initiation of an anti-dumping investigation even before starting production as per the practice of the Authority and the various decisions of the WTO Panel.
 - e. The contention of the other interested parties that retrospective imposition of duties is not allowed as held in one investigation is not tenable as non-imposition of retrospective duties in one case cannot mean that duties cannot be imposed retrospectively in other cases. The need for retrospective duties should be seen about the facts of the case and the legal position.

- f. The domestic industry shall provide such information as is required by the Authority.
- g. The domestic industry has provided its technical specification sheet in the petition.

F.3 Examination by the Authority

- 25. With regards to the claim that the current period of investigation is not representative of normal market conditions as there were significant price fluctuations during such period, based on the price information submitted by various interested parties, it can be seen that the prices of the subject goods, as well as the raw materials, have witnessed significant fluctuations in the past as well. Further, the domestic industry has claimed that price fluctuations have continued in the post-POI period as well. Further, fluctuations in the prices of products are not uncommon. However, normally, prices fluctuate in response to fluctuations in factors of cost of production. In the present case, the domestic industry has demonstrated that the prices of ECH have fluctuated in a manner which does not align with the prices of the raw materials. The fluctuations do not indicate that the current period of investigation is inappropriate.
- 26. The other interested parties have also relied upon the decision of the WTO Appellate Body in the case of EC - Tube or Pipe Fittings to claim that the period of investigation should be for a sustained period and that such period should not be affected by any variations. However, the WTO Appellate Body had rejected the arguments of Brazil for consideration of a smaller period of investigation which was unaffected by fluctuations. Rather, it was held that the period of investigation should be sustained, such as 12 months, which takes into consideration any market vagaries. The Appellate Body went ahead to state that in a situation where variations or fluctuations in certain factors result in the elimination of dumping or injury, the interested parties are free to seek review under the Anti-dumping Agreement.
- 27. With regards to the claim that the domestic industry should be allowed to file an application for an anti-dumping investigation after being in operation for a minimum of 2 years, it is noted that there is no requirement under the Act or Rules that a company must be in operation for a minimum of 2 years before it can seek remedy from the Authority. Thus, there is no merit in the claim that the domestic industry must operate for a minimum of two years before filing an application.
- 28. As regards the claim that the period of investigation should consist of a minimum period of 2 years, the Authority notes that Explanation to Rule 5(3) of the Rules provides that the period of investigation shall be for a period of 12 months normally and for reasons recorded, it can be for a minimum period of six months and a maximum period of eighteen months. Therefore, a period of 2 years cannot be considered a period of investigation in any situation.
- 29. With regards to the claims regarding the consideration of basic customs duty of 5.775% for determination of landed value for China PR, the Authority has determined the landed value for all the subject countries considering the basic customs duties as applicable during the period of investigation.
- 30. With regards to the submission concerning retrospective imposition of duties, the Authority notes that the non-application of duties in the past does not prevent the Authority from recommending retrospective imposition of duties in present or future cases. Should the Authority find it appropriate to recommend imposition of duties, it may also examine the need for recommending retrospective imposition of duties. Some of the interested parties have contended that retrospective imposition is not permissible, as there is no history of dumping. The Authority notes that the provisions of Section 9A(3) do not require a history of dumping as a mandatory condition to be satisfied for retrospective imposition of duty. As per clause (i) of sub-section (3), duties may be imposed retrospectively where there is a history of dumping or the importer was, or the importer should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury. The Authority would arrive at its final determination in accordance with such legal position.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Submission by other interested parties

- 31. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin.
 - a. The applicant has not explained efforts made to obtain information related to domestic selling prices in Thailand for determination of normal value.
 - b. The applicant has not demonstrated how Korea RP and Thailand are comparable in terms of economic conditions and has only considered comparability in terms of volume exports.
 - c. The Authority should treat the exporters from Hanwha group as co-operative interested parties as they have provided all required information.
 - d. Normal value determined for China PR based on the cost of production of domestic industry is in contravention to the hierarchical approach provided under Para 7 of Annexure-I and affirmed by CESTAT in

Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd. vs. Union of India and the Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs. Exide Industries Ltd.

- e. Construction of normal value based on cost of production of domestic industry would be detrimental to the exporters as such cost is inflated due to high start-up costs and procurement of key raw materials at higher value.
- f. The normal value for co-operating Chinese producers should be calculated based on the normal values determined for market economy countries which are also part of this investigation.
- g. Dumping margin and injury margin should be determined on a monthly basis for fair comparison due to significant price variations during the period of investigation in the prices of glycerine and ECH.
- h. The determination of dumping margin using W-T methodology would not be appropriate due to wide price variations which may lead to absurdities in calculation.
- i. The use of W-T methodology is an exception, as held by the Appellate Body in case of U.S. – Washers, and should not be applied as there is no significant differences in the export prices among purchasers, regions or time periods in the present case.
- j. The Authority should refrain from carrying out “zeroing” for the calculation of dumping margin as it is against its own practice and the principles of WTO.
- k. LFC has exported goods based on international market price determined by ICIS and it is unreasonable to expect that LFC would maintain separate market prices specifically for the Indian market.
- l. AGC Vinythai has made all appropriate disclosures regarding all affiliated party transactions and will cooperate with the Authority during the verification process.
- m. Export Declaration and CAROTAR are used for valuation, but such valuation is beyond the scope of DGTR as it is a matter for DRI. Since the CIF prices from Korea RP and Thailand are higher, under-invoicing will not serve any purpose with regards to imports under duty concession.

G.2 Submissions by the domestic industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin:
 - a. The dumping margin for the foreign producers must be calculated using the W-T methodology since there is a pattern of export prices which differs significantly in the last two quarters of the period of investigation as compared to the first two quarters.
 - b. The WTO Appellate Body in US - Anti-Dumping and Countervailing Measures on Large Residential Washers from Korea, upheld the application of W-T methodology for addressing situations of targeted dumping and noted that there must be an intelligible pattern of price differentiation, the pattern must be in relation to transactions priced lower than other transactions, the differences in prices must be significant and not merely nominal and such pattern transactions must be separate from other non-pattern transactions.
 - c. The WTO Appellate Body also held that determination of dumping margin using W-T methodology should be limited to pattern transactions and non-pattern transactions should not be considered for the determination of dumping margin. Further, all export sales should be considered as a denominator for determination of dumping margin.
 - d. Determination of dumping margin using the W-W or T-T methodology would lead to masking of level of dumping in second half of the year by the undumped transactions in the initial period.
 - e. The domestic industry has not claimed zeroing. Rather, the claim of the domestic industry is consistent with the WTO position.
 - f. Advanced Biochemicals (Thailand) Co. Limited, which was the producer of ECH during the period of investigation, has failed to provide information concerning sale of the subject goods to its parent company, AGC Vinythai Public Company Limited.
 - g. Advanced Biochemicals (Thailand) Co. Limited / AGC Vinythai Public Company Limited must demonstrate that sufficient volume of sales made in the domestic market are in the ordinary course of trade. If the volume of sales in the ordinary course of trade is low, then the normal value for the producer must be determined on their exports to third country.
 - h. The Authority must examine whether the purchase of raw materials or inputs by Advanced Biochemicals (Thailand) Co. Limited / AGC Vinythai Public Company Limited from its parent companies and various related parties are at arm's length price, failing which the cost of production for the producer must be

adjusted for prices of raw materials / inputs as prevailing in the international market.

- i. The marketing and servicing fees paid by Advanced Biochemicals (Thailand) Co. Limited / AGC Vinythai Public Company Limited to their related entity in India, namely AGC Asia Pacific (India) Private Limited, must be adjusted as selling, general and administrative expenses of the related marketing entity in the export price determined for the exporter.
- j. The domestic industry provided normal value for Thailand on the basis of information as was reasonably available to it at the time of filing response.
- k. For selection of appropriate third country for a market economy, there is no requirement to consider the level of development. Since the second largest quantum of exports from Thailand is to Korea, it is appropriate to consider the same for determination of normal value.
- l. The domestic industry has provided information regarding adjustments to normal value as was reasonably available at the time of filing of application.
- m. Normal value cannot be determined based on prices in Thailand or Korea, as the opposing parties have not demonstrated that such countries are comparable to China in terms of level of development of the economy or the product concerned.
- n. Normal value for producers / exporters from China PR should be determined based on the price payable in India, which is based on the cost of production of the domestic industry along with a reasonable profit.
- o. The cost of production of the domestic industry is not inflated and is not affected by any start-up costs which are not considered as part of the cost of production. Further, the domestic industry has no objection to use of international prices of refined glycerine and caustic soda for determination of normal value, as per the past practice of Authority.
- p. The export price has been determined based on the CIF prices of the imports adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to arrive at the ex-factory level.
- q. The claim for determination of dumping and injury margin on monthly basis is a tactic for delay. In any case, the domestic industry has provided information on quarterly basis, which can be considered.
- r. The dumping margin for the subject countries is positive and significant.

G.3 Examination by the Authority

33. The responses to exporters' questionnaire have been filed by the following producers/ exporters:
 - i. Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Limited ("Ruixiang"), China PR
 - ii. Ningbo Huanyang New Material Co. Limited ("Huanyang"), China PR
 - iii. Canko Marketing, Inc. Korea RP
 - iv. Everlite Korea Co. Limited, Korea RP
 - v. Hanwha Corporation, Korea RP
 - vi. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP
 - vii. Lotte Fine Chemical, Korea RP
 - viii. Minjin Corporation, Korea RP
 - ix. AGC Vinythai Public Co. Limited, Thailand
 - x. Samsung C&T (Thailand) Company Limited, Thailand
34. The domestic industry has claimed that there is a pattern of export prices which differs significantly in the last two quarters of the period of investigation as compared to the first two quarters and therefore, the dumping margin should be determined using the W-T methodology. On the other hand, the other interested parties have claimed that the Authority must not undertake zeroing. The Authority has examined the information with respect to margins based on W-W and the information provided by the domestic industry with respect to the W-T methodology in its written submission. It is noted that in the case of imports from Thailand, the information submitted does not show that the price differences in the export prices between different periods cannot be adequately accounted for using the W-W methodology. In view of the same, the dumping margin is not required to be calculated using the W-T methodology as per the provisions of Article 2.4.2 of the WTO Anti-dumping Agreement and para 6(iv) of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. With respect to the exports from China PR and Korea RP, though the differences in prices are more significant, the injury margin

is lower than the dumping margin determined for the cooperative and non-cooperative exporters from such countries. In view of the same, whether there is a need for the application of W-T methodology for exports from China PR and Korea RP is not necessary.

35. The Authority also notes that there have been wide variations in the prices of the subject goods imported during the period of investigation. This has been highlighted both by the domestic industry and by the opposing parties. During the first half of the year, the prices of the subject goods remained high, while the prices declined significantly during the second half of the year. Therefore, in order to account for such variations, the Authority has determined the normal value and export price for all foreign producers and exporters on a quarterly basis.

G.3.1 Determination of Normal value and Export Price

Normal value for China PR

36. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

37. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal

value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

38. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules: If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability; The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

39. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.
40. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.
41. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India.
42. At the stage of filing the application, the domestic industry submitted that the normal value for China PR should be constructed based on the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
43. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. While the domestic industry has claimed that the normal value for China should be determined based on the price of exports from the appropriate surrogate country into India, namely Belgium or Saudi Arabia, it is noted that the volume of exports from such third countries is de-minimis. Further, while the interested parties have claimed that the normal value for China should be determined based on the prices in Thailand or Korea, they have not established that either of the countries is appropriate in view of the level of development of the country concerned and the product in

question.

44. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India, for each quarter of the period of investigation. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.
45. For this purpose, the Authority considered the optimized cost of production of the domestic industry for each quarter, with an addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The weighted average normal value for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for China PR

Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Limited (Ruixiang)

46. Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Limited (Ruixiang) is a producer of the subject goods in China PR. Ruixiang has sold the product under consideration directly to unaffiliated importers in India. It is noted that during the period of investigation, Ruixiang has exported *** MT of the subject goods to unrelated importers in India. The adjustments towards freight, credit cost, insurance, and bank charges have been accepted for the purpose of the present final findings. Accordingly, the Authority has determined the export price on a quarterly basis, and the weighted average export price for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Ningbo Huanyang New Material Co. Limited (Huanyang)

47. Ningbo Huanyang New Material Co. Limited (Huanyang) is a producer of the subject goods in China PR. Huanyang has sold the product under consideration directly to unaffiliated importers in India. It is noted that during the period of investigation, Huanyang has exported *** MT of the subject goods to unrelated importers in India. The adjustments towards ocean freight, credit cost, insurance, inland transportation, port and other related expenses and bank charges have been accepted for the purpose of the present final findings. Accordingly, the Authority has determined the export price on a quarterly basis, and the weighted average export price for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from China PR

48. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal value for Korea RP

Hanwha Solutions Corporation (HSC)

49. Hanwha Solutions Corporation (HSC) is a producer of the subject goods in Korea RP. HSC has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. HSC has claimed price adjustments on account of credit cost and inland transportation and the same is allowed by the Authority. Thus, the normal value at ex-factory level for HSC has been calculated for each quarter and the weighted average normal value for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Lotte Fine Chemical (LFC)

50. Lotte Fine Chemical (LFC) is a producer of the subject goods in Korea RP. LFC has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. LFC has claimed price adjustments on account of inland transportation, loading charges, inspection fees, credit costs and packing costs and the same is allowed by the Authority. Thus, the normal value at ex-factory level for LFC has been calculated for each quarter and the weighted average normal value for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in Korea RP

51. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Korea RP has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Korea RP**Hanwha Solutions Corporation (HSC), Hanwha Corporation (HC), Canko Marketing, Inc. (Canko), Everlite Korea Co. Limited (Everlite) and Minjin Corporation (Minjin)**

52. Hanwha Solutions Corporation (HSC) is a producer of the subject goods in Korea RP. HSC has exported the subject goods to India through Hanwha Corporation (HC), Canko Marketing, Inc. (Canko), Everlite Korea Co. Limited (Everlite) and Minjin Corporation (Minjin). HC, Canko, Everlite and Minjin have sold the subject goods directly to un-related customers in India. During the period of investigation, HSC has exported the goods through the following distribution channels.

HSC → HC → Unrelated customers in India

HSC → Canko → Unrelated customers in India

HSC → Everlite → Unrelated customers in India

HSC → Minjin → Unrelated customers in India

53. It is noted that during the period of investigation, HSC has exported *** MT of the product under consideration directly to unrelated customers in India. The adjustments towards inland freight, ocean freight, brokerage, port charges, marine insurance, credit cost, commission and bank charges have been claimed for sales to India. The same has been accepted for the purpose of the present final findings. Accordingly, the Authority has determined the export price on a quarterly basis, and the weighted average export price for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Lotte Fine Chemical (LFC) and Samsung C&T (Thailand) Company Limited (SCT)

54. Lotte Fine Chemical (LFC) is a producer of the subject goods in Korea RP. LFC has exported the subject goods to India through Samsung C&T (Thailand) Company Limited (SCT), a trader in Thailand. LFC and SCT have claimed that the goods are directly shipped from Korea to India and SCT acts merely as a trader. LFC has also exported *** MT of the subject goods to India through IMS Corporation. However, since exports through IMS Corporation are minimal, the same have been excluded for the purpose of the present investigation. LFC and SCT have sold the subject goods directly to unrelated customers in India. During the period of investigation, LFC has exported the goods through the following distribution channels.

LFC → SCT → Unrelated customers in India

55. It is noted that during the period of investigation, HSC has exported *** MT of the product under consideration directly to unrelated customers in India. The adjustments towards ocean freight, customs clearance fees, inland transportation, insurance, credit cost, inspection fees, packing cost and bank charges have been claimed for sales to India. The same has been accepted for the purpose of the present final findings. Accordingly, the Authority has determined the export price on a quarterly basis, and the weighted average export price for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Korea RP

56. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Korea RP has been determined based on the best available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal value for Thailand**AGC Vinythai Public Co. Limited**

57. AGC Vinythai Public Co. Limited (AVT) is a producer of the subject goods in Thailand. AVT has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India.
58. With regards to the claim by the domestic industry that AVT has purchased raw materials and inputs from its parent company and other related parties, it is noted that the exporter has provided complete details of all raw materials and inputs purchased from its related parties for the production of the subject goods. The Authority has verified the information submitted by the exporter. It is noted that the purchases of raw materials and the inputs by AVT (formerly known as Advanced Biochemical (Thailand) Co. Ltd.) from its related parties are at an arm's length basis.
59. With regards to the claim by the domestic industry that AVT has sold the subject goods to its related parties in the domestic market during the period of investigation, it is seen that during the period of investigation, Advanced Biochemical (Thailand) Co. Ltd. had sold other products to its related parties, which were not sales

of the subject goods. The same has been verified by the Authority.

60. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The company has claimed price adjustments on account of insurance and inland transportation and the same is allowed by the Authority. Thus, the normal value at ex-factory level for AVT has been calculated for each quarter and the weighted average normal value for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in Thailand

61. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Thailand

AGC Vinythai Public Co. Limited (AVT)

62. AGC Vinythai Public Co. Limited (AVT) is a producer of the subject goods in Thailand. AVT has directly sold the product under consideration to unrelated customers in India. During the period of investigation, AVT has exported the goods through the following distribution channels.

AVT → Unrelated customer in India

63. The domestic industry has contended that AVT has paid certain marketing fees and services fees to its related party which should be adjusted in the export price. In this regard, the Authority requested further information from the exporter with respect to the marketing fees. The exporter submitted that it entered into a services agreement with its related party to provide certain services on a non-exclusive basis. AVT has paid marketing fees on a monthly basis and on the basis of a fixed formula. It is noted that since AVT has sold only ECH during the period of investigation, the marketing fees paid by AVT to its affiliate is directly related to exports of ECH to India. Accordingly, the marketing fees paid by AVT to its related party has been adjusted in the net export price determined for the exporter.
64. It is noted that during the period of investigation, AVT has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. The adjustments towards ocean freight, surveyor cost, insurance, handling charges, inland freight and credit cost have been claimed and the same have been accepted by the Authority. Accordingly, the Authority has determined the export price on a quarterly basis, and the weighted average export price for the period of investigation is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Thailand

65. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Thailand has been determined based on the best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules.

G3.2. Dumping Margin

66. The normal value, export price and dumping margin in the present investigation is determined on a quarterly basis and is as follows:

Dumping Margin Table

S.N.	Producers	NV	EP	DM	DM	Range
A	Thailand	\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	
1	AGC Vinythai Public Company Limited (AVT) (Formerly known as Advanced Biochemical (Thailand) Co., Ltd.)	***	***	***	***	10-20%
2	Any Other	***	***	***	***	15-25%
B	Korea RP	***	***	***	***	
1	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	30-40%
2	Lotte Fine Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	40-50%
3	Any Other	***	***	***	***	45-55%
C	China PR	***	***	***	***	
1	Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35%
2	Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd.	***	***	***	(***)%	Negativ

						e
3	Any Other	***	***	***	***%	30-40%

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of other interested parties

67. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link.

- i. The subject imports from Thailand are not competing with imports from China PR and Korea RP as their volume trends have moved differently and thus, such imports cannot be cumulatively analysed as per Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement.
- ii. Imports from Thailand have not caused injury to the domestic industry as they have moved in line with the Indian consumption.
- iii. The subject imports from China do not have ability to impact price as the volume of imports from China is significantly lower than imports from Thailand while the landed price from China is significantly higher than Thailand.
- iv. Based on the information submitted, the injury margin for LFC would be negative. Injury, if any, is likely caused due to exports from Thailand.
- v. The existence of a producer of ECH in 2013 that has since ceased to exist, does not prohibit the Authority from examining material retardation to the establishment of a domestic industry in the present case.
- vi. Determination of injury margin considering only injurious volume of imports is not consistent with Article 3.1 of the Anti-dumping Agreement.
- vii. During the period of investigation, the volume of imports has not increased in the same ratio as increase in demand, which is much higher as the applicant commenced production. Prior to the period of investigation, imports and demand moved in tandem in absence of domestic production.
- viii. The claim of the applicant that the volume of imports should have declined with its commencement of production cannot be accepted as a nascent industry takes considerable time to stabilize and create market presence. Nevertheless, subject imports have declined in each quarter of the period of investigation while the sales of the domestic industry have increased.
- ix. Since the applicant has just started production and has faced shutdowns, the volume of imports in relation to production would naturally be higher.
- x. The increase in volume of the subject imports during the period of investigation is only a rebound in export quantities following the economic standstill caused due to COVID-19 pandemic.
- xi. The increased share of the subject imports in overall imports is simply on account of the subject imports replacing the non-subject imports and does not imply any adverse impact on the applicant. The applicant has itself replaced the market share of the subject imports.
- xii. The demand in India has shown a positive trend and thus, even in absence of domestic production, the subject imports would show an increase.
- xiii. The subject imports have not suppressed the prices of the domestic industry, as imports from Thailand have declined despite reduction in import price.
- xiv. Import prices have followed the trend of prices in the international market, and fluctuated due to change in the price of the raw materials and the decline is not due to dumping.
- xv. The claim of the applicant that the exporters are supplying at lower prices to the Indian market must be rejected as the source or methodology used to arrive at the claim have not been provided.
- xvi. The target prices set by the applicant are unrealistic given the market scenario that existed during the period of investigation and any failure to meet such targets cannot be associated to the subject imports.
- xvii. The volume and price data alleged for examining price behaviour of the exporters is significantly different than the data provided in Proforma IVA as well as from the data independently extracted from Trade Map.
- xviii. The Authority must examine the information submitted by cooperating exporters to analyse the trends of the prices of the subject goods.
- xix. The applicant procured raw material at high prices and stocked the same for 3-4 months in order to

- facilitate the commissioning of its plant, as admitted in the earnings call for Q3 and Q4. On the other hand, the most competing imports procured raw material in an economically efficient manner.
- xx. The prices of glycerine and ECH peaked in May 2022 and declining after June 2022, when the applicant commenced operations. Production of ECH using refined glycerine imported till June 2022 when prices peaked, led to a high cost for the domestic industry. Further, the labour cost of the domestic industry has also increased.
 - xxi. The domestic industry used refined glycerine till September 2022, instead of crude glycerine which is more cost effective as there was a difference of ***% between their prices during the period of investigation. The domestic industry used crude glycerine at a much later stage. Thus, they may be unable to achieve desired market share due to conscious decision to choose production process based on glycerine.
 - xxii. In view of steep decline in prices of ECH over the period, the Authority should conduct quarterly analysis between price and cost of production instead of an annual analysis, as per past practice in various cases.
 - xxiii. The CIF price of almost all chemicals declined in the period of investigation due to Ukraine – Russia war, Israel war, financial instability in Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan etc.
 - xxiv. Since Grasim Limited and DCM Shriram Limited are not currently producing ECH, it is unclear as to why such producers are investing in the product.
 - xxv. Since the domestic industry was not operational for the entire period of investigation, injury parameters for a limited period of operation would not demonstrate an accurate picture of health of the industry.
 - xxvi. The projected parameters of the applicant cannot be relied upon as they are dependent on specific market conditions without taking into account significant price fluctuations which affect operational cost and profitability.
 - xxvii. The imports have not hampered the capacity utilization of the domestic industry and it has been able to gradually increase the same, as acknowledged in its annual report 2022-23 and the quarterly earnings call in Q2 of FY24.
 - xxviii. The capacity utilization of the applicant is impressive for an industry in nascent stage and despite facing shutdowns.
 - xxix. There is no adverse volume effect of the subject imports on the applicant as their market share has increased, even if not to targeted levels.
 - xxx. Despite plant shutdown in Q3, the domestic industry was able to rapidly increase its sales and production in Q4 as compared to Q1, which was in line with the expectations expressed in the quarterly earnings call.
 - xxxi. The applicant has claimed that even at optimum capacity utilization it would be facing losses based on project report without providing non-confidential version of the report.
 - xxxii. The inability of the applicant to sustain operations can be attributed to multiple shutdowns, which signifies operational inefficiencies. Such shutdowns are likely on account of unavailability of raw material and commercial unviability due to fall in price of ECH and increase in price of glycerine.
 - xxxiii. As the domestic industry is a new entrant in the market, it would take some time to establish itself due to market dynamics and immediate switching of suppliers by the users is not the solution.
 - xxxiv. Quarterly fluctuation of inventory level considered in isolation cannot be indicative of injury as they must be analysed as long-term trends and in relation to other parameters such as sales price, sales volume, profit, etc.
 - xxxv. The increased inventories with the domestic industry are only due to preference of the user industry based on track record of the exporters, ongoing contracts and the difference in the quality of product delivered.
 - xxxvi. The contract period adopted by the pharmaceutical sector is January to December and thus, the applicant has not had the opportunity to establish itself.
 - xxxvii. The performance of the domestic industry must be analysed against the challenging conditions in which it entered the market.
 - xxxviii. The post-POI performance of the applicant must also be examined, as had been the practice of the Authority in the case of CPVC, Styrene Butadiene Rubber and Resins.

- xxxix. To eliminate the effects of change in production methods and procurement practice from refined to crude glycerine during the period of investigation, the claimed non-injurious price must be adjusted. The average cost of crude glycerine (and not refined glycerine) for the period of investigation should be considered, based on either actual price of imports into India or average ICIS prices and actual incremental cost of refining crude glycerine based on post-POI operations of the applicant may be considered. Further, the Authority must consider ***% as the optimum capacity utilization to determine optimum production to ensure that the non-injurious price is not affected by market dynamics which may have caused injury.
- xl. High depreciation and interest costs due to production inefficiencies, plant operating at reduced capacity and higher raw material consumption is likely to skew the calculation of non-injurious price and resultant injury.
- xli. The Authority must examine whether applicant has paid any royalty fee for technology transfer agreement to acquire the unconventional production technique, resulting in inflated cost of production.
- xl.ii. The inability to attain projected profitability of the domestic industry is not due to imports, but other factors.
- xl.iii. The domestic industry is focussed more on the export market and has even established storage tanks in major ports in Europe.
- xl.iv. Tamilnadu Petroproducts Limited established an ECH plant to cater to the needs of its JV company, Petro Araldite Pvt. Ltd. which ceased operations due to poor performance. This led to discontinuation of ECH operations by TPL.
- xl.v. The applicant has admitted in their earning calls that there is a decrease in the global demand for epoxy, fluctuations in the raw material prices and global economic slowdown.
- xl.vi. The effect of imports from Taiwan and other countries must be considered in the present investigation.
- xl.vii. The end-users prefer less of Chinese produced ECH.

H.2 Views of the domestic industry

68. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Injury and causal link are as follows.
- i. The imports from all the subject countries may be cumulatively analysed as the requirements under Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement and para (iii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules are all satisfied.
 - ii. Contrary to the contention of the interested parties, for the purpose of cumulative analysis, the Authority is not required to conduct country-wise volume and price analysis as pre-condition to cumulation as observed by the Appellate Body in EC-Tube or Pipe Fittings.
 - iii. The fact that the domestic industry was not operational for the entire period of investigation has no relevance to the present investigation as the underlying assumption in an analysis of material retardation is that the industry has not been in operation for a reasonable period of time.
 - iv. Contrary to the claims of the domestic industry, the differences in the prices of raw materials were adequately factored into the projections made by the domestic industry in the information submitted to the Authority.
 - v. Despite commencement of production in India during the period of investigation, the subject imports increased by 44% as compared to the base year and by 20% as compared to the previous year. Further, the volume of imports has remained high in the post-POI period as well.
 - vi. The subject imports have increased by 16% in relation to domestic consumption and were almost six times of the total domestic production.
 - vii. While the demand for the subject goods has increased by 23% over the period, the volume of imports increased at a much higher rate of 44%, during the same time.
 - viii. The subject imports are in excess of the demand-supply gap for ECH in India.
 - ix. The market share of the subject imports has increased from ***% in 2019-20 to ****% in 2022-23. In comparison, the domestic industry gained a minimal market share despite having the capacity to cater to more than ***% of the market.
 - x. The landed price of the subject imports continuously declined during each quarter of the period of investigation and such decline is higher than the decline in prices of raw material.

- xi. While the subject imports were priced higher than the non-subject imports till 2021-22, the price of the subject imports declined significantly in the period of investigation and were priced 13% lower than the non-subject imports.
- xii. Considering the prices of refined glycerine and caustic soda, while the subject goods were priced at least USD 700-1,000 higher than the raw material cost, the mark-up over raw material declined significantly in the period of investigation and was even negative in the third quarter. The trend of declining mark-up over raw material costs is visible even when prices of crude glycerine are considered.
- xiii. The foreign producers have deliberately reduced their export prices for the Indian market and the export price to India was significantly lower than export price to rest of the world and the next largest markets during the period of investigation.
- xiv. The subject imports were significantly undercutting the domestic prices and the target prices of the domestic industry, despite the fact that the domestic industry reduced its prices and chose to sustain losses. The stiff price competition from the subject imports has continued in the post-POI period as well.
- xv. The lower priced imports have depressed the prices of the domestic industry, as it was forced to reduce its selling price, at a much higher rate than the decline in the price of crude glycerine and caustic soda, in order to compete with significantly lower landed prices.
- xvi. While the prices of raw material declined during the period of investigation, the prices of ECH declined at a much sharper rate.
- xvii. The other interested parties are attempting to mislead the investigation by citing simple price differences between crude and refined glycerine without any basis. If the prices of ECH are compared with the prices of refined glycerine or crude glycerine, it would show an inordinate decline in price of the subject imports.
- xviii. The other interested parties have failed to provide any evidence in support of their claim that the prices of the subject goods have moved in tandem with global indices.
- xix. The producer in Thailand, AGC Vinythai, has engaged in aggressive pricing as it is forced to run its ECH plant in order ensure consumption of hydrochloric acid gas, generated as a by-product from its PVC plant.
- xx. The domestic industry commenced operations with a high capacity utilization, but was forced to curtail production due to minimal market share and accumulation of inventories and utilized less than 1/3rd of its capacity. Such production and capacity utilization are much lower than the projected levels due to incessant dumping.
- xxi. The domestic industry was forced to suspend production only after 3 months of operations and the production remained suspended for the entire third quarter. The production was also suspended for more than 2 months in post-POI period.
- xxii. The subject imports have adversely affected the ability of the domestic industry to sell in the market and its domestic sales accounted for a minimal share of its capacities and less than half of its total production.
- xxiii. The domestic sales and market share of the domestic industry are much lower than their projections. Further, the sales of the domestic industry are lower than its projections even in the second year of operations.
- xxiv. A minor increase in the market share of the domestic industry cannot be treated as absence of injury, since any producer commencing production expects to gradually gain market share.
- xxv. The domestic industry has accumulated inventories, which are significantly higher than its production in certain months and domestic sales throughout the period of investigation. Further, the inventories were significantly higher than the projected levels and have continued to remain high in the second year of operations.
- xxvi. The inventory holding period in relation to domestic sales was more than one year and in relation to production was equivalent to six months.
- xxvii. Despite earning profits in the first month of operation, the domestic industry faced significant losses, cash losses and negative return on investment as the foreign producers aggressively reduced their prices. The losses suffered were in contrast to projected profitability in the first year of operations.
- xxviii. The subject imports have forced the domestic industry to sell below its variable cost and as a result, the

- contribution of the domestic industry became negative during the period of investigation.
- xxix. At current prices, the domestic industry would have faced significant losses even if it operated at the projected capacity utilization and it would have been impossible to break-even.
 - xxx. The profitability of the domestic industry was the highest when the prices of glycerine were higher, while the profitability deteriorated as the prices of glycerine declined.
 - xxxi. The refined glycerine imported by the domestic industry was sufficient to be utilized within a quarter, but the same was stocked for a longer period as the subject imports prevented the domestic industry from utilizing its capacities. In any case, the domestic industry would have suffered higher losses, had it procured raw material at prices prevailing during the period of investigation or if it has used crude glycerine as raw material.
 - xxxii. The other interested parties have made references to the statements made by the applicant in its annual report and quarterly earnings calls in isolation and have not provided the context or complete references, in order to suit their purpose.
 - xxxiii. There is no provision under the law which provides substitution of the raw material cost of the domestic industry for a different raw material and the costs as recorded in the books of the domestic industry must be considered. In any case, the raw material costs are higher.
 - xxxiv. The provisions of Annexure III allow consideration of best utilization of production capacities over the period and not the optimum utilization of capacities. Even if the Authority considers the optimum utilization, the same should be based on projected utilization, and not 100%. Further, where the domestic industry is operating at such low utilization, it would not deploy resources and incur expenses as it would if it was operational at full capacities.
 - xxxv. The other interested parties have not cited any production inefficiencies which would lead to higher costs. The domestic industry has claimed non-injurious price considering optimum utilization of glycerine, which is anyway lower than average industry consumption.
 - xxxvi. Injury to the domestic industry must be seen as it exists and a non-attribution analysis is not required to be conducted with regards to factors inherent to the domestic industry, as held by the WTO Appellate Body in EU – Biodiesel (Argentina), the CESTAT in Nippon Zeon Co. Ltd. v. DA and the Authority itself in past investigations.
 - xxxvii. There were no contracts that prevented the user industry from procuring goods from the domestic industry as users typically enter into contract for only 50-60% of their demand, while the remaining demand is fulfilled on spot basis. Further, existence of contracts cannot justify extremely low-priced imports.
 - xxxviii. The pharmaceutical industry purchases goods on spot basis or under quarterly contracts and are not limited by any annual contracts. In any case, the domestic industry has been in operation for almost two years and have still continued to suffer, implying that low sales of the domestic industry are not due to contract period of pharmaceutical industry. Moreover, the pharmaceutical industry does not account for a large share of the total consumption.
 - xxxix. While one of the major epoxy producers purchased high volumes from the domestic industry, it started importing ECH once the prices started declining, thereby indicating that the users are not limited by any contracts but by availability of cheap products.
 - xl. The domestic industry has exported its goods at higher prices, which implied that the product of the domestic industry does not suffer from quality issues.
 - xli. The shutdown faced by the domestic industry was not due to raw material shortage, fluctuation in raw material prices, legal compliances, power shortage, lack of adequate capacity or investment capacities.
 - xlii. The domestic industry has not added any technology transfer fees to its cost of production. In any case, any producer using a technology would pay such fees and the same is not unique to the domestic industry.
 - xliii. Other than the subject countries, there are significant imports only from Taiwan, but such imports are higher priced and have not caused injury to domestic industry.

H.3 Examination by the Authority

- 69. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles

and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

70. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority has noted that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking a detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry was an established industry to such an extent that the same permits assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was an embryonic or nascent industry, in the process of establishment, and not having sufficient past history to permit assessment of injury in the form of material injury.

H.3.1 Material retardation to establishment of an industry

71. It is seen that the WTO Anti-dumping Agreement or the Rules do not provide a definition for 'material retardation'. Footnote 9 to Article 3 of the WTO Agreement merely states as follows –

"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article."

72. Similarly, Annexure II to the Rules merely clubs 'material injury', 'threat to material injury' and 'material retardation' under the definition of injury. There is no further explanation to what constitutes material retardation to the establishment of an industry.

73. It is, however, clear that 'material retardation' to an industry would be in reference to an unestablished industry and not an industry that is fully established. This is true because it is not logical for the Authority to find that a domestic industry was being injured by the dumped imports (which presupposes that such an industry was already established) and at the same time, it finds that the establishment of a domestic industry was materially retarded by those imports. The term 'unestablished' industry has not been provided in the WTO Agreement, the Act or the Rules. However, there has been a proposal at the WTO for an amendment to the Anti-dumping Agreement which provides some clarity as to the meaning of material retardation and the establishment of an industry. The relevant extract of the draft proposal is reproduced hereinbelow. Even though the said provision has not been incorporated in the Agreement so far, the Authority has considered the same as well for making the present determination:

"3.9. A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made, and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies."

74. In Morocco - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel laid down some guidance on determining whether there is an establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. Accordingly, the Authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.
75. The Panel also observed that the Authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new 'product line' of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered an 'unestablished industry'. To examine this factor, the Authority would have to look into the degree of overlap in the use of the overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). A greater degree of overlap with the old infrastructure would mean that it is less likely that a new industry has been established. The relevant portion of the Panel's observation is provided as under.

“7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or whether they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic industry is unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the domestic industry is the only producer of the like product in question in the market. At the same time, we note that whilst there could be only one producer of that product in the market, where that product constitutes merely a new “product line” of an existing industry and benefits from the existing production, marketing and other operations, such shared operations may play an important role in determining whether a distinct new industry has been established. If an existing industry chooses to introduce a new product unlike any other product currently being produced, the introduction of that new product will not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be perceived as the introduction of a new product line into the existing industry, depending on the degree to which the overall infrastructure (including the productive, commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is implicated. The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely the perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing producers of that like product in the domestic market, does not preclude the possibility of that domestic industry utilizing existing infrastructure such as customer contacts and distribution channels, in its introduction of that like product in the domestic market.”

76. Considering the above and in the absence of any prescribed methodology that the Authority must follow in deciding whether a domestic industry is established, the Authority has analysed the following parameters while examining whether the case is fit to examine material retardation.

H.3.2 Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present

77. It is seen that the applicant has set up a new manufacturing facility for the production of the subject goods by making significant investments. Prior to the commencement of production by the domestic industry, the entire demand for the subject goods was being satisfied by imports. Based on the factors examined below, it is seen that the domestic industry in the present case has not been established and the injury caused to the industry is in the nature of material retardation.

a. Commencement of production by the domestic industry

78. The domestic industry started commercial production during the period of investigation. Although the production of the subject goods has commenced in India, yet the performance of the domestic is below its projected figures. The production of the domestic industry during the period of investigation was only ***% of its projected production volume, at capacity utilization of only ***%. As against this situation, the domestic industry projected to achieve a capacity utilization of ***% in the first year of operation, implying a production of *** MT. Thus, the domestic industry has failed to achieve its projected performance due to the presence of dumped imports.

b. Whether the production of the subject goods is merely a new product line in an existing industry?

79. As mentioned hereinabove, the WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the product under consideration. Further, the Panel observed that in addition to a new product line, the Authority must examine the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry.

80. It is seen that the domestic industry set up a new manufacturing plant for the subject goods and started commercial production in July 2022. Further, since a new plant or production line was set up to manufacture the subject goods, there is no overlap between the existing infrastructure and the new plant that has been set up.

c. Size of production and capacity in comparison to the size of the domestic market as a whole

81. The domestic industry set up capacities during the period of investigation, which were sufficient to cater to ***% of the market. However, despite having sufficient capacities, the domestic industry was unable to fully utilize its capacities. Further, as against a production of *** MT, the domestic industry was able to sell only *** MT in the domestic market. While the subject imports commanded a market share of **%, the domestic industry was able to cater to only ***% of the market. This shows that the imports prevented the domestic industry from supplying its production in the market.

d. Stability of operations as compared to projected operations

82. The performance achieved by the domestic industry in respect of various macro- economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, market share, profits, cash profits and return on capital employed is materially below the levels projected by the domestic industry at the time of making investments. While the domestic industry was in a position to cater to more than 50% of the demand, its market share has

been limited to only ***%. Further, the domestic industry had projected profits in its very first year of operations. However, the domestic industry has not been able to recover its costs and even variable costs and is suffering significant financial losses. Further, the difference between the projected performance and actual performance achieved is too significant.

H.3.3 Cumulative assessment of injury

83. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

84. With regards to the argument raised by the other interested parties that imports from China do not have the ability to impact the volume or prices of the domestic industry, the Authority notes that Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement as well as Para (iii) of Annexure II expressly provide the conditions to be satisfied before conducting a cumulative analysis of imports from all the subject countries. Such provisions do not require the Authority to undertake a country-wise analysis of prices as a condition prior to such cumulation. Such view has also been taken in the Appellate Body report in EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [DS/129/AB], wherein it was held as follows –

“110. We find no basis in the text of Article 3.3 for Brazil's assertion that a country-specific analysis of the potential negative effects of volumes and prices of dumped imports is a pre-condition for a cumulative assessment of the effects of all dumped imports. Article 3.3 sets out expressly the conditions that must be fulfilled before the investigating authorities may cumulatively assess the effects of dumped imports from more than one country. There is no reference to the country-by-country volume and price analyses that Brazil contends are pre-conditions to cumulation. In fact, Article 3.3 expressly requires an investigating authority to examine country-specific volumes, not in the manner suggested by Brazil, but for purposes of determining whether the 'volume of imports from each country is not negligible'.”

85. Further, the Government of Thailand has claimed that imports from Thailand do not have the same conditions of competition as the imports from China PR and Korea RP since the trends of volume of imports from Thailand are not similar to imports from such other subject countries. However, it is noted that analysis of similar volume and market share trends of imports cannot be considered as a criterion alone to determine whether the imports from one country are competing with imports from other countries. Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement places no such obligation on the investigating Authority. This has been affirmed by the WTO Panel in its report in European Union – Anti-dumping Measures on Certain Footwear from China [WT/DS405/R], as can be seen from the following –

“7.404 Turning to the alleged violation of Article 3.3, we see no basis in the text of Article 3.3 for China's view that an investigating authority must establish that imports from different countries have similar volume and market share trends, or that the conditions of competition in the different exporting countries were "similar" or "normal", in order to conclude that a cumulative assessment is appropriate in light of the "conditions of competition". As we observed above, Article 3.3 contains no specific mandatory or indicative factors that should be considered in assessing whether cumulative analysis is appropriate in light of the "conditions of competition". We note in this regard that the Appellate Body has rejected arguments that would create additional obligations under Article 3.3 of the AD Agreement.”

86. Thus, merely because the volume trends of imports from Thailand have not moved in line with the imports from other countries, it cannot be said that such imports are not competing inter se. On the other hand, the imports from Thailand are commercially and technically substitutable with imports from other subject countries and with the like article produced by the domestic industry. Further, the subject goods imported from Thailand are used for same end-use application as the imports from other subject countries and the like article produced in India. Therefore, it is noted that imports from Thailand are directly competing with the imports from China PR and Korea RP.

87. In view of the above, the Authority concludes that:

- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

88. Accordingly, the Authority concludes that it would be appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

H.3.4 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

89. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	0	0	0	100
Subject imports	MT	46,202	40,906	69,292	81,388
Other imports	MT	14,003	17,041	9,192	4,822
Consumption / Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	130	150

90. It is seen that the demand for the subject goods declined in 2020-21, but increased thereafter in 2021-22 as well as in the period of investigation. The decline in demand during 2020-21 may be on account of Covid-19.

b) Import Volumes from the subject countries

91. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DG Systems. The import volumes of the subject goods from the subject country and the share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject imports	MT	46,202	40,906	69,292	81,388
Thailand	MT	43,036	35,456	62,598	67,195
China	MT	92	1,360	3,943	8,339
Korea	MT	3,074	4,090	2,752	5,854
Other imports	MT	14,003	17,041	9,192	4,822
Total imports	MT	60,205	57,947	78,484	86,210
Sales of Domestic Industry	MT	0	0	0	***
Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	130	150
Total Indian production	MT	0	0	0	***
Trend	Indexed				100
Subject import in relation to:					
Total imports	%	77%	71%	88%	94%

Demand/Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	115	118
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	0	0	0	100

92. It is seen that-

- The volume of imports of the subject goods declined in 2020-21, but increased thereafter in 2021-22 as well as in the period of investigation.
- The imports have increased despite the commencement of production by the domestic industry during the period of investigation.
- The imports accounted for almost ***% of consumption in India in the period of investigation. This is despite the fact that the domestic industry commenced production during this period, and had the capacity to cater to a significant share of the demand.
- The present volume of imports is inordinately high, having regard to the demand-supply situation in the country.
- Prior to the period of investigation, there was no production of the subject goods. However, even during the period of investigation, the volume of imports in relation to domestic production was more than seven times, despite the domestic industry commencing production.
- The imports from the subject countries account for 94% of the total imports in the period of investigation.
- The imports have increased at a much higher rate than the rate of increase in the demand for the subject goods. While the demand has increased by 50% over the period, the subject imports have increased by 76%.

93. The information provided by the domestic industry, and verified from the Trade Map, also shows that India is the largest export market for Thai producers, accounting for ***% of their exports. Further, India is the second largest export market for the producers in China and Korea, demonstrating that the Indian market is a key market for the producers in the subject countries.

H.3.5 Price effect of the dumped imports

94. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

95. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation, for each quarter. The weighted average price undercutting is as below. It is seen that the price undercutting is positive and significant during the period of investigation.

Particulars	Unit	Q1	Q2	Q3	Q4	POI
Landed price	₹/MT	2,22,886	1,99,157	1,29,997	1,14,403	1,66,530
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	76	51	44	68
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	15-25%	0-10%	0-10%	0-10%	5-15%

**Weighted average of quarterly selling prices based on the volume of imports*

96. The domestic industry has also submitted that the landed prices of the imports is even below its projected selling price, with an even higher price undercutting. If the projected selling price of the domestic industry is considered, it would be seen that the subject imports were undercutting the target prices of the domestic

industry.

Particulars	Unit	POI
Landed price	₹/MT	1,66,530
Target price	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	10-20%

b) Price suppression/depression

97. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below.

Particular	Unit	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	106	104
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	76	51	44
Landed Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	58	51

98. It is noted that in the second quarter, the cost of sales of the domestic industry increased whereas the selling price of the domestic industry declined significantly. Thereafter, in the third and fourth quarters, the cost of sales of the domestic industry declined. However, the selling price of the domestic industry declined at a much higher rate than the decline in the cost of sales, in order to compete with the landed price of imports. Further, the landed price of the imports remained significantly below the cost of sales of the domestic industry. Thus, it is noted that the subject imports have depressed the prices of the domestic industry. The applicant has also submitted that the imports have prevented them from achieving their target price as projected in their project report and they have been forced to sell the subject goods below their costs.

c) Landed price below the raw material cost of the domestic industry

99. The applicant has also claimed that the landed price of imports has reduced below the cost of raw materials in the second half of the period of investigation. It is seen that during the initial period of the injury period, the prices of ECH were much higher than the raw material cost. The prices of ECH started declining in the first half of 2022-23 when the domestic industry commenced production. However, in the last two quarters, the landed price of imports was lower than the cost of raw materials consumed. During the course of the investigation, the other interested parties argued that the domestic industry was unable to recover its costs as the domestic industry used refined glycerine in the production process, instead of crude glycerine. It was claimed that the domestic industry purchased high-priced refined glycerine, instead of the crude glycerine which was more cost efficient. In response, the domestic industry provided the international prices of crude glycerine to demonstrate that the price of ECH was lower than the prices of crude glycerine as well. It is noted that the producers in Thailand and China are also producing ECH using refined glycerine. Nevertheless, as highlighted by the domestic industry, even if the prices of crude glycerine are considered, the prices of ECH have followed a similar trend. While the mark-up over raw material cost was healthy till the first half of the period of investigation, it declined sharply in the second half of the period of investigation when the domestic industry commenced production.

Figures in USD/MT

Quarters	Import price of ECH into	Caustic Soda Prices	Refined Glycerine Prices	RM cost Considering refined glycerine	Mark-up over cost (ECH prices –	Crude glycerine Prices	RM cost Considering crude glycerine	Mark-up over cost (ECH prices –
----------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	India			price	RM)		price	RM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20 Q1	1,608	239	711	800-850	750-800	259	425-475	1125-1175
2019-20 Q2	1,696	224	645	750-800	900-950	223	375-425	1275-1325
2019-20 Q3	1,786	214	638	725-775	1000-1050	233	375-425	1350-1400
2019-20 Q4	1,625	194	617	800-750	950-900	229	375-425	1200-1250
2020-21 Q1	1,512	200	692	750-800	700-750	252	400-450	1050-1100
2020-21 Q2	1,355	204	775	850-900	450-500	292	450-500	850-900
2020-21 Q3	1,286	191	712	800-850	450-500	289	450-500	800-850
2020-21 Q4	1,528	174	790	850-900	600-650	355	525-575	950-1000
2021-22 Q1	1,972	183	874	950-1000	950-1000	440	425-475	1275-1325
2021-22 Q2	2,338	212	1,036	1100-1150	1150-1200	568	375-425	1450-1500
2021-22 Q3	2,597	288	1,246	1375-1425	1150-1200	677	375-425	1550-1600
2021-22 Q4	2,645	390	1,574	1750-1800	850-900	757	375-425	1450-1500
2022-23 Q1	2,845	456	1,834	2050-2100	750-800	773	400-450	1575-1625
2022-23 Q2	2,548	485	1,730	1950-2000	550-600	732	1000-1050	1325-1375
2022-23 Q3	1,580	555	1,309	1575-1625	(50)-0	493	1150-1200	650-700
2022-23 Q4	1,379	530	1,051	1300-1350	50-100	351	1200-1250	650-700

100. As a result, the domestic industry has been unable to recover their variable costs as well which has resulted in a negative contribution. As against a variable cost of ₹ *** per MT, the domestic industry was able to recover only ₹ *** per MT.

H.3.6 Economic parameters of the domestic industry

101. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

102. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below. It may be noted that while the domestic industry established a capacity of 50,000 MT, the same has been proportionately adjusted since the domestic industry commenced operations in June 2022.

Particular	Unit	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4	POI	Projected
Installed Capacity	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	300	300	300	300	300
Production	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	0	168	113	254

Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	36	0	56	38	85
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	445	309	760	484	2,903
Export Sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1144	117	103	439	
Shut down days	No. of days	***	***	***	***	***	***

103. It is seen that:

- The domestic industry achieved a reasonably high level of capacity utilization, of **%, in the first quarter itself. However, its capacity utilization declined subsequently.
- The domestic industry has not been able to fully utilize its capacities and was able to achieve a low utilisation of less than **%, as against a projected utilization of **%. Almost three-fourths of the capacity set up by the domestic industry remained idle during the period of investigation.
- The actual production of the domestic industry is **% lower than the projected production.
- The domestic sales of the domestic industry have remained low throughout the period, and are only **% of the projected sales volume.
- The domestic sales are only **% of the capacity. Further, the domestic industry has been able to dispose of only **% of its production in the domestic market.
- Since the domestic industry was not able to dispose of its production, it was forced to shut down its plant for significant periods. Since commencement of production in June 2022, the applicant was forced to shut down operations for a significant period of time owing to commercial unviability of operations. Of the total *** days of commencement of production, the domestic industry has remained shut down for more than 50% of the days.

104. Some of the interested parties have claimed that the domestic industry has focused on export markets. However, the Authority notes that the domestic industry is sitting with significant idle capacities. Therefore, even after effecting exports, the domestic industry had the ability to cater to a larger share of the domestic market. However, its market share has remained low.

b) Market share

105. The market share of the domestic industry and of imports are as shown in table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	115	118
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	50	23
Domestic industry	%	-	-	-	***
Trend	Indexed	-	-	-	100

106. The Authority notes that since the domestic industry commenced production in the period of investigation, its market share improved. However, the subject imports accounted for almost 90% of the market share during the period of investigation, despite there being sufficient idle capacities with the domestic industry. Even while having a capacity sufficient to cater to more than half of the demand, the market share of the domestic industry was only **%, which is much lower than the projected market share of **%.

c) Inventories

107. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particular	Unit	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4	POI	Projected
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----	-----------

Opening Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	99	139	197	57

108. It is noted that –

- The average inventories with the domestic industry have increased during the period of investigation as they have been unable to sell in the domestic market.
- The average inventories of the domestic industry are almost equal to half of their total production volume, despite undertaking exports of the subject goods.
- Further, the inventories are equivalent to 91% of the domestic sales volume, implying that the domestic industry has hardly been able to sell the goods.
- The inventory holding period of the domestic industry is extremely high, equivalent to more than one year in relation to domestic sales and almost six months in relation to production.
- The average inventories of the domestic industry were higher than the domestic sales of the domestic industry during each month of the period of investigation and exceeded production in all but one month of its operations.
- The average inventories are much higher than the projected inventories, despite the projection being at a higher capacity utilization.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

109. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	106	104
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	76	51	44
Profit/ (loss)	₹/MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-47	-112	-132
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-208	-344	-1007
Cash Profit	₹ Lacs	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-110	-237	-638
Return of investment	%	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-82	-229	-695

110. It is seen that while the domestic industry initially earned profits in the first quarter, it has suffered significant losses from the second quarter onwards and its losses have increased in each quarter. Further, the cash profits and return on investment of the domestic industry have followed a similar trend. The domestic industry has incurred significant cash losses and its return on investment has become negative from the second quarter.

111. The applicant has claimed that the decline in profitability of the domestic industry is directly attributable to the decline in landed prices. It is noted that during the second quarter, and subsequently, the gap between the landed price and raw material cost declined sharply, with the landed price subsequently becoming lower than the raw material cost. This led to a significant impact on the profitability of the domestic industry, which deteriorated rapidly.

112. The applicant has also claimed that since the domestic industry commenced production only in the period of

investigation, its performance should also be analysed by comparing its actual performance with the projected performance considering cost structures at 80% utilization. Accordingly, the Authority has analysed the performance of the domestic industry as below.

Particulars	Unit	POI (Actual)	Projected	Normated
Cost of sales	₹/MT	***	***	***
Selling price	₹/MT	***	***	***
Profit/ (loss)	₹/MT	(***)	***	(***)
Profit/ (loss)	₹ Lacs	(***)	***	(***)
Cash Profit	₹/MT	(***)	***	(***)
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	***	(***)
Return of investment	%	(0-10)%	10-20%	(0-10)%

113. It is noted that:

- While the domestic industry projected to achieve profits of ₹ ***crores in the period of investigation, it incurred significant losses of *** crores during such period. Further, even if the domestic industry operated at a capacity utilization of 80%, it would still incur losses at current prices.
- Similarly, the domestic industry has incurred cash losses of *** crores while it had projected cash profit of *** crores. The domestic industry would have incurred significant cash losses even if it operated at 80% capacity utilization.
- The return on investment of the domestic industry remained negative, in contrast with a projected return of ***.
- The domestic industry has also highlighted that it was forced to sell below its variable cost of production during the fourth quarter of the period of investigation. As a result, it has become impossible for the domestic industry to break even.

e) Employment, productivity and wages

114. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4	POI
No of employees	Nos.	***	***	-	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	-	***	***
Trend	Indexed	100	108	-	168	113
Productivity per day	MT/Days	***	***	-	***	***
Trend	Indexed	***	***	***	***	***
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	-	***	***
Trend	Indexed	100	108	0	168	94

115. It is seen that the number of employees has remained stable throughout the period of investigation while the salaries have increased. The production of the domestic industry declined in the second quarter and was zero in the third quarter as the domestic industry shut down its operations. However, productivity improved in the last quarter as the domestic industry increased its production volumes. The domestic industry has not claimed injury on this account.

f) Growth

Particulars	Unit	2022-23 Q1	2022-23 Q2	2022-23 Q3	2022-23 Q4
Production	%	-	8%	-100%	100%
Domestic sales	%	-	345%	-31%	146%

Profit / loss	%	-	-309%	-65%	-192%
Profit / loss per unit	%	-	-147%	-138%	-18%
Cash Profit	%	-	-210%	-116%	-169%
Return on investment	%	-	-182%	-179%	-204%

116. As the domestic industry commenced production during the period of investigation, its volume parameters improved, after dipping in the third quarter. However, the profitability parameters of the domestic industry have declined in each quarter of the period of investigation and have not improved in any quarter.

g) Impact on the ability to raise capital investments

117. The domestic industry had sourced investment for setting up capacity for the subject goods and was able to raise capital investment. The domestic industry has submitted that the volume of imports has continued to remain higher in the post-POI period upto December 2023, despite the domestic industry being in operation for more than one year. Due to the continued influx of imports, the domestic industry has been unable to increase its domestic sales, which have remained low. This has led to a significant accumulation of inventories, which is higher than the production and sales levels of the domestic industry in each of the months. As a consequence, the domestic industry was forced to undertake another shutdown for almost 2.5 months in the post-POI period. Further, the domestic industry has continued to suffer significant losses, negative cash flows and return on capital employed. Some of the interested parties had highlighted that the losses of the domestic industry were on account of the fact that it produced the like article using refined glycerine for part of the period of investigation. However, the Authority notes that the domestic industry clarified that during the post-POI period, it produced the like article using crude glycerine. However, even then, it has suffered significant losses.

H.3.7 Overall assessment of injury

118. The examination of the imports of the subject product and the performance of domestic industry clearly shows that:
- The volume of imports has increased significantly despite the fact that the domestic industry commenced operations. Further, the imports increased at a much higher rate than the increase in demand for the subject goods.
 - The imports have remained high in relation to production and consumption.
 - The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry, and have prevented the domestic industry from achieving its projected prices.
 - The prices of the subject imports declined sharply during the period of investigation and were undercutting the actual and projected prices of the domestic industry.
 - The landed price of imports is lower than the variable cost of the domestic industry in the last two-quarters of the period of investigation.
 - The gap between the price of imports and the prices of raw materials has declined steeply over the period.
 - Due to the cheaper imports, the domestic industry was forced to sell below its cost of sales and its variable costs.
 - The domestic industry has been able to utilize less than 30% of its capacity, which is much below the projected utilization.
 - The domestic industry was able to sell only slightly over half of its production volumes, that too having exported some volumes. On the other hand, the volume of domestic sales in the domestic industry has remained low.
 - The domestic industry was forced to undertake plant shutdowns, due to commercial unviability in the market.
 - The domestic industry faced a significant accumulation of inventories in its first year of operation. Its inventories were more than the domestic sales during each month of the period of investigation.
 - The profitability of the domestic industry deteriorated over the period, with increasing losses, cash losses, and negative return on capital employed.

- xiii. The domestic industry faced significant losses, cash losses and negative returns on investment during the period of investigation as against the projected profitability.
- xiv. The domestic industry would have faced losses, cash losses and negative returns at present prices even if it operated at 80% capacity utilization.
- xv. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
- xvi. The dumping margin is positive and significant.
- xvii. The imports are affecting the prices of the domestic industry.
- xviii. The performance of the domestic industry has continued to remain adverse even during the post-POI period.

119. In view of the foregoing, it is provisionally concluded that the subject imports have materially retarded the establishment of industry in India.

H. **NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

120. As per the Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury, which has resulted in the material retardation to the establishment of the domestic industry.

a. **Volume and price of imports from third countries**

121. The Authority notes that other than the subject imports, there were significant imports only from Taiwan and not from any other non-subject source. However, the subject goods were not exported at dumped prices from Taiwan during the period of investigation. Thus, the injury caused to the domestic industry cannot be attributed to the imports from Taiwan.

b. **Contraction of demand**

122. It is seen that demand for the product under consideration has steadily increased with only a slight decline in 2020-21. The demand for the subject goods is also expected to continue to grow and thus, the domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c. **Changes in the pattern of consumption**

123. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. **Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers**

124. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country. Since the domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country, there is no possibility of *inter-se* competition between the domestic producers causing injury to the domestic industry.

e. **Developments in technology**

125. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration. The applicant has in fact set up a new production facility.

f. **Export performance**

126. The Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be, for the purpose of injury analysis of the domestic industry.

g. **Use of inventories of raw materials**

127. Some of the interested parties have also contended that the profitability of the domestic industry is low since it uses inventories of raw materials purchased at high prices. In response to such contention, the domestic industry submitted information with regard to the profitability of the domestic industry, based on international prices of the raw materials. On the basis of the information provided, the Authority notes that the domestic industry would have suffered losses, even if it had purchased raw materials at international prices.

Particulars	Unit	Present performance	If international prices are considered
-------------	------	---------------------	--

Domestic Sales	MT	***	***
Cost of Production	₹/MT	***	***
Selling Price	₹/MT	***	***
Profit/(Loss)	₹/MT	(***)	(***)
Profit/(Loss)	₹ Lacs	(***)	(***)

h. Impact of start-up costs on the cost of production

128. The other interested parties have also argued that the cost of production of the domestic industry is inflated due to the start-up costs involved. However, the domestic industry has submitted that any start-up costs have been capitalized in the cost of assets and have not been included in the cost of production. Thus, the cost of production of the domestic industry is not inflated on account of any start-up costs.

i. Issues regarding the quality or acceptability of the product

129. Some of the interested parties have alleged that the domestic industry might have struggled to sell goods in the domestic market owing to the long approval process or issues with the acceptability of the product. However, the Authority notes that the domestic industry has been able to supply the goods in the export markets and that too, at profitable prices. Therefore, the fact that the domestic industry has been able to sell its goods in the export markets demonstrates that the product produced by it has been accepted globally. Further, the domestic industry has even submitted that it was able to sell its goods to customers in India before the import prices started declining to injurious levels.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

130. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been compared with the landed price of subject goods from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the PUC has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.
131. Some of the interested parties have claimed that the raw material cost of the domestic industry should be adjusted to reflect the international prices and royalty expenses should not be considered. However, in accordance with the provisions of Annexure-III and as per practice, the Authority has considered the raw material cost and other expenses, as reflected in the books of accounts of the company, duly adjusted in accordance with the principles laid down in the law.
132. Since start-up costs are capitalized, the cost of production of the domestic industry is not inflated on this account. As regards depreciation, the Authority has considered the same based on the highest capacity utilization, of more than 80% achieved during the period of investigation.
133. With regards the argument raised by other interested parties that the injury margin should not be determined by considering only the injurious volume of imports as claimed by the domestic industry, it may be noted that the Authority has determined the landed price of all imports for each quarter of the period of investigation and compared the same with the non-injurious price of the domestic industry to calculate the injury margin.
134. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority on a quarterly basis and is provided in the table below:

Injury Margin Table

S.N.	Producers	NIP	LP	IM	IM	Range
A	Thailand	\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	
1	AGC Vinythai Public Company Limited (AVT) (Formerly known as Advanced Biochemical (Thailand) Co., Ltd.)	***	***	***	***	20-30%

2	Any Other	***	***	***	***	20-30%
B	Korea RP	***	***	***	***	
1	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	10-20%
2	Lotte Fine Chemical Co. Ltd	***	***	***	***	20-30%
3	Any Other	***	***	***	***	25-35%
C	China PR	***	***	***	***	
1	Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10%
2	Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd.	***	***	(***)	(***) %	Negative
3	Any Other	***	***	***	***	5-15%

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions by other interested parties

135. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. The applicant has misrepresented the impact of proposed duties by overstating the market price of epoxy resin in its calculation. The impact on epoxy producers ranges from 0% to 10% and is significant.
- ii. Imposition of duty is likely to result in an inverted duty structure for epoxy resins as the imports would be subject to basic customs duty (which is 0 for FTA partners) while epoxy producers in India would be subject to additional anti-dumping duty.
- iii. The impact of the imposition of duty is detrimental to the epoxy industry and the various downstream sectors such as paints and coatings, electronics, adhesives, water treatment chemicals, textiles, paper industry, etc. The epoxy producers would be unable to bear the increase in cost due to duty imposition and the same would be passed on to the customers, rendering the user industry uncompetitive.
- iv. Imposition of duty will negatively impact the rising foreign direct investments for the manufacture of epoxy in India and would deter entities such as Kukdo Chemicals who are planning to invest in the Indian epoxy sector.
- v. Imposition of anti-dumping duty would negatively impact the demand and prices of the upstream refined glycerine industry.
- vi. Imposition of anti-dumping duties on the subject goods would have a negative impact on the end-users as the end-users prefer importing the subject goods.
- vii. The domestic industry is unable to meet the volume requirements of the users as per confidential communication between the applicant and one of the users.
- viii. The domestic demand at present cannot be satisfied by the existing domestic production capacity.
- ix. Make In India and Atmanirbhar Bharat are beyond the scope of the present investigation.
- x. Duty concessions have been granted in the Union Budget 2023 on imports of crude glycerine specially for use in ECH.

K.2 Submissions by the domestic industry

136. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. The imposition of anti-dumping duty would be in the interest of the domestic industry, consumers, users and the public at large.
- ii. There is a need to make India self-reliant for ECH as the country was entirely dependent on imports, post cessation of operations by Tamilnadu Petroproducts Limited.
- iii. Imposition of duty to the extent claimed by the domestic industry would result in a maximum price increase which would still be lower than the prices charged by the exporters in the past. ECH purchased from the domestic industry at fair prices would result in a benefit of at least ₹ 185 crores to the consumers.
- iv. The users have themselves acknowledged in their written submissions that they would simply pass on the price increases to their end-consumers and as a result, the impact of even a 10% increase would be negligible on the end-consumers.

- v. Imposition of duties would help in the establishment of the ECH industry in India, which would increase the demand and prices of the upstream producers and would not negatively impact them.
- vi. Kukdo Chemicals has set up its plant for the production of further downstream products and since the upcoming epoxy plant would be feeding its existing plant, imposition of duties would have no impact on such investment.
- vii. The imports are currently threatening the viability of fresh investments of more than ₹ 1,300 crores in the country and there is a need to protect such massive investments.
- viii. As against a possible inflow of FDI of ₹ 250 crores considering Kukdo Chemicals' future investment, the Indian investment in like article of ₹ 1,000 crores cannot be allowed to suffer.
- ix. Post imposition of duty, the Indian industry would have sufficient capacities to cater to the entirety of the demand for the next five years.
- x. Other than the subject countries, producers in USA, Germany, Taiwan, Japan, Netherlands, Saudi Arabia, France, Italy and Czech Republic have significant capacities and may be able to divert their goods to the Indian market, if the subject imports decline hypothetically.
- xi. It is a well-established principle that demand-supply gap cannot be a ground for non-imposition of duties, as held by the High Court in *NOCIL Limited v. Government of India*, the *CESTAT in DSM Idemitsu Ltd. v. DA* and the Authority in past findings.
- xii. Imposition of duty would lead to conservation of foreign exchange by USD 639 lakhs per annum.
- xiii. The presence of a competitive domestic industry would ensure that the foreign exporters do not charge premium pricing from the Indian consumers, which was done in past as is evident from the high delta over raw material cost.
- xiv. There would not be a situation of monopolistic behaviour by the domestic industry as the Indian market is likely to be in a situation of oversupply by the time duties are imposed.
- xv. The domestic industry is producing ECH using bio-based glycerine route which is better for the environment, as compared to the traditional propylene route.
- xvi. There is an inverted duty structure with regards to the product under consideration, which has not been taken into account in the present investigation.
- xvii. The volume of imports of epoxy resin is presently very low. Kukdo Chemicals accounts for a majority of the share of imports, who are themselves in the process of setting up a plant for epoxy resin in India, which would result in further decline in the volume of imports.
- xviii. Imposition of duties would be advantageous for the users as the increase in import price post imposition of duties would still be lower than the normal value in the domestic market of the subject countries.
- xix. The end-users have preferred the subject imports over the domestic goods only because the subject imports are available at cheaper prices and not due to any other reason.
- xx. The applicant has not claimed imposition of duties only in support of Make In India and Atmanirbhar Bharat policies of the Government, but rather to further such policies.

K.3 Examination by the Authority

137. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the continuation of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
138. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An economic interest questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

139. The Authority notes that the response to the economic interest questionnaire, issued by it, was furnished by the domestic industry and by four users of the subject goods namely Atul Limited, Cardolite Speciality Chemicals India LLP, Grasim Industries Limited and Hindusthan Speciality Chemicals Limited. In its response to the economic interest questionnaire, the domestic industry has claimed that imposition of duty would not have any significant impact on the downstream users. In fact, purchasing ECH from the domestic industry at fair prices would lead to a benefit of ₹ 185 crores to the users. On the other hand, the users have claimed that imposition of duty would have an impact of upto 10% on their costs. The Authority notes that the users have themselves admitted that they would pass on any price increases to the downstream users. Therefore, it would not be appropriate to quantify the impact of duties on epoxy resin. The producers of epoxy resin cater to wide variety of downstream industries such as paints, adhesives, laminates, automotive coatings etc., which are further consumed by their downstream users. The domestic industry has contended that any price increase which would be passed on the users would result in negligible impact on the ultimate end-consumers.
140. The Authority notes that prior to the establishment of the plant by the domestic industry, India was completely import-dependent. While Tamilnadu Petroproducts Limited established a plant in the early 2010, the same was shut down due to cheap imports. This is evident from the statements made by the domestic industry in its financial statements. The domestic industry has made significant investments in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant. The domestic industry has emphasized that if the dumping from the subject countries continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations.
141. The other interested parties have argued that the imposition of duties would dissuade investment by foreign producers in the epoxy industry in India. The Authority notes that at present, only Kukdo Chemicals has announced plans to establish a plant for producing epoxy resin in India, in order to feed its downstream plant in India, at an investment of roughly ₹ *** crores. On the other hand, the Indian industry has already invested significant amounts in order to establish plants for ECH. In total, the Indian industry has already invested upwards of ₹ *** crores. Therefore, there is a need to protect such significant investments already undertaken. It is noted that large investments made by Indian producers in India cannot be forsaken in anticipation of future foreign investments.
142. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the upcoming capacity of the domestic industry would more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.

Total Indian Capacity	Epigral Limited	50 KT
	DCM Shriram	51 KT
	Grasim	50 KT
Total demand		90 KT
Excess supply		11 KT

The domestic industry has highlighted that the Indian industry would have sufficient capacity to cater to not only the present but also the future demand in the country.

143. Although the other interested parties have argued that the domestic industry does not have sufficient capacity to cater to the Indian demand, it is seen that the Indian industry as a whole would have sufficient capacity to meet the Indian demand. In any case, countries such as USA, Germany, Taiwan, Japan, Netherlands, Saudi Arabia, France, Italy and Czech Republic have sufficient capacities and the users can import the subject goods from such countries.
144. Some interested parties have claimed that the domestic industry is unable to meet the volume requirements of the users and have submitted communication with the domestic industry in support of the argument. However, the domestic industry has demonstrated that while it offered to sell the subject goods to the users, they refused to purchase the subject goods from the domestic industry as they preferred the cheaper imported goods, which the domestic industry was unable to match.
145. The other interested parties have also claimed that the imposition of duties would negatively impact the upstream producers. The Authority notes that the imposition of anti-dumping duties would allow the domestic industry of ECH to thrive. This would result in an increased demand for the upstream industry, resulting in increased prices. Thus, in no situation would the imposition of duties impact the upstream industry.
146. Lastly, the Authority notes that the anti-dumping duty would be limited to the extent of prices that would

remedy the injury caused to the domestic industry. In such a case, the current price at which the epoxy producers are importing the subject goods from the foreign exporters would remain lower than the price at which the foreign exporters are selling in their home markets. Therefore, even after the imposition of the anti-dumping duty, the prices of ECH in the Indian market would be lower than that in the subject countries. This would allow the epoxy producers in India a competitive advantage, compared to their global counterparts.

K. **POST DISCLOSURE COMMENTS**

147. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 12th July 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L.1. **Submissions by other interested parties**

148. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties.
- i. There are discrepancies in the import volume and profits submitted by the petitioner and those relied on in the disclosure statement.
 - ii. While volume effect has been examined on a yearly basis, price effect has been analyzed on a quarterly basis. Imports have declined from Q1 onwards.
 - iii. There were aberrational price spikes experienced during the period of investigation, making it unrepresentative, which is different from normal market variability.
 - iv. The Authority should consider the overall cost of production of the POI for performing the ordinary course of trade test only for the domestic sales made in the Quarter 2 and Quarter 3 of the period of investigation and not for all sales made during the period of investigation. It is humbly submitted that in the event the Hon'ble Authority finds it inconsistent to apply the overall cost only for the domestic sales made in Quarter 2 and Quarter 3 of the POI, we request to consider the cost of production for the respective quarter only for the purpose of conducting ordinary course of trade test. Even if such sales are disregarded, normal value should be based on cost of production plus 5% as profits.
 - v. There appears to be a discrepancy in the ex-factory export price as submitted by Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Ltd. and that adopted by the Authority.
 - vi. The Authority has selectively analysed the performance of the domestic industry, highlighting parameters where the performance is negatively impacted while ignoring other mitigating factors.
 - vii. Examination of material retardation should not involve a comparison with projected performance.
 - viii. The Authority has not examined the various criteria laid down in the Morocco case to conclude that the domestic industry was materially retarded.
 - ix. The raw material is purchased under fixed contractual agreements and thus, costs of exporters would take some time to reflect change in the prices of product under consideration.
 - x. The domestic industry has admitted in public statements that it is unable to increase sales due to existing long-term contracts.
 - xi. The fluctuations in the international market price should be considered for calculation of non-injurious price. Further, a return of 22% should not be considered.
 - xii. The Authority must calculate quarterly non-injurious price and then compare the weighted average non-injurious price and landed price against the weighted average of total import volume, which would result in a reduced injury margin.
 - xiii. While imposition of duty on subject countries would result in lower prices for ECH, exporters from non-subject countries might negate such advantage by offering competitive prices.
 - xiv. Contrary to observations of Authority, TPL had shut down its operations as its downstream purchaser PAPL ceased operations due to poor performance.
 - xv. The decline in profitability of domestic industry is temporary as supply of bio-glycerin is expected to increase in coming years, resulting in reduced cost for domestic industry.
 - xvi. The performance of the domestic industry has improved significantly in the post-POI period, showing a lack of injury.

- xvii. The domestic industry should provide details of duties and prices paid on imports of crude glycerine and the reason for importing crude glycerin.
- xviii. The users cannot switch their sources due to high production cost in other countries, high transportation costs, long transit period, higher landed cost due to customs duties, and high inventory cost with users to ensure uninterrupted production.
- xix. Imposition of duty would result in trade tensions with China.
- xx. Increased domestic production in less regulated environments could harm sustainability efforts.

L.2 Submissions by the domestic industry

149. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry.
- i. The dumping margin and injury margin determined for non-cooperative exporters from China should be re-quantified at least at the level of non-cooperating from other subject countries, in order to ensure non-participation by such exporters is not rewarded.
 - ii. The manner of determination of raw material cost for the purpose of calculation of non-injurious price may be reconsidered and reviewed.

L.3 Examination by the Authority

150. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations of submissions which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
151. With respect to the submission by the domestic industry concerning the re-quantification of the dumping margin and injury margin for the non-cooperative Chinese exporters, the Authority has determined the margins based on the facts available. It is also noted that the prices of imports from China are also higher than the prices of imports from Thailand and Korea RP. In view of the same, it is reasonable that the dumping margin and injury margin for China would be lower than that for the producers in Thailand and Korea RP.
152. As regards the submission that the raw material cost of the domestic industry to be reconsidered and reviewed for calculation of the non-injurious price, the Authority notes that raw material cost has been determined as per annexure III of the rules.
153. The Authority has obtained and relied upon details of imports from DG Systems, which may show different volumes than that claimed by the applicant. Further, the Designated Authority has relied upon verified information in examining the economic parameters. There is no material change in the economic parameters, as claimed by the applicant, and as considered by the Authority.
154. As regards the contention that the volume of imports has been analysed on a yearly basis while the price effect has been analysed on a quarterly basis, the Authority notes that in order to undertake examination of price effect of imports on the domestic prices, a quarter-wise analysis was undertaken, since the domestic industry was operational only during the period of investigation. On the other hand, the subject imports were entering the country for the entire injury period.
155. With respect to the arguments by AVT regarding the determination of normal value for the exporter, the Authority notes that the sales disregarded for the determination of normal value for the exporter are in consonance with the provisions of Article 2.2.1 of the Agreement. It is noted that the loss-making sales which were disregarded were made over an extended period. Further, Footnote 5 to Article 2.2.1 provides that sales below per unit costs are made in substantial quantities when the authorities establish that the weighted average selling price of the transactions under consideration for the determination of the normal value is below the weighted average per unit costs, or that the volume of sales below per unit costs represents not less than 20 per cent of the volume sold in transactions under consideration for the determination of the normal value. In the present case, the loss-making sales are not less than 20% of the total volume of sales during the quarters. Thus, such sales were not found to be in the ordinary course of trade and were disregarded.
156. Further, the Authority has also examined the contention of the exporter that the overall cost of production of the POI should be considered for performing the ordinary course of trade test only for the domestic sales made in the Quarter 2 and Quarter 3 of the period of investigation and not for all sales made during the period of investigation. The Authority notes that such an approach would be inappropriate being selective in nature.

The Authority further notes that there is a significant decline in raw material cost over the period, with a decline in the prices as well. Therefore, in view of ensuring consistency of approach, the Authority has compared the prices in each quarter, to the cost of the same quarter for all exporters, to examine whether the

sales were made in the ordinary course of trade. The Authority does not find it appropriate to make any modifications to the dumping margin already determined.

157. With regards to the contention that the normal value for Q2 and Q3 for AVT should be calculated based on cost of production plus reasonable profit margin of 5%, it is seen that the exporter has not submitted any reasoning or justification regarding the reasonableness of consideration of 5% profit margin. For determination of the normal value, the Authority has considered the profit earned by the exporter itself in respect of sales of subject merchandise made at the same time period, which cannot be considered unreasonable. In this regard, the Authority notes that the provisions of Section 9A(1)(c) of the Act provide that when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, normal value can be determined on the basis of the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. However, the provisions of Section 9A(1)(c) or the Rules do not define what profit margin shall be considered reasonable in this regard. The Authority notes that in a situation where the volume of profitable sales would have been less than 80%, but higher than 20%, the normal value would have been determined based on the price of profitable sales only, as per the consistent practice of the Authority. The price of profitable sales is essentially the cost of production plus the profit margin on profitable sales. However, simply because the volume of profitable sales is less than 20%, it cannot be considered that the profit margin on profitable sales is no longer an appropriate benchmark for the determination of normal value. Consideration of a benchmark of 5% in such a situation would effectively imply a more favourable treatment to a producer having a lower volume of profitable sales (that is, less than 20% of total volume), as compared to a producer having a higher volume of profitable sales (that is, more than 20% of total volume). The Authority further notes that the exporter has not explained any reason why the profit margin earned on the profitable sales in these two quarters should be considered unreasonable. On the contrary, the Authority notes that the profit margin earned in the remaining quarters of the period of investigation, where normal value has been determined based on selling price was even higher, at ****% in Q1 and ****% in Q4. In view of the higher profit margins earned in the two quarters, where normal value has been determined based on the selling price, it cannot be considered that the profit margin of merely ****% in Q3 and ****% in Q4 are unreasonable.
158. The Authority has considered projections of the domestic industry, after due adjustment for fluctuations in raw material cost. Further, it has been a practice of the Authority to consider and compare the actual performance of the domestic industry with the projected performance in material retardation cases. Such a comparison does not go beyond the scope of examination of the Authority.
159. With regards to the contention that the Authority has only selectively analysed injury parameters, it is noted that the Authority has examined every parameter listed under the provisions of Para (iv) of the Annexure-II to the Anti-dumping Rules in its injury examination. The other interested parties have not identified any specific parameters which have not been analysed in the disclosure statement.
160. With respect to claims that the volume of imports has declined when compared on a quarterly basis, the Authority finds that it is obvious that the volume of imports would be arrested once a new producer enters the market. Further, despite a decline in the imports over certain quarters, the volume of imports during the period of investigation was still higher than the previous year while the landed price of the imports declined. Thus, even though the volume of domestic sales increased, the growth of the domestic industry was retarded due to the presence of a significant volume of imports in the market.
161. With regards to the contention that global market prices are lower than the non-injurious price of the domestic industry which imported refined glycerin at higher cost, it is noted that the exporter from Thailand has also used refined glycerin in its production process, instead of deriving refined glycerin from crude glycerin. Thus, the higher cost of production would also have an equivalent impact on the cost and prices of the exporter. Further, NIP has been determined as per annexure III of the rules.
162. The Authority notes that with respect to the argument concerning the comparison of landed price with cost of production considering utilization of crude glycerine, one of the exporters has claimed that since they procured raw material at high cost under contractual obligations, their cost of production and resultant prices would decline over time and the effect would not be visible immediately. However, on the other hand, the exporter has also claimed that the domestic industry is facing injury due to its procurement of glycerine at high cost, which has resulted in a high cost of production. Therefore, on one hand, while the exporter is citing a business reality, on the other hand, it is claiming the same situation as a poor purchasing decision on the part of the domestic industry, where margin was determined based on comparison of prices. The Authority further notes that the exporter has shown dumping even in Q1 and Q4. Had the prices taken time to reflect the changes in raw material prices, the same would have been true for both, home market and export market. However, the same is not true in the present case.
163. With regards to the claim that a new producer in the market required considerable time to stabilize, the Authority notes that the domestic industry was operating at a high capacity utilization during the first quarter of

its operations. However, subsequently, the capacity utilization of the domestic industry declined which shows that it was forced to curtail operations due to the presence of significant volume of dumped imports and not because of initial operational inefficiencies.

164. With regards to the argument that the domestic industry faced low sales and capacity utilization due to existing contracts and time taken for sampling / quality approvals, the Authority notes that the other interested parties have not submitted any evidence to demonstrate that the poor performance of the domestic industry is due to such other factors.
165. The Authority notes that one of the exporters has claimed that the Authority incorrectly held that Tamilnadu Petroproducts Limited ceased operations due to cheap imports and that such flawed observation casts doubt over the investigation. It is noted that the exporter has not provided any evidence to prove its claim that the previous producer of ECH closed operations for reasons other than cheap imports. On the other hand, the annual reports of Tamilnadu Petroproducts show that the operations for ECH were closed due to presence of cheap imports.
166. With regards to the argument that the projected performance parameters of the domestic industry relied on in the material retardation analysis have not been disclosed, it is noted that such information is confidential in nature and the same cannot be disclosed publicly, to the detriment of the party making the submission.
167. With regards to the claim that the epoxy industry would suffer due to imposition of duties since any advantage offered due to low-priced imports of ECH from subject countries could be negated by exporters in non-subject countries which may offer competitive prices, it is noted that the subject countries in the present investigation are the major exporters of ECH globally. The information provided by the applicant shows that the subject countries have exported ECH at higher prices to third countries as compared to India and no evidence has been submitted to the contrary. Therefore, producers of epoxy in third countries are also obtaining ECH at higher prices. Further, the subject countries are also major exporters of epoxy to India and producers of epoxy in such countries are sourcing ECH at higher prices than the price of exports of ECH to India. This is evident from the fact that the dumping margin has been found positive, which shows that the prices of ECH in the subject countries are higher than the prices at which the same has been exported to India. Since the quantum of duty does not exceed the margin of dumping, even after imposition of duty, the prices of ECH in India would not be higher than that in the subject countries. Thus, the advantage available to the epoxy industry in India is not likely to be negated by exporters in non-subject countries.
168. As regards the claim that that Authority has not examined the criteria laid down by the WTO Panel in Morocco - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, it is noted that the Panel only laid down guidance for the criteria which an investigating authority may consider while examining material retardation. However, the Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established and the Authority is allowed to use any reasonable methodology. Further, the other interested parties have not highlighted any parameters which suggests that the domestic industry was established and thus, did not suffer material retardation.
169. With regards to the claim that the ex-factory export price determined for Jiangsu Ruixiang Chemical Co. Ltd. varied from the information submitted by the exporter, the Authority has revised the export price determined for the exporter. The updated export price and dumping margin have been incorporated in the table hereinabove.
170. With regards to the arguments concerning determination of non-injurious for the domestic industry and consideration of return at 22% for such determination, the Authority notes that the non-injurious price for the domestic industry has been determined based on the established practice of the Authority and the injury margin has been determined accordingly.
171. As regards the argument that imposition of duties would result in increase in trade tensions with China, it is noted that both India and China are members of the WTO and signatories to the GATT and the accompanying agreements, including the Anti-dumping Agreement. Thus, any action undertaken pursuant to the provisions of the Anti-Dumping Agreement cannot be considered as a trigger for any trade tensions.

L. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

172. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes as below.
 - i. The application for initiation of the anti-dumping investigation into imports of Epichlorohydrin ("ECH") originating in or exporter from China PR, Korea RP and Thailand was filed by Epigral Limited (formerly known as Meghmani Finechem Limited).
 - ii. The product under consideration is Epichlorohydrin, which is a colorless liquid with purities greater than 99%. It is majorly used to make epoxy resins and is also used in pharmaceutical APO, water

- treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants, adhesives, elastomers, plastics and rubbers and as a strength additive in papers.
- iii. The applicant has produced like article to the imported product under consideration.
 - iv. The applicant is the sole producer of the like article in the country and commenced commercial production during the period of investigation. The applicant set up a new manufacturing plant for the subject goods and its operations were not stabilized during the period of investigation. Thus, the applicant constitutes an establishing industry, and is the domestic industry for the purpose of Rule 2(b) of the Rules.
 - v. Two other producers, DCM Shriram Limited and Grasim Limited, are in the process of setting up production capacities for the subject goods.
 - vi. The producers in the subject countries are dumping the product under consideration into the Indian market.
 - vii. The demand for the subject goods increased over the injury period.
 - viii. The volume of imports increased over the injury period and were the highest during the period of investigation, despite the commencement of production by the domestic industry. The imports accounted for 94% of the total imports into the country and were higher than the demand-supply gap.
 - ix. India is the largest export market for the exporters in Thailand and was the second largest export market for exporters in China PR and Korea RP, which shows that India is a key market for the exporters in the subject countries.
 - x. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry in each quarter of the period of investigation. In fact, the subject imports were priced even below the projected selling price of the domestic industry, which restricted the domestic industry from reaching its target price.
 - xi. The imports have depressed the prices of the domestic industry.
 - xii. The landed price of the imports was even lower than the raw material cost, with the mark-up of the export price over the raw material cost reducing in the second half of the period of investigation when the domestic industry commenced production.
 - xiii. The domestic industry was unable to recover its variable cost which resulted in a negative contribution during part of the period of investigation.
 - xiv. As regards the effects of the dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the subject imports caused material retardation to the establishment of a new industry in India. The following are relevant in this regard –
 - a. While the domestic industry achieved high capacity utilization in Q1, its capacity utilization declined and almost three-fourths of its capacity remained idle.
 - b. The production and domestic sales of the domestic industry remained significantly low and below the projected production and sales.
 - c. Since the domestic industry was unable to dispose of its production, it was forced to shut down its plant for 50% of its total operational period during the period of investigation.
 - d. The domestic industry was able to cater to a minor share of 4% in the total despite having significant idle capacity while the imports accounted for 90% of the market share.
 - e. As a result, the domestic industry faced piling up of inventories, which were equal to almost half of their production and equal to 128% of the domestic sales. Further, the inventories in hand exceeded monthly sales in each month of operation.
 - f. The profitability of the domestic industry declined throughout the period of investigation and it suffered huge losses and cash losses. Further, the domestic industry earned negative returns on its investment since Q2. This is in contrast to the profits projected by the domestic industry.
 - g. Further, the domestic industry would have suffered significant losses even if it operated at 80% utilization at current prices.
 - h. While the volume parameters of the domestic industry improved, its profitability parameters declined in each quarter.
 - i. Due to the significant losses suffered and the negative return earned, the subject imports adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments.

- xv. Considering the above, it is clear that the domestic industry has suffered material retardation to its establishment due to the dumped imports.
- xvi. A comparison of the landed price of subject imports with the non-injurious price determined by the Authority shows that the injury margin is significant and positive for all responding exporters, barring one.
- xvii. The investigation has not shown any other factor, which could have caused injury to the domestic industry.
- xviii. The anti-dumping duty in the larger public interest as is evident from the following—
- The Indian industry has made major investments in order to manufacture the subject goods to make Indian self-reliant.
 - There is a need to protect significant investments undertaken by the Indian industry.
 - Imposition of duty would not have any adverse impact on the downstream users.
 - Imposition of duties would be advantageous for the users as the increase in import price post imposition of duties would still be lower than the normal value in the domestic market of the subject countries.
 - A producer of ECH was already forced to shut down operations in the past due to cheap imports.
 - Once the other Indian producers commence production, there would be no demand-supply gap in the country for the subject goods.
 - The subject goods can be imported from other countries as well at competitive prices.
 - The presence of three producers in the market would ensure that a monopoly is not created in the industry.
 - Imposition of duties would lead to conservation of foreign exchange in the country.
173. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
174. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

Duty table

S. N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2910 30 00	Epichlorohydrin	Thailand	Thailand	AGC Vinythai Public Company Limited (AVT) (Formerly known as Advanced Biochemicals (Thailand) Co., Ltd.)	298	MT	USD

2	-do-	-do-	Thailand	Any country, including Thailand	Any producer other than (1)	327	MT	USD
3	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	Thailand	Any	327	MT	USD
4	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	274	MT	USD
5	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Lotte Fine Chemical Co. Ltd.	506	MT	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country, including Korea RP	Any producer other than (4) and (5)	557	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	Korea RP	Any	557	MT	USD
8	-do-	-do-	China PR	China PR	Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd	108	MT	USD
9	-do-	-do-	China PR	China PR	Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd.	Nil	MT	USD
10	-do-	-do-	China PR	Any country, including China PR	Any producer other than (8) and (9)	216	MT	USD
11	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	China PR	Any	216	MT	USD

M. **FURTHER PROCEDURE**

175. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority